यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम और आसानी से जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर पायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The question is:

That the Bill to amend the Food Safety and Standards Act, 2006 be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, I beg to move;

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE BUDGET (GENERAL) 2008-2009

GENERAL DISCUSSION

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे गहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम जब बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक विचित्र स्थिति में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं। आज हम वहां देखते हैं कि वहां बहुत मंदी का दौर चल रहा है और वहां चुनाव भी हो रहे हैं। हम भी विश्व अर्थ-व्यवस्था से जुड़े हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे रोजगार पर पड़ता है। आज विश्व में खाद्यान्न की कमी हो रही है और अन्न के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल को मूल्य 109 डालर प्रति बैरल हो गया है। हमारे पड़ोस में भी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरताएं हैं, चीन में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, डालर कमजोर हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन से हमारी खेती और औद्योगिक व्यवस्थाओं पर भी दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। उसकी चिंताएं और उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। मुझे पता नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ऊर्जा के संबंध में समझौता हो रहा है, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, वह होगा, नहीं होगा और उससे किस प्रकार की हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में अस्थिरताएं आएंगी, राजनीति के क्षेत्र में अस्थिरताएं आएंगी, मैं नहीं कह सकता। फिर जिस प्रकार से भारत में निवेश हो रहा है उसके क्या परिणाम होंगे और उससे हमारी अर्थव्यवस्था में क्या गिरावट आएगी या कोइ सुधार होगा। आज हमने अखबारों में देखा है कि हमारे औद्योगिक विकास की दर 2007-08 में हमारी अपेक्षाओं के विपरीत बहुत घट गई है। हम यह जानना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं का यह बजट किस प्रकार से निराकरण करेगा। बजट का मतलब क्या है? क्या बजट सिर्फ आय और व्यय का आंकड़ा है और उसमें कुछ फेर-बदलकर के एक हिसाब-किताब पेश कर दिया जाए, इतना ही है या बजट देश में किसी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की भी दिशा देता है, लंबी दिशा देता है, छोटी दिशा देता है, वह किस तरफ ले जाना चाहता है।

महोदय, मेरे सामने भारत का संविधान है। इसके प्रियम्बल में उद्देशिका में लिखा है कि इसमें हम समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय प्रदान करेंगे और इसमें हम अवसर की समानता और समता भी देंगे और यह भी कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी बढ़ाएंगे। यह संविधान की उद्देशिका में लिखा है। हम यह जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या बजट इन उद्देश्यों को पूरा करता

है। क्या इस भावना को जिसके आधार पर यह गणतंत्र बना है, इस बजट के अंदर कोई स्थान दिया गया है या बजट उस तरफ कोई कोशिश कर रहा है। हम इन सब बातों पर अगर गहराई से विचार करें, तो हमें पता लगता है कि यह बजट, मैं धीरे-धीरे आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा, किन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, बल्कि इस देश में आम आदमी के लिए एक बहुत भयावह जिंदगी का श्रीगणेश करता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे प्रधान मंत्री ने, अपने भाषण में जब वह राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें कही जो सत्य के केन्द्र से बहुत दूर थीं। मैं नहीं समझता कि किसी प्रधान मंत्री को इस प्रकार से सत्य के केन्द्र से दूर रहना चाहिए, *far away from the centre of truth.* इतनी दूर तक जाना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार मैंने देखा है। अब कहा गया कि यह सरकार और कुछ नहीं कर रही है, बल्कि इसकी नीतियां वे हैं, जो हम कूड़ा-करकट छोड़कर गए थे, यह सरकार उसको साफ कर रही है। Prime Minister launched a scathing attack on NDA in Parliament on March 5 for leaving behind the problems such as indebted farmers and rising prices. उन्होंने कहा था "What we have done is nothing more than picking up the unpaid distress bill which the NDA Government left behind. "यह जो बात उन्होंने कही है, मुझे नहीं लगता कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो 2003-2004 का यहां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, इकोनोमिक रिव्यू, वे उसको शायद भूल गए। उसकी शुरुआत ही कहती है कि The economy appears to be in a resilient mode in terms of growth, inflation, and balance of payment, a combination that offers much scope for consolidation of the growth momentum with continued macro economic stability.

फिर वे इसके आगे यह भी कहते हैं.---"The real Gross Domestic Product is estimated to have grown by 8.1 per cent in 2003-2004 buoyed by a strong agricultural recovery of 9.1" यह तो वे एग्रीकल्चर रिकवरी के बारे में कह रहे हैं। आगे वे यह भी कहते हैं कि "The economy has enjoyed the benefits of a relatively low inflation with comfortable stocks of food grains, an enhanced competition in product market and an appropriate mix of fiscal and monetary policy. "यह सब बात कहने के बाद जब प्रधान मंत्री जी और उनसे मिलती-जुलती आवाज में वित्त मंत्री जी यह आरोप लगाते हैं कि एन्डीए सरकार बहुत कुछ ऐसा छोड़ गई और एक डिस्ट्रेस में किसान और खेती को छोड़ गई, देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल कर गई, वे इसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के किसी वक्तव्य की हमें उनसे अपेक्षा करनी चाहिए था उनका यह वक्तव्य किसी प्रकार के तथ्यों से मेल खाता है। आगे भी हमने देखा कि उन्होंने Outlook 2004 में उन्हें क्या मिलेगा, वे क्या कुछ समझते हैं, इस पर भी उन्होंने कहा है" Broad objectives and parameters of the monetary and credit policy for 2003 and 2004 have been met, and overall assessment of the developments during 2003 and 2004, and prospects for 2004-05 provide grounds for optimism." इसमें से पेसिमिज्म कहां आ गया? इसमें डिस्ट्रेस कहां आ गया? मैं मानता हूं कि आम तौर पर लोगों की स्मरण शक्ति कम होती है, मगर इतनी भी कम नहीं होती कि तीन-चार साल में ही भूल जाएं। खास तौर पर वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी की स्मरण शक्ति तो इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आजकल बहुत सारे टॉनिक्स आ रहे हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि उनमें से कुछ टॉनिक्स का प्रयोग करें और अपनी स्मरण शक्ति को ठीक करें। मेमोरी प्लस हो सकता है। प्राइसेस एण्ड फूड मैनेजमेंट के चैप्टर में वे कहते हैं, "The double-digit annual average inflation rate of 10.6 per cent between 1991-92 and 1995-96 came down to 4.2 per cent, between 2001-02 and 2003-04. The structural decline in inflation has also narrowed the difference with inflation in developed economies." फूड एण्ड मैनेजमेंट में फिर आगे कहते हैं" "in the last two years, food stocks have been used as a principle resource for poverty alleviation programmes under the various welfare schemes. "यानी एन्डीए सरकार ने जो अन्न था उसका सदुपयोग किया, लोगों की गरीबी और भूख दूर करने के लिए किया। "The mid-day meal scheme संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना are the two major welfare schemes that absorbed a substantial off-take of food grains. "फिर कहते हैं "In the longer run, with resources currently being spent on holding stocks, it should be possible to eliminate hunger, make a significant dent on the current appalling levels of malnutrition among India's children and augment the quality of human resources. "यह परफोर्मेन्स तो हमारी 2003-04 की इनके शासन में आने से पहले थी और शासन में आने के छह, सात, आठ हफ्ते बाद इन्होंने यह इकॉनोमिक

रिव्यू देश की अर्थव्यवस्था पर पेश किया है, इन्हें कब याद आ गया कि हम डेब्री, डिस्ट्रेस और कूड़ा कर्कट छोड़कर गए हैं। क्या यह कूड़ा-कर्कट है? फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि इन्होंने अनाज बाहर भेज दिया। यहां सर प्लस था और भारत को एक विदेशी बाजार में अन्न के मामले में हमने एक स्थापित शक्ति के तौर पर बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित किया था। "India exported over 20 million tonnes of food grains during the last two and half years and emerged as one of the leading exporters of food grains in the world grain market." फिर आप कहते हैं, The subsidy incurred on exports is estimated to be much lower than the expenditure that would have been incurred on carrying these foodgrains had they not been exported.' हमारे उस निर्यात को, जिसकी आज आप बहुत अधिक निन्दा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, उसके बारे में तो आपके यही शब्द हैं। 'There is a need for establishing India as a reliable exporter of foodgrains to get a profitable outlet for channelizing the country's surplus foodgrains.' हम surplus foodgrains वाले थे, आज आप deficit foodgrains वाले हैं। आज भाव बढ़ा है और अभाव भी बढ़ा है। भाव भी बढ़ा और अभाव भी बढ़ा और आप हमको यह बात कह रहे हैं। मैं यह नहीं समझता कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधान मंत्री जी या माननीय वित्त मंत्री जी को करना चाहिए। सरकार बदलती है, नीतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस प्रकार से तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना और उनके विपरीत ऐसा वातावरण पैदा करना कि जैसे पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं था और जो किया, उसको नकारना, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है।

फिर फूड मैनेजमेंट के लिए आप कहते हैं, 'The comfortable supply situation and remarkable price stability in respect of foodgrains in different parts of the country, despite 2002 poor monsoon have demonstrated relevance of our food security system, notwithstanding the recent debate about its utility in the context of ongoing liberalisation, etc. फिर आप आगे कहते हैं, 'Thus, there has to be restraint in hiking the MSP of foodgrains till it equals the C-II cost of production of the least cost of that strain.' हमको कहा जाता है कि हमने MSP बढ़ाया ही नहीं। आप MSP बढ़ा रहे हैं और खुद आप कह रहे हैं कि 'There is a need to restrain it.'

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): That is a fact.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Then, why are you criticising us? आप उल्टी बात क्यों कहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जब तक Cost के बारे में यह स्थिति नहीं आएगी, तब तक MSP नहीं बढ़ानी चाहिए। आप बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के बाद क्रेडिट ले रहे हैं और हमको गाली दे रहे हैं। यह क्या बात है? आप कहिए कि आपने चुनाव की वजह से दाम बढ़ाए हैं, आप कहिए कि आप इस सारे बजट का चुनाव के लिए फायदा उठाना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति में होता है। आप कह रहे हैं, तो खुल कर कहिए कि चुनावी बजट है। फिर आप इसको विकास का बजट क्यों कहते हैं? Growth in agriculture: Agriculture and Allied Sectors of value added registered a growth rate of 9.1 per cent in 2003-04, reflecting the growth in physical production and remunerative prices of agricultural goods, the growth rate of this sector for 2003-04 was one of the highest in the recent years is only marginally lower than the previous high of 9.6 per cent achieved in 1996-97.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Joshiji, if you pardon me, for 2003-04 agriculture growth, please refer to 2002-03.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Yes, yes. I know. लेकिन आप तो यह नहीं कह सकते कि ग्रोथ नहीं हुआ।

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am only requesting you.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am also requesting you and informing you what you have said.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You please refer the growth of 2002-03 and then 2003-04 make sense.

3137RS—14

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That is right. You, yourself have said, 'because of a bad monsoon.'

Sir, the total credit flow to agriculture in the IX Plan amounted to Rs. 2,29,956 crores which is projected now a substantial jump in the credit flow to agriculture. In the X Plan, it is projected at Rs. 7,36,570 crores, which is almost three times than the IX Plan achievement. This was in the X Plan which was mostly executed in our time. Then, if you look at the table with regard to institutional credit to agriculture from Rs. 31,956 crores in 1997-98, it became Rs. 80,000 in 2003-04-consistently rising. Even if you see the Kisan Credit Cards, the total number of Kisan Credit Cards issued were 4,39,079 and the amount sanctioned was Rs. 9,77,010 crores. आप यह कैसे कह सकते हैं कि रूरल क्रेडिट नहीं दिया गया! इस किसान क्रेडिट कार्ड में phenomenal progress हुई है। आपने खुद इसकी तारीफ की है कि किसान क्रेडिट कार्ड कितनी popular थी, कितनी लोकप्रिय थी। इस किसान क्रेडिट कार्ड के होते हुए, तमाम क्रेडिट फंड्स के होते हुए, कृषि में विकास होते हुए, फूडग्रेंस का सदुपयोग होते हुए, लोगों की भूख मिटाते हुए आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और जो कुछ किया, वह अब आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप और अच्छा करें, हमसे बेहतर करके दिखाएँ, हमें खुशी होगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अपने जमाने में हम बिलो पावर्टी लाइन्स के लिए प्रति परिवार 35 किलो ग्राम सस्ते से सस्ता अनाज दे रहे थे। बहुत बड़ी मात्रा में हमने यह अनाज वितरित किया और बरसों तक वितरित किया। उसी की वजह से देश में लोग अपनी भूख से छुटकारा पा सके। गरीब आदमियों को हमने राहत दी, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि आप अनाज का आयात कीजिए। इस तरह तो आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। खाद्य के लिए आप राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि आप अनाज का, खाद्य का आयात कीजिए। यह क्या बात हो रही है? आप सीधे राज्य सरकार को यह कर रहे हैं कि आप बाजार से ले आइए, लेकिन इससे किस प्रकार से बाजार भाव बढ़ेंगे और किस प्रकार से बाजार में अव्यवस्था आएगी, बिना इसका ध्यान किए हुए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सरकार लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सरकार गरीब आदमियों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन्स सिस्टम के माध्यम से सस्ता अनाज देने की जिम्मेदारी से बचना चाहती है और धीरे-धीरे राज्यों को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ने के लिए और उससे प्रभावित होने के लिए मजबूर करना चाहती है। मैं यह समझता हूं कि यह अच्छी नीति नहीं है और अगर हम इस देश में अनाज के आयात करने की नीति शुरू करते हैं, तो यह देश की खेती के लिए बहुत खतरनाक नीति होगी।

श्रीमन्, यह आयात की नीति बड़ी खतरनाक है। इसने दुनिया के बहुत से देशों को परेशान किया है। आपको यह मालूम ही होगा और आगे मैं बताऊंगा भी कि आज अनाज की कीमतें दुनिया में किस तरह से बढ़ रही हैं।

आगे कहा गया कि किसान की ऋण माफी कर दी जाए और शायद यह बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह तो अंग्रेज भी कर देता था। वह भी लगान माफी कर देता था, थोड़ा बहुत कर्जा भी माफ कर देता था। वह कर्जा उस समय महाजनों का कर्जा होता था, उस समय वह शेड्यूल्ड बैंक्स का कर्जा नहीं होता था। चौधरी देवी लाल जी ने भी एक बार किसानों का 10,000 रुपये का कर्जा माफ करने की बात की थी, लेकिन तब आप लोगों ने कितना हल्ला मचाया था कि क्या कर दिया, खजाना लुटा दिया, लेकिन आज आप 60,000 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। उसकी वास्तविकता क्या है, वह भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस विदर्भ की दुर्दशा के कारण यह स्कीम सोची गई, वहां के किसानों के कुल कर्जे का 2/3 से 3/4 तक महाजनी कर्जा है, जो निजी क्षेत्र का है। फिर विदर्भ के किसानों को इससे क्या मिलेगा? श्री मुतेमवार ने सरकार को पत्र लिखा है कि इस कर्जा माफी का कोई भी फायदा कर्नाटक के छोटे किसानों को नहीं मिलेगा।

विदर्भ में 3 हैक्टेयर से अधिक की औसत जोतें हैं, लेकिन कर्ज माफी की सीमा 2 हैक्टेयर से कम है। चूंकि वहा जमीन की उपज कम है और वह असिंचित है, इसलिए उनकी होल्डिंग्स बड़ी हैं। फिर 31 मार्च 2007 तक का कर्जा माफ किया गया है, उसके बाद का नहीं किया गया। यह बात सारी दुनिया जानती है कि गन्ने वाले लोग दिसम्बर-जनवरी से मार्च के दौरान कर्जा लेते हैं, रुई वाले लोग अप्रैल से लेकर मई-जून के दौरान कर्जा लेते हैं, तो अगर आपने 31 मार्च, 2007 तक का कर्जा माफ किया है, तो वैसे ही वह विदर्भ वालों को नहीं मिलेगा और उस एक साल की कर्जा माफी से तो बिल्कुल ही वंचित हो जाएंगे। यह आप क्या कर रहे हैं?

पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर जोतें दो हैक्टेयर से कम हैं और वे बहुत उपजाऊ भी हैं। वहां का किसान ज्यादा समृद्ध है। गन्ना पैदा करता है। यह कृषि मंत्री शरद पवार जी का क्षेत्र है। वहां अंगूर पैदा होता है और उसमें उन्हें 80 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलता है। लेकिन यह जो बेचारा रुई पैदा करने वाला किसान है, उसको 4 हजार रुपया प्रति एकड़ कर्जा मिलता है। इस तरह एक तरफ तो उसने कर्जा ज्यादा लिया, इसलिए उसकी माफी भी ज्यादा हुई, दूसरी तरफ इसको कर्जा भी कम मिला और इसकी माफी भी नहीं हुई और यह मर भी रहा है। आत्महत्याएं विदर्भ में ज्यादा हो रही हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में नहीं।

आप इसे देखें, यह क्या हो रहा है? क्या यह मजाक हो रहा है कि आप गरीब किसान को वंचित कर रहे हैं और अमीर किसान को मालामाल कर रहे हैं? इसे मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा।

आप एक बात और भी देखें कि सारे कर्जे का 1/6% यानी 9,360 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के हिस्से में आता है और इसका अधिकांश हिस्सा पश्चिमी महाराष्ट्र को मिलता है। फिर सवाल यह है कि विदर्भ को क्या मिला? इसका जवाब आपको देना है और समझाना है कि आप किसका कर्जा माफ कर रहे हैं? सारे देश में, जहां बारानी खेती है, जहां असिंचित भूमि है, वहां लोगों के पास जोत 10 एकड़, 8 एकड़, 9 एकड़, 12 एकड़ और 5 हैक्टेयर तक है, लेकिन उनकी उपज बहुत कम है। बुंदेलखंड में बहुत से लोगों के पास आपको 10, 12 या 15 एकड़ जमीन मिलेगी, लेकिन वह बारानी है, वह असिंचित है और उसको उपज बहुत कम है, किन्तु उनका कर्जा माफ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास 2 हैक्टेयर जमीन है और उसमें एक कैश क्रॉप होती है, जैसे अंगूर होता है, उसमें गन्ना होता है या तम्बाकू होता है, तो आप उसे माफ कर देंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप उनको माफ कीजिए, लेकिन जिसको भी जरूरत है, उसे भी माफ कीजिए। जिसको जरूरत है, उसको आप माफ नहीं कर रहे हैं, यह मेरा आरोप है। मैं किसानों के कर्जे को माफ करने के पूरे हक में हूं, लेकिन उस को माफ करने का कोई rational होना चाहिए, उसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए। आज इस देश में एक हेक्टयर से कम जोत वाले 72 लाख किसान हैं। इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की "हैंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2006-07" के अनुसार 20,499 करोड़ रुपए का कर्ज है और उन किसानों पर जो एक से दो हेक्टेयर की जोत रखते हैं, उनके 59 लाख खाते हैं, उन पर 20,758 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस तरह कुल 41,257 करोड़ रुपए का कर्ज हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इसे हमने माफ कर दिया। अभी इसके अन्दर जो महाजनी क्षेत्र से ऋण लिया गया है, उसका जिक्र नहीं है। इसलिए आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। आप हर साल कॉपोरेट सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए की छूट देते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में आपने कितने हजार करोड़ रुपए लुटा दिये? उद्योगों को आप कितनी टैक्स-राहतें हर साल दे रहे हैं? आई॰ टी॰ सेक्टर को कितनी छूट दी गई है, एस॰ ई॰ जेड॰ में कितनी छूट और लूट मची हुई है? ये सवाल हैं, जब आप कहते हैं कि हमने किसानों को दिया। अव्वल तो दिया कहां से, आप बताएंगे और इन लोगों को आप देते आ रहे हैं, हर साल देते आ रहे हैं, हर सरकार दे रही है, हमारी सरकार ने भी दिया था, यह एक विचित्र बात है कि इस छूट का कोई जिक्र ही नहीं करता। 30-40 हजार करोड़ रुपए की छूट हर साल दी जा रही है, कभी बैंकों की तरफ से और कभी सरकार की तरफ से। एक तमाशा और है कि जिनके खेत 2 हेक्टेयर से अधिक हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमैंट है, यानी 75 परसेंट ऋण आपको देना होगा और 25 परसेंट की आपको छूट मिलेगी। अगर 75 परसेंट मैं दे सकता हूं, तो 100 परसेंट भी दे सकता हूं। क्या तमाशा की स्कीम बनाई है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को भुलं में रखने के लिए, लोगों को भ्रम में रखने के लिए! फिर यह स्कीम इसी साल क्या आई? क्योंकि, यह चुनाव का साल है। जरूरत तो इसकी 2-3 सालों से महसूस हो रही थी, आवाजें उठ रही थीं, आत्महत्याएं हो रही थीं, तब सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। 'इस साल और अक्टूबर तक हम इसे पूरा करेंगे और झटपट पूरा करेंगे', यह क्यों किया जा रहा है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री यह बताएंगे कि किस राज्य में किसानों ने कॉमर्शियल, सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों से, सहकारी बैंकों से और महाजनों से कितना कर्जा लिया है? अगर इसकी संख्या उनके पास है, तो वह बताएं और उनके जोत की संख्या क्या है, वहां एवरेज जोत क्या है, जिस पर कर्जा है तथा उनमें से कितने किसानों को राहत मिली है? वह यह भी बताएं कि देश भर में कितने किसानों ने किस प्रकार के बैंक से ऋण लिये और उसका भुगतान न कर पाने के कारण आत्महत्याएं कीं और महाजनों से ऋण लेने के कारण से कितने किसानों ने आत्महत्याएं कीं। क्या वित्त मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उनके बैंक और महाजन कर्जा वसूल करने के लिए बाहुबलियों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हाल में अखबारों में आपने चित्र देखें होंगे कि एक महाजन ने बाहुबलियों का उपयोग कर के लोगों को घर से घसीट कर बाहर

निकाला। इसके बाद उस व्यक्ति ने बाहर जाकर जब गुहार मचाई और गांव के लोग वहां आए, तब कहीं जाकर वह छूट पाया। क्या आप इसको रोकेंगे? क्या इसमें इसकी कोई व्यवस्था है और क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे किसानों को ऋण लेने की जरूरत न पड़े?

यह कोई स्थाई सोल्यूशन नहीं है। आप खेती को लाभकारी कैसे बनाएंगे? आप सरकारी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग नियुक्त करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। हम उसके हक़ में है। आप इन्फ्लेशन के साथ, मुद्रा-विस्तार के साथ उनके वेतन को नियोजित करते हैं, डी॰ ए॰ देते हैं। आप किसान के साथ क्या करते हैं? क्या उसकी कोई सुनिश्चित आय है? क्या आप यह कह सकते हैं कि एक निश्चित जोत के किसान को कम-से-कम सरकार के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी के बराबर आमदनी सुनिश्चित होगी? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह काम भी करे, उसके बाद भूखा भी रहे और फिर आत्महत्या भी करे, जबकि यहां संगठित क्षेत्र के लोग और बाकी काम भी कम करें, खाना भी ज्यादा खाएं और फिर उसके बाद सिर्फ बहुत अफसोस के साथ यह कहें कि:

भूख है रोटी नहीं, गरीबी है तो क्या हुआ।

आजकल ज़ेरे बहस वित्त मंत्रालय में है यह मुद्दा।।

फिर उसके बाद आप यह कहें कि हम अभी बहस कर रहे हैं, देखेंगे, आगे बताएंगे और किसान से कहें कि तुम काम करते रहो, तुम आत्म-हत्या करते रहो। आप अब किसान के सब्र का और ज्यादा इम्तहान न लीजिए। मैं सदन के माध्यम से विन मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और देश की जनता को सावधान करना चाहता हूं कि अगर खेती की हालत यही रही, अगर किसानों की आमदनी लाभकारी नहीं की गयी तो देश एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। उसके कितने दुष्परिणाम होंगे, इस से मैं सावधान करना चाहता हूं। इस मामले को आसानी से न लीजिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, "Everything can wait, but not agriculture." हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बजट-दर-बजट आप देखें, प्लान-दर-प्लान आप देखें कि हमने किस प्रकार से खेती की उपेक्षा की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अमेरिका के फूड सेक्रेटरी के उस वचन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि "Food is a wapon in our bargaining kitty." हमारे पास अन्न एक ऐसा हथियार है जिससे हम राजनीतिक bargaining कर सकते हैं। आज हमारे पास अन्न कम है। आज हमारी खाद्य सुरक्षा की हालत बहुत खतरनाक है। आप उसे देखें कि हमारी क्या खपत है और क्या हालत है? आज के समाचार पत्रों में निकला है कि, 'Estimated yearly consumption of all foodgrains": North America-909 kilogram per capita; EU 552; Sub-Saharan Africa-162; Indian Subcontinent-179.' यह below the 'famine trap' है। सन् 1862 या 1864 में अंग्रेजों ने कहा था कि 200 किलोग्राम पर केपिटा, per year से अगर availability घटती है तो आप 'famine trap' में हैं। आप 179 दे रहे हैं और आज से 15 साल पहले भी मात्रा यही थी। महोदय, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन उसके अनुपात में food availability नहीं बढ़ी है और पशुओं के चारे का तो इस में जिक्र ही नहीं है। आज उनकी हालत भी बहुत खराब है। महोदया, वह कहते हैं, 'where do we go from here?' क्योंकि इसके बाद दाम बहुत बढ़ रहे हैं। अनाज घट रहा है। वह बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए कि वर्ष 2001-2002 में wheat production 581.1 था और consumption 584.4 था और आज 2007-2008 में production 600.5 है और consumption 612.2 है। इसलिए अनाज के वर्ल्ड प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। यह wheat की हालत है। यही हालत rice की है, यही हालत corns की है। अमेरिका चिंतित है, यूरोप चिंतित है, क्योंकि corn price बढ़ रही है। वह लोग कहते हैं कि आप उसका उपयोग ethanol में कर रहे हैं। तो प्रश्न किया गया, 'Where do we go from here? Think of prices as barometers of anxiety levels for users. And what would be the impact on India? Experts say, there is only one way to come out of the mess. It is expansion of foodgrain production, and the expansion must come fast. पर यहां तो expansion of suicide हो रहा है, यहां expansion of agricultural production नहीं हो रहा है। आप जिस तरह की नीतियां ला रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत चिंता है। मैं जब कभी अखबारों में देखता हूं 'Living off the ground' 'Rising food prices compel the poor and the healthy to eat cookies made of mud' हेथी, कैरेबियन लोग मिट्टी से बिस्किट बनाकर खा रहे हैं क्योंकि अनाज नहीं मिल रहा है और प्राइस उनकी purchasing power से बाहर चली गयी है। वह कहते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, अपने लोगों को नहीं दे सकते और यह हाल हेथी का ही नहीं है।

महोदय, आज 40 देशों में अनाज पैदा नहीं किया जाता है। वे लोग अनाज के इम्पोर्ट पर निर्भर करते हैं। अब उन का क्या हाल होगा? किसी भी दिन उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रताएं, सार्वभौमिक स्वतंत्रताएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इस मामले में देश को धोखा न दें, आप देश को गुमराह न करें। मैं सभी पार्टियों से और सदन से भी यह अपील करता हूं कि खाद्य सुरक्षा को ठीक रखने के लिए, किसानों की हालत ठीक रखने के लिए, देश की 70 प्रतिशत आबादी को ठीक रखने के लिए गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। एक राय बनाकर एक नीति का पालन करना चाहिए और यह अमरीकन मॉडल जो खेती का है कॉर्पोरेटाइजेशन का, इससे हमको छुट्टी मिलनी चाहिए। मुझे इस बात को कहने में कोई दुख नहीं है कि यह सरकार खेती, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन खेती, एग्री बिजनेस की खेती, विदेशी बीज और पेस्टिसाइड के ऊपर निर्भर खेती कराना चाहती है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक होगी। इस मामले में मैं सारे सदन से यह अपील करूंगा कि वह बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार करे और हिंदुस्तान की खेती को इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के जाल से मुक्त कराए, क्योंकि जो भारतीय बीज हैं, जो इस देश की प्रकृति के अनुसार हैं, उनसे खेती कराने का प्रयास किया जाएगा, तो शायद पांच-सात साल में यह हालत सुधर सकती है। इसमें गंभीर प्रयास की जरूरत है, ऐसी खेती में से ज्यादा लोगों को निकालकर बाहर ले जाने की जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में इस तरफ कोई चिंता नहीं की गई है। पिछले चार-पांच साल के बजट अगर आप इस सरकार के देख लें, तो इनमें किसान के बारे में, देश की खेती के बारे में उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। इसी का नतीजा है कि भारी पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मुझे यह भी याद आता है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि तीन चीजें बहुत जरूरी हैं-एक तो ग्रोथ बढ़नी चाहिए, दूसरा इनफ्लेशन यानी मुद्रास्फिति को घटना चाहिए और तीसरा, निवेश, इन तीनों के बीच संतुलन रहना चाहिएं इन्वेस्टमेंट, इनफ्लेशन, ग्रोथ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों मामलों में यह बजट बिल्कुल असफल रहा है और देश की स्थिति पर इसमें कोई गौर नहीं किया गया है। अभी आज ही के दिन समाचार-पत्रों में है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी में जनवरी, 2008 में गिरावट आ गई, यह जनवरी, 2007 के 11.6 परसेंट से गिरकर 2008 में 5.3 परसेंट हो गई। यह घटने की दर अगस्त, 2007 से शुरू हुई और जनवरी तक गिरती ही चली गई। आज के अखबारों में इसके आंकड़े दिए हुए हैं कि अगस्त में जो आईआईपी की वृद्धि दर 10.7 थी 2007-08 में और 2006-07 में 10.3 थी, उसके बाद यह घटनी शुरू हो गई। सितबंर में आईआईपी की वृद्धि दर 6.4 रही, जबकि 06-07 में यह 12 प्रतिशत थी। इसी तरह से आप देखेंगे, अक्तूबर में कुछ बढ़ी, लेकिन नवंबर में फिर घट गई यह 06-07 नवंबर में 15.8 परसेंट थी और इस साल 5.3 हो गई। फिर 06-07 दिसंबर में 13.4 थी, जो घट कर दिसंबर में 7.6 हो गई, फिर जनवरी में 06-07 में आईपीपी की दर 11.6 थी, जो जनवरी में घटकर 5.3 हो गई। इसमें देखने की बात यह है कि बिजली की दर 8.3 से घटकर 3.3 आ गई। यह भी देखने की बात है कि उपभोक्ता वस्तुओं की ही वृद्धि हुई है। कन्ज्यूमर्स, ये कौन से कंज्यूमर्स हैं, ये फैशन के कन्ज्यूमर्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, कॉसमैटिक्स हैं, पावडर हैं, क्रीम है, साबुन है, इस तरह की चीज हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, इन उपभोक्ता वस्तुओं में जरूर वृद्धि हुई, लेकिन जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं, ड्यूरेबल कन्ज्यूमर्स हैं, वे भारी पैमाने पर घट गए। वर्ष 2006-07 में इनकी रेट 5.3 थी, जो अब घटकर माइन्स 3.1 हो गई, लेकिन गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पूंजीगत, कैपिटल गुड्स में तो भारी कमी हुई है, जो 16.3 से घटकर 2.1 हो गई है। यह इस बात का सबूत है कि इस देश में ग्रोथ घट रही है और जो यह कहा जा रहा था कि हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, मुझे लग रहा है कि वह शायद अब नहीं बढ़ सकती, शायद इस साल 2008-09 में वह 6 परसेंट पर आकर लटक जाए, क्योंकि उसके बारे में तरह-तरह के लोग तरह-तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कोई कहता है कि यह 7 परसेंट होगी, कोई कहता है कि यह 7.5 परसेंट होगी, कोई कहता है कि यह 8 परसेंट होगी और कोई कहता है कि यह 6 परसेंट होगी। इसके बारे में भी लोगों में आशंका हो गई है कि ग्रोथ की दर क्या अगर 9 परसेंट ग्रोथ की दर रखने का इरादा था, वह घट कर 6 परसेंट, 7 परसेंट पर आ गया, तो ग्रोथ आप मैनेज नहीं पाएंगे, इनफ्लेशन आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। कीमतें बेहिसाब बढ़ रही हैं, क्योंकि आप देखें, यह आज के ही समाचार-पत्रों में कीमतों का जो विवरण है वह दिल दहला देने वाला है कि ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। सारे के सारे एडिबल ऑयल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिस में कमी आई हो। 10 परसैंट, 8 परसैंट एक ही महीन के अंदर चीजों के दाम बढ़े हैं। चीजों के दाम बढ़ना बहुत खतरनाक है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मंदी आएगी और दूसरी तरफ आप इस देश के अंदर हर महीने, हर 15 दिनों में, आज जो अखबार में आंकड़े हैं, वे तो बहुत चिंताजनक हैं कि हर 15 दिनों के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि खाद्य

तेल है, नमक है, उड़द है। उड़द के दाम बढ़ने से या दालों के दाम बढ़ने से मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि इस देश में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दालें हैं और दालों के दाम जब बढ़ते हैं तो आप न्यूट्रिशन भी घटाते हैं। आप केवल महंगाई ही नहीं बढ़ाते, आप केवल आम आदमी पर बोझ ही नहीं डालते, आप केवल गरीब आदमी की जेब ही नहीं काटते, बल्कि आप इस देश के न्यूट्रिशन को कम करते हैं। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि उसकी खाद्य नीति से न्यूट्रिशन का संतुलन बना रहे या लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहें? अगर यह महंगाई खाद्यान्नों में बढ़ती है तो वह गरीब आदमी, जिसके बजट का 55 प्रतिशत खाद्यान्न पर जाता है, उसका तो बिल्कुल ही दिवाला निकल जाता है। मंहगाई को न रोक पाना, हर चीज में मंहगाई के अंदर वृद्धि होना, यह बहुत खतरनाक है। नमक 5 से 7 परसैंट तक बढ़ गया। हमारे यहां कहा जाता था कि और कुछ नहीं मिलेगा तो नमक-रोटी खा लेंगे, लेकिन गेहूं का दाम भी बेहिसाब बढ़ गया और नमक का दाम भी बेहिसाब बढ़ गया, वो क्या खाए। कहते हैं मिट्टी की रोटी खाइए, जैसे हेती में खाई जाती है। यह सरकार इस देश के लोगों को सामान्य भोजन से वंचित करना चाहती है, न्यूट्रिशन से वंचित करना चाहता है यह बजट।

इस बजट और इस सरकार की नीतियों की वजह से ये हालात पैदा हुई है कि आज देश भुखमरी के कगार पर जा रहा है। कल अगर यही हालात रहे तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, भगवान न करे, यहां भी इस देश के अंदर लाखों-करोड़ों लोगों को मिट्टी की रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीधी-सीधी बात होनी चाहिए। यह बताया जाए कि सरकार की नीतियों का जो दुष्परिणाम है, उसको ये कैसे ठीक करेंगे, यह बजट कैसे इन सारी चीजों का निराकरण करेगा, इस दिशा में यह बजट कैसे बढ़ेगा? मैं नहीं समझता कि इस बजट में कोई एक छोटी सी भी इस बारे में चिंता व्यक्त की गई है। न तो ये महंगाई रोक पा रहे हैं, न ये ग्रोथ ठीक कर पा रहे हैं और न ही ये निवेश के बारे में व्यवस्था ठीक कर पा रहे हैं, वह भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसको हमारे वामपंथी मित्रों ने बहुत जोर से सपोर्ट किया था, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में, मुझे पता नहीं, इनकी क्या दृष्टि है। How do they look upon it मैं यह देखता हूं कि उसमें आम आदमी, यानी असंगठित क्षेत्र जो सबसे ज्यादा तादाद में है इस देश में उसकी क्या हालत है। क्या बजट उसे कुछ दूर तक धकेल सकता है? क्या इस बजट ने इस देश की अर्थव्यवस्था में विकृतियां और डिस्टॉरशंस पैदा नहीं की हैं?

यह बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी रिफार्म्स के बड़े पुरोधा हैं और रिफार्म्स से सारे देश का कायापलट हो गया। हां, कुछ का हुआ है। क्योंकि हम देखते है कि 1992 से 2005-07 के दौरान भारत की वास्तविक आय में 120 से 125 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जब कि इसके पूर्व के 15 सालों में यह केवल 97 प्रतिशत थी। ठीक है, प्रगति हुई है, परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में 77 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन, जरा इसको देखें कि और क्या हालात हैं - विकास दर 9% के आसपास रही है, बचत दर 24% से बढ़कर 30-35% हो गई है और निवेश भी 30% के पास हो गया, विदेशी मुद्रा का भंडार भी 250 बिलियन डॉलर के पास हो गया, कुछ महीनों पहले रुपया डॉलर के मुकाबले बलवान हुआ था, अब फिर टूट गया है। लेकिन, ये जो हालात पैदा हुए, राइज़िंग और शाइनिंग, हर तरह से भारत के अंदर हमने परिवर्तन कर दिया, वह कहां तक पहुंचा, इसका अनुभव बहुत सीमित जनसंख्या को हुआ और वे लोग जिन्हें 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें इस अर्थव्यवस्था की उछाल का पता ही नहीं चलता। मैं आज, कल, परसों अखबार में देख रहा था कि हमारे देश के IIM के छात्रों को डेढ़ करोड़ रुपए के पे पैकेज मिले हैं, सवा करोड़ रुपए के पे पेकेज मिले हैं, दूसरी तरफ जो सबसे कमजोर है, उसे 9 रुपए प्रतिदिन की आय पर जिंदा रहना पड़ रहा है। 9 रुपए और डेढ़ करोड़ और जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग हैं, उनकी आमदनियां तो बेशुमार हैं। मुझे खुशी है कि वे आमदनियां बढ़ी हैं। उसमें चार ही विश्वव्यापी, विश्व स्तर के धनीमानी क्यों हों, चार सौ क्यों न हों, चार हजार क्यों न हों, चार लाख क्यों न हों। यह देश कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, हालांकि वित्त मंत्री का यकीन यह नहीं है। वह कहते हैं कि भारत कभी विकसित था ही नहीं, भारत कभी धनी था ही नहीं। जिन किताबों में यह लिखा है उन्हें जला दो। मैं उन्हें बता दूं कि यह कहां कहा जाता है। मैं बता दूं कि 1830 में मैकाले ने यह लिखा कि मैंने सारा हिन्दुस्तान घूमा और मैं यह जानता हूं कि यह इतना धनी, इतना संपन्न और इतना सुसंस्कृत देश है कि इसको गुलाम बनाए रखना मुश्किल है। फिर जो कुछ हुआ, वह लंबी कहानी है, मैं उसे यहां नहीं कहना चाहता हूं वह records की बात है। ह्वेनसांग, फाह्यान, इन्होंने क्या कहा, जो लोग Alexander के साथ आए थे, उन्होंने क्या कहा, ग्रीक हिस्टोरियन क्या कहते हैं, उसको बिना जाने आपने कह दिया कि हिन्दुस्तान तो कभी धनी था ही नहीं। हिन्दुस्तान धनी था और हिन्दुस्तान फिर से धनी बनेगा।

आज हिन्दुस्तान कुछ धनी लोगों का गरीब देश है, लेकिन एक समय आएगा, जब हिन्दुस्तान दुनिया के धनी देशों में सबसे आगे होगा। यह कुछ धनी लोगों का गरीब देश न रह कर अधिकांश धनी लोगों का संपन्न देश बनेगा। जब तक आपकी अर्थव्यवस्था चलती रहेंगी, तब तक यह नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यद्यपि प्रधान मंत्री ने यह कह कर बड़ी सफाई से हाथ झाड़ लिए कि अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट है, वह एक independent व्यक्ति की रिपोर्ट है और सरकार का उससे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन वह रिपोर्ट बहुत मार्मिक है। उसको देखने की जरूरत है। वह रिपोर्ट यह बताता है, उस रिपोर्ट में जो लब्बो-लुबाब है, वह यह बताते हैं कि इस देश में different expenditure class के हिसाब से जनसंख्या कितनी है। वह रिपोर्ट उपलब्ध है, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहता। वह कहते हैं कि जो दुर्बलतम कमजोर वर्ग है, vulnerable section है, उसकी जनसंख्या 76.7 करोड़ है। एक अरब बीस करोड़ में वह जनसंख्या 76.7 करोड़ है। इसके अंदर भी जब देखा जाता है तो यह पता चलता है कि यह poor vulnerable SC &ST में 87.8 परसेंट है और all OBCs except Muslims में 79.9 परसेंट है, all Muslims except OBCs में 84.5 परसेंट है और अदर्स में 54.5 परसेंट है। Vulnerability भी एक अजीब चीज है, जिसको देखने की जरूरत है। जो vulnerable section का परसेंटेज पोपुलेशन वाइज है, वह आप भी देखें, SC and ST में 33 per cent, all OBC except Muslims, 39.2 per cent; all Muslims except ST and SC, 34.8 per cent; others without ST, SC and OBC and Muslims, 35.2 per cent, यानी देश के हर सैक्शन में vulnerability लगभग बराबर है। यह कैसी हालत है? इस देश में 78.7 परसेंट दुर्बल वर्ग है और हर सेक्शन में लगभग 33 परसेंट यह दुर्बलतम वर्ग है जो थोड़े से आघात से धराशायी हो जाएगा। यह क्यों हो रहा है? इस पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले 15 सालों में जब से ये रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, तब से इस हालत पर गौर किया जाना चाहिए। तब क्या पोजिशन थी और अब क्या पोजिशन है। जिस प्रकार से, जितने प्रयोग हुए हैं, उसका लाभ किसको मिला है। वह भी हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में क्या हालत है। आज इस देश के अंदर करीब-करीब 83 हजार लोग ऐसे हैं कि जिन धन्ना सेठ की परिसंपत्ति तीन सौ अरब डॉलर के आसपास है, जो 2004-05 में उस वर्ष की जीडीपी का 58 परसेंट था। एक धन्ना सेठ की औसत परिसंपत्ति लगभग 35 लाख डॉलर है, जब कि भारत की औसत व्यक्ति आय 630 डॉलर है। यह disparity है। एक धनी की परिसंपत्ति 56 या 57 सौ भारतीयों की आय के बराबर है। इस तरह से 83 हजार धनिकों की परिसंपत्तियां 46.77 करोड़ भारतीयों की सालाना औसत आय के बराबर है। हम चाहेंगे कि भारत की इस बढ़ती हुई समृद्धि का लाभ वित्त मंत्री जी नीचे तक दें। आपने उस दिन गुड गवर्नेंस पर संत तिरुवल्लुवर का एक बहुत ही धार्मिक पद्य पढ़कर सुनाया था, उसके अनुसार इस बजट में कहां वह बिनायनें, कहां वह कम्पैशन, कहां वह गुड गवर्नेंस है। किसी देश में, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रकार से वंचित हो, इस प्रकार से पीड़ित हो, तो इस प्रकार से अवसरों की तलाश में काम कर रहीं हो, संविधान की उस गाइडिंग लाइन से, उस उद्देशिका से, उस Preamble से सर्वथा विपरीत आप जा रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि इस अर्थव्यवस्था से आप देश को आगे ले जा सकेंगे। या इस अर्थव्यवस्था से आप देश में कुछ आगे काम करा सकेंगे।

महोदय, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एन॰एस॰ तो कहता है कि 58 परसेंट आबादी, व्यक्ति नहीं, बेरोज़गारी से जूझ रही है और बेरोज़गारी शहर में पढ़े-लिखे लड़कों में तेज़ी से बढ़ रही है। अगर यह भूख और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी, तो हमारे गृह मंत्री, जो यह रोज़-रोज़ कहते हैं कि हम इस देश में तमाम होने वाले नक्सली और अन्य आंदोलनों पर नियंत्रण करेंगे और आप बराबर उसके लिए पैसा देते जा रहे हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अगर आप बेरोज़गारी, भूख और किसानों की समस्या का हल नहीं करेंगे। देश की अस्सी प्रतिशत आबादी को वंचित करके केवल एक प्रतिशत आबादी की धनाड्यता को लेकर कोई देश विकसित नहीं होता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम और आप इसमें जरूर गहराई से विचार करें। आपका बजट इस दृष्टि से हमें कोई राहत नहीं देता।

फिर अब मुद्रा-स्फीति, inflation - यह किस तरह से बढ़ रहा है, इसका सब अनुभव करें। आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या है इसके मामले में, यह हमारी समझ में नहीं आता है। अभी आपने जितना राहत के लिए पैसा फेंकने की बात कही है, जितना आपने अभी संगठित क्षेत्र को डी॰ए॰ देकर राहत पहुंचाई है और जो आप छठे वेतन आयोग से पैसा बाज़ार में डालेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी। अगर उससे ग्रोथ बढ़ती होती, तो मुझे बड़ी खुशी होती। आप शायद ग्रोथ को stimulate करने के लिए यह पैसा फेंकना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ तो stimulate हो नहीं रही है, ग्रोथ तो बढ़ नहीं रही है। आप पैसा फेंकिए और ग्रोथ न बढ़े, तो वह कहां जाएगा? महंगाई पैदा होगी, देश के अंदर विषमता पैदा करेंगा, वह पैसा कहीं कुछ हाथों में सिमटकर रह जाएगा, यह एक ऐसा दुश्चक्र है, जो मैं बार-बार आपसे सदन में पूछता हूं और आप बार-बार यह

कह देते हैं कि यह बड़ा जटिल है। हां, जटिल है और इस जटिलता को सुलझाना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहां महंगाई न बढ़े, यहां ग्रोथ हो और यहां निवेश ठीक हो, यह जरूरी है। इसका संतुलन आपका बजट नहीं करता और यह बजट मेरी दृष्टि में घोर असंतुलन पैदा करता है। आपका सारा बाज़ार अमेरिका से जुड़ा हुआ है। वहां मंदी आती है, तो आपके यहां भी मंदी आ जाती है। विश्व व्यवस्था में तो यह होगा ही, लेकिन नतीजा क्या है? मैं अभी यह देख रहा था कि आई॰एम॰एफ॰ की एक रिपोर्ट थी, जो यह सवाल पूछ रही है कि क्या भारत में ' धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन हो रहा है? यह सवाल आई॰एम॰एफ॰ पूछ रहा है हमसे। मैं तो 1991 से कह रहा हूं कि ये जो आईएमएफ की नीतियां हैं, वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, मेरे मित्र, रेड्डी जी सामने बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ उस समय इन बातों को कहा करते थे, मैं तो आज भी कह रहा हूं, पता नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं, कि ये नीतियां इस देश में धनी को धनी और निर्धन का निर्धन बनाएंगी और आज उलटे आई॰एम॰एफ॰ हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है?

"इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा,
लड़ते हैं मगर हाथ में शमशीर भी नहीं!"

पूछ रहे हैं हमसे बड़े भोलेपन से कि क्या भारत में गरीबी बढ़ रही है? क्या धनी अधिक धनी हो रहा है और निर्धन अधिक निर्धन हो रहा है? Stiglitz पूछ रहे हैं इस बात को कि भाई, आप अपनी नीतियों को बदलिए, आप inflow के बारे में ऐसा करिए, वैसा करिए और Stiglitz महोदय ने बहुत पहले जो बात कही थी, मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं, पूरी पुस्तक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी "Globalisation and Its Discontents". इसके कवर-पेज को ही थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूं।

" I have written this book because while I was at the World Bank, I saw firsthand the devastating effect that globalisation can have on developing countries, and especially the poor within those countries. I believe that globalisation, the removal of barriers to free trade and the closer integration of national economies can be a force for good and that it has the potential to enrich everyone in the world, particularly the poor market. But I also believe that if this is to be done, the way globalisation has been managed, including the international trade agreements that have played such a large role in removing those barriers and the policies that have been imposed on the developing countries in the process of globalisation, need to be radically rethought". और भी वह कहते हैं, "Globalisaiton today is not working. It is not working for many of the world's poor. It is not working for much of the environment. It is not working for the stability of the global economy."

2003 में Mr. Woltemohn ने कहा, "This world is out of balance." उन्होने कहा कि, "let us identify those forces who have created this imbalance". And I say that ;this IMF-World Bank model of development is one of the biggest forces which is destabilising the global economy. It has created a wide gap between the rich and the poor. It has plunged now one-sixth of the world's population in the pangs of hunger, deprivation disease, squalor, and no education. If this is what you mean by 'a globalized economy' and 'the uplift of economies', then I ask: What else will be the meaning of 'poverty', and what will be the meaning of 'economic exploitation?' वित्त मंत्री जी, आप किस अर्थव्यवस्था की तरफ हमें ले जा रहे हैं? आप भारत की अर्थव्यवस्था की लिए भारत के हिसाब से सोचिए। भारत में बहुत potentiality है, भारत में बहुत दम है, भारत की तरफ देखिए, भारत की तरफ ध्यान दीजिए। आखिर में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि आपका बजट communally divide कर रहा है, communal बजट है। आप बजट स्पीच में यह कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए यह होगा। आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में माइनॉरिटीज के लोगों को हम पैरा-मिलिट्री फोर्सिज में भर्ती करेंगे- यह क्या है? यह क्या communalisation of Budget आप कर रहे हैं? सच्चर कमेटी की बातें कही जाती है। मैंने उसका analysis किया है। समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगा लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक भ्रम है कि इस देश में किसी खास कम्युनिटी के साथ विशेषकर मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आज इस देश में सच्चर कमेटी के मुताबिक 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें मुसलमान भाइयों की शिक्षा की दर उनके राज्य के औसत से ज्यादा है- उसमें

झारखंड भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें गुजरात भी है। यह इस बात का सबूत है कि मुसलमान तरक्की कर रहा है, इस बात का सबूत है कि वह पढ़ने में आगे आ रहा है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कुछ राज्यों में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की दर राज्य के औसत से और पुरुषों के औसत से बहुत ज्यादा है। यह हो रहा है। हमने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, और भी बहुत प्रकार की सहायता उनको दी थी, उसका नतीजा हमें मिल रहा है और मिलना चाहिए। आप उनको शिक्षा दीजिए, वे आगे आएंगे। वे इसी देश के निवासी हैं। उनकी बुद्धिमानी में मैं कोई कमी नहीं देखता। मैं बुद्धि को किसी धर्म या जाति की बपौती नहीं मानता हूं। प्रतिभा हरेक के लिए समान है। उनको आप अवसर दीजिए, वे आगे आ रहे हैं। ग्रुप-ए सर्विसिज में राज्यों में उनकी संख्या बढ़ रही है। बैंक डिपॉजिट्स में, टोटल जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उसमें 12 परसेंट मुसलमान भाई हैं, तो कि उनकी आबादी के बराबर है। कौन सा अन्याय है? कहां से उनके पास पैसा आ रहा है? जब काम कर रहे हैं, देश की प्रगति में भागीदारी कर रहे हैं तो पैसा आएगा। उनके अकाउंट पर जो लोन की संख्या है, वह पिछले चार-पांच साल में, यानी 2004-05 के पहले दुगुनी हो गयी है। क्यों हुई? कैसे हुई? फिर कहा जा रहा है कि वे सर्विसिज में नहीं है। अरे भाई, हर आदमी सर्विसिज में नहीं आता है लेकिन वे लोग जो काम कर रहे हैं, वह एक्सपोर्ट ओरिएंटिड काम है। आप हैंडलूम में उनको देखिए, brassware के अंदर उनको देखिए, साड़ी के काम में आप उनको देखिए- वे पैसा लगा रहे हैं। सर्विसिज में आएंगे। शिक्षा में जैसे-जैसे वे आगे बढ़ेंगे, उनकी तादाद वहां भी आएगी। वे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैंने 40 साल तक पढ़ाया है और मैं यह कह सकता हूं कि जो मुसलमान लड़के आते थे, वे किसी से कम नहीं होते थे, टॉपर्स भी होते थे। इसलिए यह कहना कि हम उनके लिए विशेष करेंगे, उनको भी भ्रम में रखना है। साफ बात होनी चाहिए। पिछले साठ साल में हिन्दुस्तान की राजनीति ने और अर्थनीति ने जो अवसर लोगों को दिए हैं, उससे मुसलमान भाइयों ने लाभ उठाया है। वे और लाभ उठाएं, हमें खुशी होगी। वे देश की प्रगति में और भागीदारी करें, हमें और खुशी होगी। आप पाकिस्तान के साथ तुलना कीजिए। पाकिस्तान की क्या हालत है और हिन्दुस्तान की क्या हालत है। तुलना कीजिए कि जो मुसलमान यहां रह गए थे वे कौन थे, किस हालात में थे। जो यहां से चले गए, वे कितनी सम्पत्ति लेकर गए। इन्होंने पिछले साठ सालों में, इस देश की राजनीति के कारण इस देश के मानस के कारण एक अवसर पाया है और उस अवसर से वे आगे बढ़े हैं। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, हमें खुशी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ ऐसा कर दें कि राशि वहीं जाएगी। फिर दलित का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा? वे भी vulnerable हैं। इसलिए अर्थनीति को इस तरह से कम्युनलाइज करने के हक में हम बिल्कुल नहीं हैं। अर्थनीति सबके लिए समान होनी चाहिए। अर्थनीति का लाभ सारे देश को मिलना चाहिए। यह सेक्टोरल, यह कम्युनल बजटिंग हम पहली बार सुन रहे हैं। यह बहुत गलत है और मैं इस प्रकार की बजटिंग का विरोध करता हूं। क्लाइमेट चेंज के बारे में ....(व्यवधान)...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, I ....*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI. I am not yielding.

इसके बारे में तकलीफ होती है, क्योंकि वोट बैंक पर असर पड़ता है, उधर से भी आ रही है चुप रहो, हम बोलेंगे, चुप रहो हम बोलेंगे, क्या बात है? साफ बात सुनने की कोशिश कीजिए।

फिर क्लाइमेंट चेंज पर क्या असर होंगे, यह लम्बी कहानी है, इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्लाइमेंट चेंज से उद्योग और कृषि दोनों बुरी तरह से प्रभावित होंगे, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो प्रोडक्शन मॉडल है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों प्रभावित होंगे। बिजली के सेक्टर में आप एलईडी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनसे आप आठ-आठ सौ मेगावाट बिजली बचा सकते हैं, जो सारी दिल्ली के लिए पर्याप्त हो सकती है। सिर्फ स्ट्रीट लाइट में नेनो टेक्नालाजी का प्रयोग करिए। आप साइंस एंड टेक्नालॉजी की बात करते हैं, मगर उसका उपयोग आम आदमी के लिए नहीं करना चाहते हैं। Where is the common man? Where is this man? इसका बजट में कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए उपसभाध्क्ष जी, मैं इस बजट का तीव्र विरोध करता हूं और इस बजट की मूल धारणा से मैं असहमति व्यक्त करता हूं। यह आम आदमी के खिलाफ है, यह ग्रोथ के खिलाफ है, यह किसान के खिलाफ है और यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, क्योंकि यह बजट में कम्युनल डिवाइड पैदा करता है। धन्यवाद।

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): Thank you, Dr. Murli Manohar Joshi. Now, Shri Janardhana Poojary.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Thank you, Sir. This is the best Budget which I have seen for the last so many years. Sir, there is a qualitative change in the Indian economy. ...*(Interruptions)*... I am not saying this for scoring a debating point. Sir, if you kindly see the fundamentals of the economy since the First Five Year Plan till the Eleventh Five Year Plan we are in the first year of the Eleventh Five Year Plan—we have gone a long way. There is a contribution that has been made by the people of the nation.

Sir, now here, if you kindly look into the history of the Congress of 123 years, when we started, we promised to the nation that we are committing ourselves for the freedom, that is, the political freedom. Then, Sir, we have also promised that we are going to give them economic freedom and are going to free the country from the economic slavery....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Pany, if you want to talk, you go to his seat and talk. ...*(Interruptions)*...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Orissa): Sir, I am a very good listener. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can go to him and speak.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, पाणि जी ही नहीं, यहां तो मंत्री जी भी बात करते है। ....(व्यवधान).. प्रथम पंक्ति में बैठे हुए वित्त मंत्री जी और जयपाल रेड्डी जी, आपस में बात कर रहे थे, तब आपने टोका नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): सर, वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, उस समय आपने टोका नहीं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. That is not the point. Mr. Pany is talking at a distance from where I can directly hear. That is the point. I can hear him. I have not heard others. If I hear them, I will certainly tell them. ...*(Interruptions)*... If I hear them, I will tell them.

SHRI JANARADHANA POOJARY: Sir, when I saw through the TV ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): One second, See, if you want to talk to a Member, go to his seat and talk, then, I will not be disturbed. But, here, what happened is, from this side, he is talking loud ...*(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH: Sir, nobody should talk including Ministers. ...*(Interruptions)* ..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, that is the rule. ...*(Interruptions)*... Amar Singhji, that is the rule ...*(Interruptions)*... Okay, please.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, after attaining political freedom, we went in for Industrial Policy Resolution of 1948. Sir, it is not a new thing. The words might have been changed. Globalisation, liberalisation, etc. have been there even after 1948. So, we wanted to progress. The then Prime Minister of the nation had a vision that we must have a mixed economy. On the one side, there should be public sector and, on the other, there should be private sector. Both should contribute to the development of the nation. After the Bhubanswar Resolution, in Bangalore Resolution, the All India Congress Party

has come out with ten points. There we have committed ourselves to a vibrant and very strong economy with growth as also social justice. Today, we are coining another term "inclusive growth". It is not a new thing. The point which I am going to make is that we have been criticised. I belong to a poor family. I have seen poverty. I have seen hunger. When I saw the hon. Minister presenting the Budget, in fact, for the first time, I felt that he had touched the heart of the people of this country. I will come to the point why I was moved later. He touched every sector of the economy, every section of the people of the nation. You have seen the farmers' plight. He has touched them. His heart has bled for them. He has touched the middle class people. He has also touched the old people. He has contributed much more to the State exchequers also.

Now, first, I would deal with the State resources which have been transferred from the Central Government. In the year 2004-05, an amount of Rs. 1,86,871 crores was transferred to the State. In the year 2008-09, an amount of Rs. 3,28,420 crores has been transferred to the States . What a big jump! We have been criticised earlier. When I was in the Finance Ministry also, we had been criticised saying that the States were neglected and sufficient funds were not made available to the States. Now, the credit will go to the UPA Government, the Congress Government, as also to the allies, including our ally the CPM, the Left Party. Now, fiscal management has been done. The point is whether the Indian economy has seen a boom, whether we have developed to the extent which is expected by the people of the nation,

You kindly go through the Budget. He has given some Flagship Programmes in the Budget. He has stated. "The National Rural Employment Guarantee Scheme will be rolled out to all 596 rural districts in India. Initially, we will provide Rs. 16,000 crore. Let there be no apprehension in anyone's mind; as demand rises, more money will be provided to meet the legal guarantee of employment". Where is it going? It is also going to the States. It is also going to the rural India. It is going to help the weaker sections there, particularly the labours who do not have any work. Those people are touched. They will be very happy. Then he says, "The Jawaharal Nehru National Urban Renewal Mission is the main vehicle for improving urban infrastructure. It has also succeeded in driving reforms in urban governance and urban-related laws. I propose to increase the allocation from Rs. 5,482 crore in 2007-08 to Rs. 6,866 crore in 2008-09". This section of the society in the urban areas will also be helped. Then, he says, "The goal of the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission is to supply safe drinking water to uncovered habitations and slipped back habitations as well as to address issues of quality. I propose to enhance the allocation to Rs. 7,300 crore".

These are the flagship programmes. Why I am bringing these to your notice is that he has touched every section of the society.

Now, if you go to the housing sector, he says, " Housing for the poor is one of the six elements of Bharat Nirman and is implemented through the Indira Awas Yojana. Against a target of 60 lakh houses, 41.13 lakh houses have been constructed up to December, 2007, and the cumulative number will be 51.77 lakh houses by end March, 2008." Reflecting the higher cost of construction, I propose to enhance the subsidy per unit in respect of new houses sanctioned after April 1, 2008 from Rs. 25,000 to Rs. 35,000 in plain areas and from Rs. 27,500 to Rs. 38,500 in hill/difficult areas." He further says: "The subsidy for upgradation of houses will be increased from Rs. 12,500 per unit to 15,000. A beneficiary will still need own funds to complete the house. Public sector banks will be advised to

include IAY houses under the differential rate of interest scheme and lend up to Rs. 20,000 per unit at an interest rate of 4 per cent." In other words, up to Rs. 20,000, the banks will provide loans under differential rate of interest, that is, at 4 per cent interest. So, in addition to giving subsidy for construction of houses for the weaker sections, the banks will also provide up to Rs. 20,000, which means, they can go in for houses with a subsidy of Rs. 35,000 plus the differential rate of interest on Rs. 20,000. Then, Sir, in the Budget, he further says:

> "the Aam Admi Bima Yojana that will provide insurance cover to poor households. I am happy to annouce that, in the first year of the Yojana , the LIC will cover one crore landless households by September, 2008. I have already placed Rs. 1,500 crore with the LIC. In order to cover another one crore poor households in the second year, I propose to place an additional sum of Rs. 1,000 crores with LIC in 2008-09." Sir, you will kindly note that this is a very important steps in the interests of workers in the unorganised sector. You will also not that there are various aspects as far as the Scheduled Castes are concerned; like, the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana, establishment of a large number of micro enterprises in rural areas- activity cluster and group approach are the two key components of the Programme. He has said, "At least 50 per cent of the Swarozgaris will be the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes: 40 per cent will be women and three per cent will be unorganised workers." I must congratulate the hon. Minister for this steps. How can you, then, say that it is not in the interest of poor people?

Then, Sir, look at rural housing.

Sir, as per the Indira Awas Yojana guidelines, houses should be allotted in the name of female members of the households or in the name of the husband and the wife. Then, 60 per cent of the total allocation is to be utilised for the construction of houses for SC/ST BPL families. Sixty per cent! This had never happened. What a step! Can anybody criticise this Budget saying that it is not for the poor? Yes, there is the UPA Chairman; she is responsible for the loan waiver. We have to congratulate not only Dr. Manmohan Singh, but we must also be grateful to Madam Sonia Gandhi. Then, I do not want to denigrate our allies also. We must congratulate UPA's allies also for supporting this Government and enabling it to do all this reconstruction.

Then, what have we done for the Central Plan? What is the amount that has been allocated? Sir, out of Rs. 7,50,848 crores, the total Budget amount, how much is for the Central Plan? If you kindly go through the Budget Papers, the Central Plan outlay, for all sectors, comes to Rs. 3,75,485 crores. But, Sir, where is this Central Plan located? Is there any particular place in India which is said to have the Central Plan? It belongs to all the States. There is no place which is said to belong to the Central Government. So, the Central Plan belongs to the entire country. Whatever project is there, whether it is a cement factory or a coal factory or any other unit of a public sector undertaking, it will naturally be located in a particular State. This is the development model. Here is a Government, Sir, which thinks of the nation as a whole . So, one one can criticise; it is very easy to criticise. When we were on the opposite side, we also were criticising the Government . Sir, Governments may come and Governments may go but the nation should keep on progressing. Now, what is the GDP growth rate? The GDP growth rate is 8.4 per cent. What is the GDP growth rate of America? Sir, in 2008, the GDP growth rate of the USA is 1.9 per cent. The

rate of growth of GDP of the United Kingdom is 2.3 per cent. And, These are developed countries.The rate of growth of GDP of Japan is 1.7 per cent. Then, the rate of growth of GDP in respect of Australia, which is a small country and which does not have a population of even two crore, is 3.8 per cent. If you take that into consideration, the average growth rate of GDP in these developed countries is about 3 per cent. If you take into consideration the average growth rate of GDP in respect of developing countries, it is 5 per cent. Now, look at India's GDP. The rate of growth of India's GDP is 8.24 per cent. Why should we belittle ourselves? Is it not the performance of the Indian people? Is it not the performance of our workers? Is it not the performance of our workers? Is it not the performance of our farmers, engineers and so on? Should we not be proud of them? Then, we say, American people are in a better position than we are!

Japanese are better than us; we are good for nothing. If that is the feeling that is going out, it is not good. Sir, we should be proud of our achievements. Yes, there should be a lot; we have to do a lot more for that purpose. Sir, as I stated earlier, including the State Plans, and including the Central Plan, it will be about four to five lakh crores of rupees. What is our dependence on the foreign assistance? It is not even seven per cent ! That is the strength of the economy. While presenting the Budget, the Finance Minister has stated, 'I will be in a position of creating the wealth, and this wealth should be distributed among all the sections of the society, particularly, to the weaker sections, particularly to the people who are below the poverty line.' I want to know whether it would have been possible without the growth, without the cooperation, without the sacrifice and without the labour of all the sections of the society. So, I can only say that we are proud of the Indian people. For that purpose, Sir, I am requesting the Members of the Opposition not to criticise it. Yes, for oppositon sake, you can criticise it.

Sir, everybody here, including the BJP, the Members of our Left parties, our Congress people, and the nation was crying at the distress of farmers, who were committing scuicides in thousands. Sir, when I was the President of the Karnataka Pradesh Congress Party, for four or four-and-a-half-years, there was drought. There was no water. The people were borrowing money from the banks, cooperative banks and the moneylenders. There was no water, even after digging three or four bore wells. There was no crop. There was nothing. In their houses, there was nothing. You may not have listened about it, but I have seen so many deaths; hundreds of farmers had committed suicides. In one family, Sir, seven children were without food for seven days. One the eighth day, all the seven children fell prey to the poison; they committed suicide. At that time, Sir, our Congress people came to put shawl on me and give flowers to me. Then, I said, 'till the time we get rain throughout the State, I will not receive any shawl or any flowers.' I stated this, and I am still maintaining it. That was the condition there. Every citizen of this country was crying for that. They were crying that we should do something for them. When we have done that when the Government has come forward to help the farmers, we are being criticized! When Mrs. Sonia Gandhi is taking a lot of interest in that, why should there be a hue and cry about it? We should have given them even more. But, unfortunately, we are not in a position to give. Sir, I request you to go through page 13 of the Budget Speech of the hon. Finance Minister relating to debt waiver and debt relief. The scheme is, " Having carefully weighed the pros and cons of the debt waiver and having taken into account the resource position, I place before this House a scheme for debt waiver and debt relief for farmers." I am reading it because you are also interested in it.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

"All agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, regional rural banks, and cooperative credit institutions up to March 31, 2007 and overdue as on 31st December, 2007 will be covered under the scheme." I would tell you what the effect would be so far as Karnataka is concerned. For the marginal farmers who are holding up to one hectare and small farmers holding 1-2 hectares, there will be a complete waiver of loans that were overdue on December 31, 2007, and, then, which remained unpaid till February 29, 2008. In respect of other farmers, there will be a one-time settlement, OTS Scheme, for all loans that are overdue on December 31, 2007. Sir, even for the big farmers, there would be a relief to the extent of 25 per cent, which remained unpaid till February 29, 2008 under the OTS, a rebate of 25 per cent would be given against the payment of balance of 75 per cent.

When there was the JD(S)-BJP Government in Karnataka, they gave a relief to the extent of Rs. 25,000. In order to get that relief, those who were in distress— Sir, they were about to commit suicide—went to all places, asked and begged for money saying, "We are getting Rs. 25,000 benefit, please pay the principal amount. If you pay the principal amount, we will be given that benefit, otherwise not. Please give me Rs. 25,000." So, these people, in order to get that Rs. 25,000 relief, they went and borrowed the money from all sources. Then, they were given the loan. Now, Sir, this date is very important: March 31, 2007. If there is any loan disbursed up to 31st March, 2007, no benefit after that! So, I am requesting the hon. Minister to kindly extend this date upto 31st December, 2007. Then, those farmers would be getting the benefit. Otherwise, Sir, very few people will be benefited. He and the Government have done a wonderful job as the Finance Minister. I ask the Government and the Minister as to why do not you realize this.

My submission to the Finance Minister is, when you have touched the hearts of the people, when you wanted to save them from the clutches of the money-lenders and banks, at least, those who have paid by borrowing again, those farmers will not be benefited. Farmers are highly respected people. They may even die, but in high esteem. The poor people are like that. Unfortunately, for their honesty, they have to suffer now! So, I am requesting all the people, through you, Sir, when you have done it, it is the contribution of all the people. Their cry has been heard by the Government. You wanted to help the poor farmers. It is not a beginning? Rs. 60,000 crores is not a small amount in a Budget of Rs. 7,50,884 crores. It is not a small amount. Then, I would say, it is an investment for boosting the agricultural production. When he is free, if there is no loan, then, Sir, he will be in a mental condition to work for the production. If they are still reeling under the debt burden, you will not be in a position to produce more. So, indirectly it is an investment in the agricultural sector. When you have given Rs. 2,40,000 crores as a loan to these farmers, this is a big step that you have taken. Not only that, Sir, you have taken so many steps even for irrigation also. So, my submission is, when you are coming to their rescue, you have done a wonderful job. We are grateful to the Government, but at the same time, save those people also who are sincere. So far as coffee and other plantations are concerned, under this scheme they are also covered, I am told by Mr. Ramesh, the hon. Minister for Commerce. I congratulate them also for bringing the coffee plantation and other plantations under this scheme. Sir, it has been criticized that nothing has been done for the Public Distribution System. It is a relevant point. It has to be strengthened. It is going to the root of the uplift of the weaker sections. A sum of Rs. 32,667 crores is being provided next year for the food subsidy under the Public Distribution System and other welfare programmes. Sir, this should reach the poor people. It is the duty of the State Govenments. Here also the bank debt relief, it should reach them. You know the attitude

of some of the bank employees and bankers also. So, if it is not going to them, then *danda* should be used. They should be told that this is the time limit we are giving you. Relieve them and let them produce. In 2003-04, the food production was 213 million tones and it has been increased to 219 million tones. It is not sufficient. You may have been today's newspapers. There is food shortage throughout the world. If you are not going to produce more food, then what will happen? You are talking about Special Economic zones and at the same time, you are talking about the food security also. If you are going to give this fertile land to those people how are you going to have more food production? Can you eat only industrial production? We have reached population of 113 crore people. You have got 113 crore mouths to eat. Are you not taking into consideration that also? The other day I did not like the answer of the Commerce Minister saying that in the Special Economic Zones houses could be constructed, hotels could be constructed. Oh! Oh! Hotels could be constructed, Houses could be constructed, but what about 113 crores people's hunger? What about their food? Are you not going to take into consideration that factor? Yes, some people may say, yes, Sir. When this debt relief was given, -even from some people from industrial sector,-there was a hue and cry on TV, oh! Oh! As a former Finance Minister in the Banking Department, I ask how may crores of the rich industrialists have been written off. Let the Government come with those figures and tell how many crores and lakhs have been written off since 1947. Sir, there was a hue and cry in the Parliament, "when you are giving loan to the weaker sections, the poor will not give back, the farmers will not give back, the women will not give back that amount". It was said. "Without security, you are giving". When all this hue and cry was raised, Indiraji, the then, Prime Minister, a woman, a mother, that is woman's heart-there are so many leaders here-stood up and said. "Yes, our poor people will give back." They are giving back the money. They are paying back the amount. It was stated that labourers are not paying, women are not paying, then, I stated, the rich people's loans have been siphoned off. Sir, some industries are shown as sick industries; money has been diverted, and huge industries have been started. All this you have seen, Then, if tomorrow, the Government comes up with some statistics, no voice will be there to oppose, as is being done now when help is being given to the weaker sections. We will also say, how many big industries, big corporate, big companies owe to the country. It is also people's money. That is why, I was just telling you let us not hear that voice. Why should there be Naxalities? It is a social problem. Nowhere it is written that it is Naxalite. They don't have anything. We are seeing girls going with guns in the forest, knowing that it is full of thorns, with no water, no shelter. But they are going, we are seeing. Why? We are not supporting them. Why are they doing it? They are killing; they are cutting off the heads. Why are they doing it? They don't have employment; they don't have any income. Nothing is there. For years, they are waiting, waiting, waiting! They know they will be killed by the police, they know they will be hunted by the people and the police. But still they go. Why? Has anybody understood it? Indira Gandhi at that time understood it; that is why, she came up with the 20-Point Programme. She had given land to the weaker sections. That is why she is remembered today also. Somehow, I don't blame all the rich industrialists. Those people cannot understand this; they are condemning, they are insulting those poor people, they are insulting the farmers. For that purpose, I am just telling you, Sir, the voice of the Parliament, all the people belonging to all sections, whether this party or that party, their heart is beating. Sometimes, there is some *hulla gulla*, and there will be. It is stated, Sir, that we are throwing to the winds the democratic principles and everything. Sometimes, I am quietly observing it. If their voice is not heard here, what will happen? Sir, for the academic purpose, for professors and other people it will be very nice to say. So, there should not be *hulla gulla*. Why should there be *hulla gulla*? Why should there not be

gun fighting? Then, fight is here. It is the Parliament. It is the voice of the nation. Sir, here also, sometimes, you are forgetting us, and forgiving us also. But, at the same time, for the last so many years, that is being allowed here. Nobody will care unless you cry. Even a mother will not give milk to her children. This is the fate. For that purpose, Sir, for this present state of Indian economy, I must congratulate our Government, our Prime Minister, even the Finance Minister, The UPA Chairperson and all the parties. For this reason, I say that we are proud of the nation, we are proud of 113 crores of people. The contribution of those people who are working here on this Table is also there.

Their contribution is also there. If you forget all these things and if you go on criticising, it is not good for the country. At least, don't do this for the sake of the country. I have also been a critic. You see me performing in Parliamentary Committees; I will not spare the concerned if it is in the interest of the nation. It is immaterial whether it is our Government or any other Government. But, if you are opposing just for the sake of opposing, sometimes, we also feel that you are not doing the correct thing. Even if we are in the opposition, we should not do it. Why should you grumble? Are you afraid that you are going to lose? It is for the people to decide. If we perform well, if we give good governance, people will vote for us. They will bring us back. If we don't perform, they will throw us out. It has happened in history.

Sir, you have given me a lot of time. I am asked to be brief, because there are eight more speakers from my party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are eight Members from the Congress Party.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am sorry, Sir. I am retiring. Please pardon me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I am not putting my finger on the time-bell.

SHRI JANARDHANA POOJARY: So, Sir, with these words, I conclude my speech. Thank you very much.

श्री अमर सिंह: धन्यवाद, उपसभापति महोदय। आज लोकशाही को हाज़िर-नाज़िर जानकर आपके समक्ष मैं खड़ा हूँ। राजनीति करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि सच को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे बुजुर्ग नेता, विद्वान नेता डा॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत सारगर्भित लंबा भाषण दिया और अपने भाषण में बार-बार माननीय वित्त मंत्री जी को और हमारे पुराने दोस्त जयपाल रेड्डी जी को एक आध बार संबोधित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं और चिदम्बरम जी चले गए। सौभाग्य इसलिए क्योंकि जयपाल रेड्डी जी सहनशील हैं, वह हमारी बात को सह लेंगे, सुन लेंगे और चिदम्बरम जी के लिए कुछ कहने से डरता हूं क्योंकि वह बड़े हाकिम हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार और इस सरकार के, ये दोनों लिविंग लिन्क हैं। जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी, जिसमें हमारे नेता मुलायम सिंह जी थे, उसमें भी ये लोग थे और आज की सरकार में भी ये लोग शामिल हैं। ये लोग सदाबहार, evergreen politicians हैं। यहां पर जोशी जी कह रहे थे कि हमारी नीति और तुम्हारी नीति, मेरी और तुम्हारी नीति। मुझे तो लगता है कि इधर के बैठे लोग और उधर के बैठे लोग हमारी नीति है। उदारीकरण के पक्ष में कौन ज्यादा है, यह कह पाना मुश्किल है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री जी वहां बैठकर राजनीति के भीष्म पितामह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दुहाई दे रहे थे और आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नारायणन की दुहाई नहीं दे रहे थे, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा जी को उद्धृत करके इधर का समर्थन मांग रहे थे। औपचारिकता के लिए कभी ये खड़े होकर उनकी लानत-मलामत करते हैं और कभी ये खड़े होकर इनकी लानत-मलामत करते हैं। उदारीकरण के प्रश्न पर, लिबरलाइजेशन के प्रश्न पर, पूंजीवाद को बढ़ावा देने की कीमत पर, दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। ऐसा मेरा मानना है ...(व्यवधान)...।

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): बीच वालों की स्थिति खराब है।

श्री अमर सिंह: चलिए, आप हमको त्रिशंकु कहना चाहते हैं, तो हम लटके तो रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि 60 हजार करोड़ रुपए ऋण की माफी इस बजट में करने की घोषणा हुई है। हमारे मित्र जयपाल रेड्डी जी, आपने तो देवी लाल जी के साथ ज्यादा काम किया है, कांग्रेस के साथ काम करने का आपका अनुभव थोड़ा कम है, आप हमारे साथ ज्यादा रहे हैं। आप हमारे भी प्रवक्ता रहे हैं और इनके भी प्रवक्ता हैं। तो दो दशक पूर्व देवी लाल जी ने ऋण की माफी की थी और ऋण की माफी के बाद जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में देवी लाल जी को और उनकी पार्टी को विशेष लाभ नहीं मिल पाया था। अभी परम आदरणीय प्रात: स्मरणीय माननीय चिदम्बरम जी ने कहा है कि ...(व्यवधान)... हमारी कितनी बड़ी सफलता है कि हम 60 हज़ार करोड़ रुपए के ऋण की माफी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी बयान दे दिया-हम ऋण की माफी तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दो सालों में हम किसानों को दिए जाने वाले ऋण की राशि दोगुनी कर देंगे। क्या अद्भुत विलक्षण प्रस्ताव है! जो कर्ज़दार है हमारा किसान, उसके कर्ज़ की मुक्ति कर रहे हैं, फिर उसे दोगुना कर्ज़ा देंगे, ताकि वह दोगुना कर्ज़दार हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसान कर्ज़दार होता क्यों है? उपसभापति महोदय, इस मूल कारण पर किसी ने रोशनी नहीं डाली इस बजट में! किसान कर्ज़दार इसलिए होता है कि किसानी आज के समय में लाभप्रद नहीं रही। मैं उदाहरण देता हूं-ग्रीन रिवॉल्यूशन देश में हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई है। हमारे राजस्थान के सांसद अगर यहां होंगे, तो उनको याद होगा कि राजस्थान में एक बार बाजरा खूब हुआ। बागड़ोदिया जी, आपको याद होगा-बीच में एक बार बाजरा खूब हुआ और जब खूब बाजरे का उत्पादन हुआ, तो किसान खुश हो गया, बम-बम हो गया कि बाजरा हुआ है। उस समय बाजरे की कीमत थी साढ़े पांच रुपए। इतना बाजरा हुआ कि बाद में उस बाजरे की कीमत सीधे घटकर हो गई ढाई रुपया! यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, रिवॉल्युशन हो गया बाजरे का, लेकिन साढ़े पांच रुपए का बाजरा ढाई रुपए पर आ गया, यानी यह किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लेकिन उसके साथ-साथ दाम भी बढ़े। हमारा मानना यही है कि अमेरिका में मक्के का उपयोग बॉयो डीज़ल के लिए हो रहा है और ब्राज़ील में चीनी उद्योग में सीधे -सीधे गन्ने के रस से ethanol बना रहे हैं। हम अमेरिका की अंधाधुंध नकल करते हैं, पाश्चात्य संस्कति की नकल करते हैं, उनकी व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अपनी कृषि के लिए, अपने कृषि के उत्पादन के लिए, किस तरह से कृषि उत्पादन को लाभप्रद बनाया जाए और अगर लाभप्रद नहीं है तो किस तरह से subsidise किया जाए, इस पर जो उन देशों में विचार होता है, उस पर हमारे देश में विचार नहीं होता है। हम कहते हैं, जो अब तक का कर्ज़ा है, उसको हमने माफ किया और दोगुना कर्ज़ा हम देंगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के किसान को दोगुना कर्ज़दार बना देंगे, लेकिन उत्पादकता बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए और किसानी लाभप्रद न हो। सबसे बड़े मज़े की बात यह है महोदय कि कोई आयोग हमने नहीं बनाया, बीच वाले लोगों ने! यह चाहे स्वामीनाथन आयोग हो, इसका भी गठन आप लोगों ने किया है, चाहे सी॰ए॰सी॰पी॰ हो, यह भी आपकी उपज है और चाहे राधाकृष्णन आयोग हो, यह भी आप ही लोगों की करामात है, आप लोगों द्वारा बनाया गया आयोग है स्वामीनाथन जी इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक मोटी बात भी कही और कहा है कि किसान की समस्या का निदान तब तक नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा किए गए उत्पादन का लागत मूल्य निर्धारित करके उसको पचास प्रतिशत ऊपर उसका लाभप्रद मूल्य नहीं देंगे और जब तक आप उसको ऋण देंगे, उस ऋण की, ब्याज की दर आप चार प्रतिशत नहीं करेंगे। इस बारे में परम आदरणीय प्रात: स्मरणीय चिदम्बरम जी मौन हैं कि उत्पादकता के मूल्य का निर्धारण करके उसमें पचास प्रतिशत वे देंगे या नहीं देंगे? चार प्रतिशत ब्याज होगा या नहीं होगा? यह स्वामीनाथन आयोग हमने नहीं बनाया है, सुषमा जी ने नहीं बनाया है, वृंदा कारत जी ने नहीं बनाया है, समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया है, आप ही ने बनाया है, लेकिन रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट बनाकर ठंडे बस्ते में फेंक दो।

सी॰ए॰सी॰पी॰ आपने बना दी और सी॰ए॰सी॰पी॰ कोई हमारी बात नहीं है, विरोध की या सत्ता पक्ष की बात नहीं है। मूल्य निर्धारण के लिए हक साहब सी॰ए॰सी॰पी॰ में बैठे हुए हैं। यू॰एन॰पी॰ए॰ के तमाम लोग, वामपंथी साथी, हम सब लोगों ने सी॰ए॰सी॰पी॰ में गुहार लगाई।

जो दर सीएसीपी ने धान के लिए निर्धारित की, अन्य पदार्थों के लिए, कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित की-उस दर से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उस दर को भी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। सीएसीपी आप ही की संस्था है, हमारी संस्था नहीं है। जो दर उन्होंने दी है, वह कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से वह लाभप्रद मूल्य की नहीं है। अब आप राधाकृष्णन आयोग पर आ जाइए। राधाकृष्णन आयोग कर रहा है कि एक लाख पच्चीस हजार करोड़ किसानों का कर्ज

बाकी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आप लोगों की तरह विद्वान नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, illiterate हूं। मैं तो, जो आप लोग लिख देते हैं, पढ़कर सुनाता हूं, कोट करता हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): इलीट्रेट कहां हैं?

श्री अमर सिंह: यानी, इन लोगों की अपेक्षा। इन लोगों का लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं। हमारी अपनी बौद्धिक सोच नहीं है। यह विद्वान लोगों की जो कमेटी बनायी है, राधाकृष्णन कमेटी, उस विद्वान और सुधी व्यक्ति ने लिखा है कि एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का कर्जा है। आपने उसका आधा माफ किया है। जो आधा माफ किया है, वह भी कैसे किया है। संभवतय: यह आखिरी बजट है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं कि यह चुनावी बजट है। पहली बार तथाकथित fiscal discipline and law के ऊपर राजनीति हावी हुई है। चलिए, अवधारणा ही सत्य होती है-Perception is truth-हम यह मान भी लें तो हम यह कहना चाहते हैं कि अपनी सरकार के अंतिम वर्ष के बजट में आपने 60 हजार करोड़ कह दिया, बिना किसी प्रावधान के, बिना किसी बजटरी सपोर्ट और एलोकेशन के। यह 60 हजार करोड़ सुनने में बड़ा लोक-लुभावन और अच्छा लगता है, लेकिन वह तीन साल की अवधि में है। यानी इस साल सिर्फ 20 हजार करोड़ है। उसके बाद दो साल बाद जो सरकार आएगी, वह सरकार आपकी आए या किसी और की आए, उसके सिर पर ठीकरा। अगर उन्होंने किया तो यह आपकी घोषणा है। नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया। वाह! क्या बात है। आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र जयपाल रेड्डी जी चुनाव लड़ रहे थे। कहा नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उनको हम हथियार समेत ले आएंगे। कहा, हम तेलंगाना बना देंगे और यह भी कहा कि बिजली मुफ्त देंगे। महाराष्ट्र में भी यह कहा। वोट ले लिए। महाराष्ट्र में भी बिजली मुफ्त नहीं हुई। नक्सलवाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तेलंगाना नहीं बना, इनके सहयोगी छोड़कर भाग गए। उन्होंने सदन की सदस्यता यहां भी छोड़ी, वहां भी छोड़ दी। इसलिए यह संदेह होता है। यह संदेह प्रासंगिक या राजनैतिक नहीं है। आपका इतिहास ऐसा है कि चुनावी वर्ष में आप कुछ भी कह देते हैं-संभव हो या असंभव हो-सब ले लो। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अखबार के इंटरव्यू में कहा कि ऐसे भी यह लोन जो हमने किसानों को दिया है, वह लोन हमें वापस नहीं मिल रहा था, एनपीए हो गया था इसलिए हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया-बुक एडजस्टमेंट। ऋण के बदले किसान अपनी जान दे रहा था। तो चुनावी साल में किसान की जान थोड़ा ही लेनी है। इस एनपीए को ठीक करना है। जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग हुई है, यह बहुत अच्छी हुई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। You need to be congratulated for this financial restructuring and rescheduling. जो corporate लैंग्वेज में कहते हैं कि reschedule हो गया है। अभी तक rescheduling बड़े-बड़े धन्ना सेठों की होती थी, पहली बार हिन्दुस्तान के गरीब किसानों के लिए भी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों का सर्वे निकल रहा है। आप लोगों के विशेषज्ञ आंकड़े दे रहे हैं। सिर्फ इस तथाकथित साठ हजार करोड़ रुपए में आंकड़ा कुछ इस तरह से है कि 4.8 परसेंट कोऑपरेटिव सोसायटी, 22.3 परसेंट बैंक, 35.8 परसेंट गांव का सूदखोर, 32.4 परसेंट रिश्तेदार और मित्र और 1.6 परसेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप-ये आंकड़े मेरे पास हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का एक बयान आया कि जो सूदखोर ने, मनी लैंडर ने दिया है, उसके बारे में हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के क्रिकेटप्रेमी, लब्ध प्रतिष्ठित किसान नेता, देश के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी का बयान आया कि सूदखोरों को पैसा मत दो, इनको मारकर भगाओ। यह सामूहिक जिम्मेदारी का विलक्षण नमूना है, collective responsibility का wonderful example है। सूदखोर के लए वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते हैं और कृषि मंत्री जी कहते हैं कि दो मत, मार भगाओ, किसको सच मानें, मैं बड़ी मुश्किल में हूं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। वित्त मंत्री जी की सुनूं या कृषि मंत्री जी की सुनूं, एक टेक्नोक्रेट हैं और एक शुद्ध पोलिटिसियन हैं, टेक्नोक्रेट की टेक्नीकल एडवाइज़ पर जाऊं या पोलिटिसयन की प्रगमैटिक पोलिटिकल एडवाइज़ मानूं, देश का किसान भ्रमित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार हमें इस भ्रम से मुक्ति दिलाये। मैं कहना चाहता हूं कि हारवेस्टर पर, एक्सकेवेटर पर आप टैक्स लगाते, जो फर्टिलाइजर सबसिडी किसानों के लाभ के लिए है, वह फर्टिलाइजर के मिल मालिकों की जेब में चली जाती है। वह मिल मालिकों की जेब में न जाये, किसानों की जेब में जाये, इसके बारे में कोई विचार आपने नहीं किया है। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, आपने बहुत अधिक धन का प्रावधान किया है और आपने शिक्षा का बजट बढ़ाया है, लेकिन सरकारी स्कूलों के नतीजे वैसे ही हैं जैसे हॉकी की टीम के नतीजे हैं।

असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए बीमा योजना शुरू की है। नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम, जो 100 दिन के लिए है, इसे आप भी मानते हैं, हर राज्य में दे दी गयी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके दल से सबसे बड़े नेताओं में

एक आपके दल के जैजन्यमान युवा प्रतीक श्री राहुल गांधी ने कहा है कि नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, आंतरिक लोकशाही हमारे दल में नहीं है। नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गांरटी स्कीम आपने पूरे देश में लागू कर दी, यत्र-तत्र-सर्वत्र आपने फैला दी, यह चालू थी, लेकिन इसके बाद बड़ा शानदार नतीजा आया हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, त्रिपुरा में और मेघालय में। अभी हमारे दोस्त जनार्दन पुजारी जी कह रह थे कि डरते क्यों हो, काम करो, जनता वोट देगी, आपने खूब काम किया, नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम लागू की, 100 दिन के लिए लागू की, आपने सब जगह इसको फैलाया, सब राज्यों में फैलाया, लेकिन जितने चुनाव हुए, उनमें जैसे आपने सफलता के कीर्तिमान और मानदंड स्थापित किये हैं, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह चुनावी बजट है, मैं ढोल नहीं पीट रहा हूं, सबसे पहले किसानों की बात यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव एलाइंस की तरफ से उठायी गई थी और वामपंथी दलों के दबाव में किसानों की बात बजट में कही गई है। इससे पहले हमेशा सैंसेक्स की बात होती थी, बाजार गिरने पर वित्त मंत्री का बयान आता था, अगर किसानों की इतनी चिंता थी, तो इसके पहले किसी ने किसानों की बात क्यों नहीं कही। इनक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम इस बजट में नहीं उठाया गया है। कृषि विकास 3.8 प्रतिशत होता था, यह वहां से 2.6 प्रतिशत पर आ गई है, यह आपके आंकड़े कहते हैं। क्रूड ऑयल, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और खाद्यान्न के दाम, इस लोक-लुभावन बजट के बाद, जनता के हृदय के तार को बजाकर छेड़ने वाले तार और इन्फ्लेशन कई गुणा बढ़ा है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह वृंदा जी नहीं कह रही हैं, यह मुरली मनोहर जोशी नहीं कह रहे हैं, यह आपका इकोनोमिक सर्वे कह रहा है। इकोनोमिक सर्वे के अनुसार आर्थिक विकास आने वाले दिनों में इससे सीधे तरीके से प्रभावित होगा। क्या शानदार कीर्तिमान आपका है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को आपने पांच साल में एक-दो- बार नहीं, सिर्फ सात बार बढ़ा दिया है, आठ बार बढ़ा दिया है वृंदा जी, हमको सही कर रही हैं। टैक्स संग्रह खूब हुआ है, टैक्स से खजाना भर गया है, लेकिन इसका लाभांश आम आदमी को नहीं मिला है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

मैं यह कह चुका हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण कर्ज राहत के लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी, चार परसेंट पर लोन लेने की बात नहीं कही गयी है और रूरल इन्फ्रास्ट्रांक्चर की पूरी तरह से अवहेलना की गयी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो हैक्टेयर से अधिक जिनकी जमीन होगी, उनको कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं, यहां पर श्रीमती सुप्रिया सुले जी बैठी हैं, शरद पवार जी की पुत्री और हमारी बहन, वह बतायेंगी कि विदर्भ में किसी किसान को लाभ नहीं पहुंचेगा, जो कॉटन का किसान है। हम अपने बुंदेलखंड की बात जानते हैं, उसको आपके बजट की इस घोषणा से कोई लाभ नहीं मिलेगा और आन्ध्र प्रदेश के साथ भी यहां बतायेंगे कि रायलसीमा में भी इसका कोई लाभ नहीं होगा, आप इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

महोदय, पहले ग्रोथ रेट 9.6 परसेंट थी, अब 8.7 परसेंट हो गई है। इसका सीधा-सीधा कारण यह है कि कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और सबसे विलक्षण बात यह है कि मैं स्टेंडिंग कमेटी हैल्थ का चेयरमैन हूं, इसलिए मुझे सीधी जानकारी है। मैंने 'हिन्दू' में श्रीमती वृंदा कारत जी का एक लेख भी पढ़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र का बिल्कुल प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय चिदम्बरम जी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इन्होंने देश को बीमार बनाने की पूरी योजना बना दी है। चाहे पूरे देश बीमार रहे, लेकिन स्वास्थ्य की इतनी अवहेलना हुई, आप पूछिए मत। हम वृंदा कारत जी के लेख में उद्धत इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हैं। कुल बजट का बहुत मामूली-इन्होंने आंसू पोंछने का काम भी नहीं किया है। इसका हाल क्या है, आज ज़रा सुनिए। महोदय, युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2006 में भारत का स्थान 126 था, 2007 में इसका स्थान 128 हो गया है। यह आंकड़ा बनाया गया है कि दुनिया के 177 देशों में 2006 में भारत का स्थान 126 पर था और बाद में 128 पर चला गया है और बोलीविया, वियतनाम और मंगोलिया आदि देश हम से बेहतर हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर है अर्थात् विश्वव्यापी भुखमरी संगठन में हम 94वें स्थान पर हैं। दुनिया में इथियोपिया को भुखमरी के लिए अव्वल दर्जे का देश माना जाता है, हम उससे भी पीछे हैं। हमारे लिए यह शर्म की बात है और हम लोक लुभावन बजट बना रहे हैं। शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए भी खूब राजनीति हो रही है। कांग्रेस संदेश में एक लेख आया है, हम डा॰ मनमोहन सिंह जी का बड़ा आदर करते

4.00 P.M.

हैं। उस लेख में यह है कि हम अगला प्रधान मंत्री दलित का देंगे। बजट की तरह, यह भी एक नारा दे दिया है, लेकिन शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए पूरे बजट में केवल 6 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि इनकी जनसंख्या अनुपात में 16 परसेंट से 8 परसेंट है।

महोदय, अभी फूड सिक्योरिटी पर ध्यान देने की बात की गई है। मैं जनार्दन पुजारी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। शायद वे रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने सच बोलने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने बहुत बहादुरी से कहा है और कल हमने वाणिज्य मंत्री जी का तमाशा भी देखा है। यह स्पेशल इकनोमिक जोन है या स्पेशल एक्सप्लॉएटेशन जोन है? हरियाणा और पंजाब में फूड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मिलती थी। इन्होंने पूरा हरियाणा बेच दिया है। अब वहां पर अम्बानी के बड़े-बुड़े मॉल्स लगेंगे, जिसके लिए काफी हैक्टेयर जमीन दे दी गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके कांग्रेस के पूर्व भजन लाल जैसे तमाम लोग कह रहे हैं। वे स्पेशल एक्सप्लॉएटेशन जोन के विरोध में आपका दल छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। जब तक आप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि इस पर कोई कंट्रोल हो सकेगा। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा और शरद पवार जी से अनुरोध करूंगा कि आस्ट्रेलियन व्हीट बोट से सड़ा हुआ गेहूं मंगवाकर मत खिलवाइए और फूड सिक्योरिटी को ठीक करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा, यहां पर मणि शंकर अय्यर जी बैठे हुए हैं, उनको ग्राम की चिंता बहुत है, बहुत लेख लिख रहे हैं। स्पोर्ट्स से ज्यादा वे ग्राम विकास की चिंता ज्यादा करते हैं। वे पंचायत मिनिस्टर हैं, लेकिन ग्राम की चिंता करते हैं, पंचायत की चिंता करते हैं। वे पंचायत को प्रधान मंत्री कार्यालय से जोड़ने की चिंता करते हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इनके जैसा आदमी कृषि मंत्री बन जाए और स्पोर्ट्स मिनिस्टर शरद जी बन जाएं, तो शायद देश का भला हो जाए। ...(व्यवधान)...

पंचायती राज मंत्री, युवक, कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): बहुत, बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मणि शंकर जी आपके शुभचिंतक हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए हमारे साथी कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिकरण हुआ है, मैं इससे असहमत हूं। देखिए, मुसलमानों के लिए कम काम हुआ है। इस बजट में जो एलोकेशन हुआ है, यह कम हुआ है। आप सच्चर और श्रीकृष्ण आयोग बनाते हैं, यह तो आपकी पुरानी अदा है कि कोई आयोग बना देते हैं। आप स्वामीनाथन आयोग बनाते हैं और उसे ठंडे बस्ते में रखते हैं, तो सच्चर और श्रीकृष्ण आयोग भी ठंडे बस्ते में हैं। आपके माइनोरिटीज मंत्री श्री अब्दुल रहमान अन्तुले ने अलीगढ़ की एक सभा में कहा कि मुसलमानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हमारी पार्टी है, क्योंकि हम ज्यादा समय तक पावर में रहे हैं। जब आपके माइनॉरिटीज अफेयर्स के मंत्री को मैं उद्धत कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अलीगढ़ में जो बयान दिया है, तो बराय करम मुसलमानों के लिए चिदम्बरम साहब, थोड़ा ज्यादा पैसा निकालिए, यह हमारा अनुरोध है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अखबारी कागज जो है, टैक्स और नॉलेज लाना बंद करें और उनके ऊपर नियंत्रण करना कम करें। जो आप विज्ञापन पर अपनी दर लगाते हैं, वह कम करें और इसको ठीक करें। क्योंकि आज मैंने लोकशाही को हाज़िर-नाज़िर जानकर सच बोलने और सच के सिवा कुछ नहीं बोलने का संकल्प लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बुराई नहीं हैं। इस बजट में मिडल क्लास के लिए टैक्स सीलिंग बढ़ाई गई है और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए राहत दी गई है, इसके लिए मैं प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय चिदम्बरम् जी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हाकिम हैं, पता नहीं क्या कर दें, तीसरी आंख खोल दें। मैं चिदम्बरम जी से बहुत प्यार और आदर से कहना चाहूंगा–

चाहे जितना भी हो दुश्वार, कहा जाता है

सच वही है जो सरेदार कहा जाता है।

यह अलग बात है कि मुझको मेरा हक न मिले।

वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, this being the last Budget of this Government, the last full Budget of this Government, it was important for the hon. Finance Minister to ensure adequate allocations to fulfil the assurances of the Common Minimum Programme. In comparison, I would say, in certain important areas such as the social sector spending, the debt waiver scheme, the raising off of ceiling and giving some relief to middle classes on taxes, undoubtedly, this Budget is ahead of the Budgets of the NDA Government. But the point is, in the last year of this Government, do we still have to go by comparisons with the dismal record of the NDA Government? The point is that with the opportunities that the Finance Minister had, of buoyant revenues, healthy foreign exchange reserves, huge dividends from the public sector enterprises, he could have put this increased revenue where the CMP is. And in that context, I would say that the measures proposed by this Budget are half-hearted. They are tokenist and they, most definitely, do not fulfil the assurances of the Common Minimum Programme.

Right at the outset, I would like to state that I think the major failure of this Government is the failure on the price-rise front. The people of this country, who have been suffering as a result of inflation rates, hoped that the Finance Minister would take certain concrete measures to control this price rise. But he has not, He has failed. And I do not know whether, at the end of his term, Mr. P. Chidambaram would be known as 'Mr. Price-rise Chidambaram'. And Mr. Price-rise Chidambaram, as he knows only too well, may have to pay a very heavy price. I would also like to say, Sir, that a lot has been made of the gross budgetary support, and it is said that this time it is over Rs. 38,000 crores. But if you look at it in terms of the nominal GDP, it is actually very much the same. There is not the kind of increase that we had expected. Particularly, as my colleagues have spoken earlier, at a time when agriculture growth is just 2.6 per cent, at a time when it is so clear that our economy is beset with the most obscene kind of inequalities, what was required was a massive injection of funds into the economy. But he has not done it. As far as the agricultural sector is concerned, Sir—my colleague is going to speak on it and I am not going into the details—I would like to welcome on behalf of my party the debt waiver, it is good. It is necessary and it is equally necessary to widen the eligibility conditions of beneficiaries through a realistic inclusion of farmers in dry lands. There are many conditions which have been put. I think, those conditions are going to act as barriers if the actual spirit of this waiver is going to be implemented, and, therefore, it is necessary for the Finance Minister to take on board many suggestions which have been made in the Parliament and to widen the scale. But, I would also like to ask the Finance Minister as to why he has created all this confusion. Since this waiver is not at all reflected in the Budget papers—it is a policy decision—he could have done it any time. Now, that he is linking it with the Budget, if he is not reflecting where he is getting these Rs. 60,000 crores from, at least, he should have indicated that this is where he is going to get the money from. Why is there confusion? I saw an interview by the hon. Prime Minister in which he said—I think, hon. Finance Minister has also said it—that the Government may disinvest in PSUs to pay the bill for debt waiver for farmers. I want to make it absolutely categorically clear on the floor of this House that my Party will, strongly oppose any such move to disinvest in PSUs to pay the farmers' debt bill. Please, this is not *aam aadmi* politics. You cannot put the workers of the PSUs against the farmers in distress. This will be a travesty. We all know that a huge debt waiver, however substantial, is not going to solve the problems of the *kisan* in this country. And, if you want a *Kisan*-centric agricultural policy, you cannot depend on corporates. If you want a kisan-centric agricultural policy, you need a comprehensive approach. You would not have to go very far for it. As the previous speaker said, our esteemed

colleague, Prof. M.S. Swaminathan, has given a very clear blueprint, a roadmap as to what is required for the agriculture. I want to ask the Finance Minister, "Is he or is he not going to accept four per cent as the interest rate? Is he or is he not going to accept the price stabilisation fund recommendation?" These are some of the basic issues. Is he or is he not going to accept the demand which is being made across the board? Don't just limit the MSP to foodgrains. You have to extend the MSP if you are going to protect the farmers of this country. Don't go by WTO conditions; go by conditions of agrarian distress in India. Is he prepared to do it? So, these are some of the issues which are agitating those who are working among farmers, who are aware of the extent of agrarian distress in this country. Therefore, while welcoming the debt waiver, I would say that he has to go a much-much longer way if he actually wants to alleviate the position that farmers are facing today. Now, one of the basic issues, जो एक बुनियादी बात है, जिसे मैं इस सदन में उठाना चाहती हूं। इस बजट का जो पूरा कॉम्प्रिहैंशन है, इसका जो फ्रेमवर्क है, वह किसी नीति के अंतर्गत है। अब अगर आप वित्त मंत्री जी के भाषण को देखें, उन्होंने पैराग्राफ 9 में कहा है, ''मैं ठोस विश्वास करता हूं कि हमारी सस्टेंड प्रोग्रेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी के कारण है।'' उन्होंने कहा, "It was first ushered in by the Congress Government, and now carried forward by the UPA Government." आगे बढ़ कर उन्होंने कहा, in the following paragraph, "India has growth story, confident that high growth was sustainable. The UPA declared its intention to make growth more inclusive." अभी तक तो एक्सक्लूसिव था, अभी तक तो सबको एक्सक्लूड किया गया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने यह तो मान लिया, लेकिन, सर, सवाल एक नीति का है ...(व्यवधान)... । सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले चार सालों से भी पहले, यहां मैं एनडीए के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं यह मैंने पहले ही कहा है, लेकिन पिछले चार साल से ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ, यह मंत्र हमने सुना है। चाहे भीष्म पितामह जी ने कहा हो या द्रोणाचार्य जी ने कहा हो, लेकिन मंत्र उनका एक ही है और वह मंत्र है - रिफॉर्म। यह जो एक स्टबर्ननैस है, एक ढीठ समझ है कि अपने देश का अनुभव के आधार पर हमारी नीति का कौन सा रास्ता होना चाहिए, कौन सा पथ होना चाहिए, आप उस पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही ग्रोथ का पैर्टन है। मैं यह कहना चाहती हूं, सर, कि आप पैटर्न ऑफ ग्रोथ को देखिए, स्टैटिस्टिकल ग्रोथ को मत देखिए। सभी जानते हैं कि ग्रोथ जरूरी है, लेकिन किस प्रकार का ग्रोथ, किसके लिए ग्रोथ, किसके फायदे के लिए ग्रोथ, इस पर आप देखेंगे कि नहीं? हमने देखा है। मैंने पिछले 4 साल की बजट स्पीच पर छोटी-सी एक्सरसाइज की कि इन्क्लूसिव कब से शुरू हुआ? पहले बजट में यह नहीं था, दूसरे बजट में एस॰सी॰/एस॰टी॰ के लिए था, तीसरे बजट में शायद एक बार जिक्र हुआ, लेकिन अभी यही मंत्र है, क्यों? क्योंकि अगर आपको अनुभव है कि आम जनता को, आम आदमी को इस ग्रोथ रेट से एक्सक्लूड किया है, तो अगर आप मशीन को थोड़ा-सा टिंकर करके सोचेंगे कि यह इन्क्लूसिव होगा, तो यह होने वाला नहीं है। जोशी जी ने stiglitz का जिक्र किया। मैं भी करना चाहती हूं, क्योंकि stiglitz, a Nobel Prize winner, वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा समर्थक था। अगर वह मॉडेस्टली अनुभव के आधार पर अपने फ्रेमवर्क को, अपनी नीति को, बदल सकता है, तो क्या यह भारत सरकार नहीं कर सकती है, वित्त मंत्री जी नहीं कर सकते? उन्होंने कहा: GDP is a handy measure of growth, but it is not the be-all and end-all development. Growth has often been accompanied by increased poverty and sometimes even lower income for individuals in the middle. If the economic growth is not uniformly shared in the society, then, development will fail.

आप हिन्दुस्तान को इस मापदंड से देखिए। हमारी शेयरिंग का रिकॉर्ड क्या है? डिटेल्स सब जानते हैं। पिछले 10 सालों में हर 30 मिनट में एक किसान ने आत्महत्या की। हमारे साथी श्री अर्जुन सेनगुप्ता जी ने बहुत मेहनत करके वे आंकड़े निकाले। इस देख की 77 प्रतिशत जनता, 81 करोड़ जनता, 10 साल के रिफॉर्म प्रोसेस में-जो चिदम्बरम जी सर्टिफिकेट देते हैं-उस 10 साल के रिफॉर्म प्रोसेस में 20 रुपए खर्च करने वाले लोगों की

संख्या 81 करोड़ से बढ़ कर 83.6 करोड़ हो गई और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अपने जबाव में कहा, "But these are 2004-05 figures." It is correct. But is there any evidence that after 2005, these figures have gone down, these numbers have gone down. Is there any evidence? Sir, the common sense tells us, when inflation is going up, the prices of essential commodities are going up, undoubtedly, these numbers would have gone up, they would not have gone down. This is what common sense says. And, in the absence of sharing, Sir, जब बंटवारा नहीं होता है, तो क्या है? अगर हिन्दुस्तान की इकोनॉमी की जिस पृष्ठभूमि में यह बजट पेश हुआ, अगर उसको आप देखें तो जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस देश की जो सबसे बड़ी हकीकत है, वह है-असमानता। हम गर्व से कहते हैं कि इंडियन्स बड़े बिलियनेयर्स हो गए हैं। मैं तो कहती हूं कि it is obscene. I am sorry, Sir. I say that these inequalities in any modern society are nothing but obscenity. And, today, we want to flaunt that wealth, we want to show how much more wealthy we are. There are others at the bottom of the ladder, who may be more brilliant than we are, but they do not get the opportunity. These are the inequalities, which this reform process has created, not created, but intensified in India, which the Finance Minister in his Budget speech said, yes, this is the reform. So, when this is the reform process, I can tell you, Sir, you can never have inclusive growth. आप कभी भी सर्वव्यापी विकास–जो आपका नारा है–उसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप इस बजट में उन नीतियों को बदलने के लिए तैयार हैं? यह बी॰पी॰एल॰–ए॰पी॰एल॰, यह सबसे बड़ा फ्रॉड जो हिन्दुस्तान की जनता से है, आज अगर आप पैसे के रूप में बी॰पी॰एल॰ का मापदंड करें, तो एक एडल्ट के लिए महीने में 327 रुपए, एक दिन में 11 रुपए, यह बी॰पी॰एल॰ है और इस बी॰पी॰एल॰ के आधार पर आप quotas देते हैं और उन quotas के आधार पर क्या होता है? यह poverty estimates और poverty quotas मैं इस सरकार को चार्ज करती हूँ कि आप की इस रिफॉर्म पॉलिसी के आधार पर, सबसे बड़े एक्सक्लूज़न की पॉलिसीज़ के आधार पर आप कर रहे हैं और इसलिए मेरी पार्टी यह मांग करती है–पहले भी हम लोगों ने इनको कहा है, लेकिन यह नहीं माने की यह बी॰पी॰एल॰–ए॰पी॰एल॰ समाप्त करो। जो बेसिक अधिकार है इस देश की जनता का, उसको सार्वजनिक बनाओ, यह हम लोगों ने कहा है। सर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि लोग हम से पूछेंगे, You are talking about so many things. आप तो हर चीज चाहते हैं, पैसा कहां से मिलेगा आपको, कहां से आएगा पैसा? सर, मैं कहती हूँ कि आप अपने बजट पेपर्स में देखिए। हमने देखा है, चिदम्बरम जी के बजट पेपर्स में एक revenue forgone column है। अगर आप, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप ने कितने टैक्स कंसेशंस दिए? आज आप का effective tax rate corporates पर 20 प्रतिशत है। आप बहुत गर्व से कहते हो कि 19 से 20 हो गया है। ठीक है, very good. लेकिन है 20 प्रतिशत जहां 33 प्रतिशत का टैक्स रेट है। आप ने इतनी टैक्स कंसेशन दी, आप खुश हैं कि मेरे रेवेन्यूज बढ़ गए। हम भी खुश हैं कि आपके रेवेन्यूज बढ़ गए, लेकिन रेवेन्यूज बढ़े क्योंकि प्रोफिट्स बढ़े। आप और भी ले सकते थे, लेकिन मैं आपसे कहती हूं revenue forgone, सर दो साल में, कॉर्पोरेट्स के प्रति इतने उदार दिल हैं हमारे वित्त मंत्री जी कि उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स छूट दे दी। बाकी छोड़िए, मैं टैक्स एरियर्स की बात ही नहीं कर रही हूं, सिर्फ revenue forgone, 1 लाख करोड़ रुपया और पैसे नहीं हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, हमने कहा आप कम-से-कम उनको न्यूनतम वेतन दीजिए, महंगाई के लिए कुछ दीजिए, उन्हें कुछ पेंशन बेनिफिट्स दीजिए। सर, 20 से 25 साल तक एक औरत, आई॰सी॰डी॰एस॰ वर्कर सब कुछ करती है। आप ने 1 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए 500 करोड़ और आप inclusive growth की बात करेंगे? मैं पूछती हूं कि आप से, सर, आपका health programme है, आशा बोलकर हैल्थ वर्कर्स गांव-गांव में उनसे मिलने गयी हूं। यह आपका इकॉनोमिक सर्वे बताता है कि कितना-कितना काम उनको करना पड़ता है, लेकिन उनकी औसतन आमदनी 800 रुपया है, सिर्फ 800 रुपया। 1 लाख करोड़ और 800 रुपया, 500 रुपया आप न्यूनतम वेतन नहीं दे सकते। सर, मैं कहती हूँ कि यह पॉलिसी का सवाल है और पॉलिसी के सवाल पर चूंकि यह बजट उसी

new liberal framework में है, यहां तक यह आपका एफ॰आर॰बी॰एम॰ एक्ट, क्या है यह एफ॰आर॰बी॰एम॰ एक्ट, किसने तय किया है एफ॰आर॰बी॰एम॰ एक्ट, क्यों तय हुआ? मुझे पता है एन॰डी॰ए॰ ने तय किया। मैं कहती हूं 3 परसेंट ऑफ जी॰डी॰पी॰ आप deficit कर सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जो deficit पर इतना ध्यान रखते हैं। अपने fiscal fundamentalist की constituency, जनता की constituency, fiscal conservatism की constituency, fiscal conservatism की constituency 3 परसेंट deficit पर भी वह नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि खर्च ज्यादा हो जाएगा और वह 2.5 पर रुक गए। सर, यह उनकी पॉलिसी है।

सर, मैं वापस महंगाई पर आना चाहती हूं। मैं क्यों आना चाहती हूं? वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और हमारे प्लानिंग कमीशन के चैयरमेन का वक्तव्य हमने सुना। उन सब की एक समझ है, global prices are rising, wheat by 88 percent, he says in budget. यह 15 प्रतिशत और 88 प्रतिशत बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो आपको वोट दिया है। आपको वोट दिया, ग्लोबल प्राइसेस से हिंदुस्तान को बचाने के लिए आपको वोट दिया। अगर ग्लोबल प्राइसेस ही चलनी है, तो आप फार्मर्स को ग्लोबल प्राइसेस क्यों नहीं दे रहे हैं? यू॰एस॰ की इतनी बड़ी subsidy है अपने फार्मर्स के लिए। आज भी एक गाय की सब्सिडी यूरोपियन यूनियन में इतनी ज्यादा है, वह ग्लोबल सब्सिडी आप दीजिए। आप क्यों selective हैं? जनता की जेब से जब निकालना है तो ग्लोबल प्राइसेस, लेकिन किसानों के लिए कोई ग्लोबल प्राइसेस नहीं। सर, आज आप सोचिए कि जहां ग्लोबल प्राइसेस का manipulation बड़े-बड़े व्यापारी और एम॰एन॰सीज॰ कर रही हैं, वहां हमारे वित्त मंत्री जी और हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसे वह सदन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एफ॰डी॰आई॰ को फारवर्ड कांट्रैक्ट ट्रेड में लाने की इजाजत दें। सर, मैं आज इस सदन में खुलकर कहती हूं कि अगर यह ऑर्डिनेंस आता है तो हमारी पार्टी इसके खिलाफ वोट देगी क्योंकि हम इस प्रकार के कानून को कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दस साल पहले का एक बयान सुनाना चाहती हूं- "Any Government worth its salt, any Government which is concerned about the poor of this country, any Government which has some heart must place inflation control number one on the agenda. This Government has failed to do that. Your first duty was to tame inflation. You have failed in that duty. We, therefore, charge you with betraying the confidence of the people of India and in immiserising and impoverishing them."

Sir, suppose I do a ''कौन बनेगा करोड़पति'', जया जी और मैं पूछती हूं ए, बी, सी, डी, कि किसने यह कहा? यह किसका बयान है? अगर मैं सदन से आपके द्वारा अपने साथियों से पूछूं कि यह बयान किसका है, तो सदन हैरान होगा। यह बयान है शिवगंगा के एम॰पी॰ का, जब वह अपोजीशन में बैठते थे, मिस्टर चिदम्बरम का। I leave it to his conscience whether he applies those same words to himself. I will leave it to his conscience. But the fact of the matter is that the words which apply to one Government, when he was in the Opposition, whether those words apply to his own regime when he is the Finance Minister. Sir, the people of this country will certainly ask Mr. Chidambaram. When Mr. Chidambaram says, "What are the steps? I am doing my best " I saw yesterday, he said, "I am doing my best."

I say that three issues are there. One is the PDS. Strengthen the PDS. आपने पीडीएस राशन प्रणाली को चौपट कर दिया, समाप्त कर दिया। आपने पूरी फूड सबसिडी लगभग 30 हजार करोड़ से, मतलब 3.5 परसेंट बढ़ाई मगर एक भी अंत्योदय परिवार, एक भी बीपीएल परिवार को नहीं जोड़ा, सर। हमारा देश malnutrition का सबसे बड़ा शिकार है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी malnourished हमारे देश में है। But not a single family has been included in the PDS. What is this? I say to you, Sir, that this is nothing but sheer injustice to the people of this country. Therefore, we demand from this Government, from the Finance Minister, and from this Budget, please get away from

these quotas and include a substantial section of the APL into the BPL category. Without doing that, you will never have an 'inclusive growth.'

What have you done in the name of shortages? Sir, in the last three years, 139 lakh tonnes of foodgrains, in food allocation to the rationing system, has been cut. I know that there are friends who will say that what to do, off-take is low. Yes, off-take is low, when there is not much difference between market prices and ration prices. When there is a huge difference as of now, undoubtedly, people will go to the ration shops. I say that you need reform in the ration system. But, for these types of allocations, which have been cut, we demand from the Government to reverse allocation cuts.

The second step is on petrol and diesel. They have hiked it eight times! आठ बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई। मैं मानती हूं, सर, सौ डॉलर बैरल अगर किसी सरकार को देना है, तो निश्चित रूप से हम सब को चिंता होगी कि यह पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जैसे यह दाम बढ़ रहा था, वैसे सरकार का खजाना भी भर रहा था एक्साइज डयूटी, कस्टम डयूटी से। अगर दाम बढ़ रहा है और जनता की जरूरत है, तो आप अपने खजाने को तो कम करो, लेकिन, मेरे पास मुरली देवड़ा जी की फिगर्स हैं, जो मैंने उनसे मांगी थी और उन्होंने दी है,यह 35 हजार करोड़ रुपया अधिक, आज 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए सरकार की आमदनी है। एक्साइज डयूटी स्टेट और सेंट्रल दोनों की है, लेकिन इसमें अधिकतर हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है।

सर, अभी जब आठवीं बार पेट्रोल, डीजल का भाव बढ़ा, तो उसमें लगभग 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसमें 35 हजार करोड़ रुपए उनकी एक्साइज ड्यूटी और इमपोर्ट ड्यूटी है। ठीक है *ad- valorem* tax की जो हमारी मांग थी, उसको हटा दिया, मैं स्वागत करती हूं, लेकिन that is revenue neutral. So, decreases the prices, reverse the price rise. Even the Economic Survey has said so. 'इकानॉमिक सर्वे' ने कहा कि पैट्रोल-डीजल प्राइस राइज़ के कारण cascading impact हुआ।

दूसरी मेरी मांग है, प्राइस राइज़ के बारे में, जो मैं इस सदन में रखना चाहती हूं अपनी पार्टी की ओर से कि इस प्राइस राइज़ को वापिस लो, एक्साइज़ ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी का जो तुम्हारा टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको बदलो और आम जनता को राहत दो। यह हम लोगों ने दी।

तीसरी बात है, सर, प्रिक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में। इम्पोर्ट और प्रिक्योरमेंट में बहुत बड़ा घपला है, मैं कहना चाहती हूं घपला है। मैं मानती हूं प्रॉडक्शन करना है, कौन मना करेगा कि हिन्दुस्तान की प्रॉडक्शन न बढ़े। हम सब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की प्रॉडक्शन बढ़े, लेकिन आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऐसी थी, आपने commercial crops को इनकरेज किया, फूड ग्रेन की जमीन को डाइवर्ट करने के लिए export-oriented agriculture के नाम पर आपने किया, लेकिन आज आप किसानों को दोष दे रहे हैं कि आप हमें ग्रेन नहीं दे रहे। इसलिए, मैं कहती हूं कि जो प्राइवेट प्रिक्योरमेंट हो रहा है, उसको खत्म करो। सरकार उचित दाम देकर वह प्रिक्योरमेंट करे।

अब, सर, मैं employment पर आती हूं, क्योंकि आज देश के अंदर बेरोजगारी की सबसे बड़ी काली छाया छाई है। Sir, I want to just read one quotation. You are familiar with Karl Marx, the great revolutionary. Maybe, I don't know what your opinion is *vis-a-vis* his writings. But, I just want to say what he said about the unemployed, "There is a forest of arms reaching for employment. The forest gets thicker but the arm gets thinner." That is the picture of India today. हम देखते हैं, 'इकानॉमिक सर्वे' के सारे आंकड़े हैं। Employment rate 3% से नीचे है और

uneployment rate, अगर आप NSSO के quinquennial sample survey को देखें तो करंट डेली बेसिस का उनका जो एक आंकड़ा है, वह बढ़कर 8.30 हो गया है और उसमें सबसे अधिक शिकार हुई हैं हमारी महिलाएं। मैं जानती हूं, सर, employment generate करने के लिए जहां जॉबलैस ग्रोथ का paradigm चल रहा है, कठिन काम है। REGA बहुत अच्छा है और हमने स्वागत किया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि दो साल के बाद वित्त मंत्री जी ने REGA को praise किया। मैं जानती हूं REGA को लागू करने के लिए, लाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं बताना चाहती हूं इस सदन को, आज वित्त मंत्री जी कहते हैं, SC/ST women are benefiting, but, I don't know where the Finance Minister was when we were informed, "No, no, it is not going to be universal. वह सार्वजनिक नहीं हो सकता, केवल BPL होगा।" हम लड़े, हमने BPL हटवाया। हमने कहा कि switch-off clause नहीं होगा। हम लड़े, वह switch-off clause खत्म हुआ। आज भी मैं आपको कहती हूं कि हमारी लड़ाई के कारण महिलाओं का नाम उसमें दर्ज हुआ। हमने कहा, पैसे दीजिए। वित्त मंत्री जी कहते हैं, There is nothing. हमारे साथी श्री जनार्दन पुजारी जी ने कहा, We will always give money. You will always given money! Do you know even today and I say this, in the Finance Minister's own constituency, मैं उनके DM से मिली और उन्होंने कहा कि पैसे को कम से कम डेढ़ महीना, दो महीना लगता है पाइपलाइन में जितने shelf of projects हैं, उनको लागू करने के लिए पैसा दीजिए, लेकिन पता चला कि पैसा देने में जो शर्तें हैं, उनके कारण पैसा आता नहीं है और फिर स्टेट को कहा जाता है कि आप बेरोजगारी भत्ता दो। मैं उस पक्ष में हूं कि बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, लेकिन समय पर अगर पैसा नहीं दिया जाएगा, तो बहुत कठिन मामला होगा, यह भी मैं कहना चाहती हूं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उनका क्या attitude है work norms पर, जो इतने impossible work norms हैं rural development में REGA में कि 8 घंटे, 7 घंटे काम करने के बाद आप न्यूनतम वेतन तक पहुंच नहीं सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूं वित्त मंत्री जी से कि क्या आप हमारा समर्थन करेंगे, जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यह पीस रेट से टाइम रेट होना चाहिए, क्योंकि इस रूप में एक कमजोर काम नहीं कर सकती है, क्या आप हमारा समर्थन करेंगे?

सर, आज हम लोगों ने देखा, employment का सवाल, skill development पर जोर दिया, हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। सर, आज सुबह हमने अखबारों में पढ़ा कि Free Trade Agreement हुआ है श्रीलंका और बंगला देश के साथ। Garment और textile industries में already जो global recessionary trends हैं, वह already हमें प्रभावित कर रहा है। अब Free Trade हो रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि Triupur Hosiery Industry में जो चालीस हजार लोग already बेरोजगार हो चुके हैं और इन ग्लोबल recessionary trend से हिन्दुस्तान की economy को insulate करने के लिए, हमारे रोजगार बेरोजगार न बनें, उसके लिए वह क्या उपाय ढूंढ रहे हैं? यह मैं जानना चाहती हूं। मैं इम्प्लॉयमेंट के बारे में एक और बात कहना चाहती हूं, अभी पता चला है, Private sector is a magic word for everything. The market is going to solve all our problems. सर, Economic Survey में जो आंकड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हुए हैं, सर्विस सेक्टर में हुए हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर में कम हुए हैं, लेकिन कुछ हुए हैं, लेकिन जितने बेराजेगार हैं, उतने नहीं हुए हैं। आप जॉब्स के लिए केवल प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करेंगे, जब कि यह जॉबलेस है। मैं यह कहना चाहती हूं, What about your public sector? आप पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि इस समय पब्लिक सेक्टर की रिजर्व्स चार लाख करोड़ से ऊपर है। एक ही साल के अंदर इसमें सोलह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, वृद्धि हुई है। जो पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, क्या आप उसका अचार डालेंगे? वह जो सरप्लस है, उस सरप्लस को इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कहती हूं कि हमारे जैसे economy में जब तक पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

सर, मैं, Unorganised Sector पर कुछ कहना चाहती हूं। मैं श्री अर्जुन सेनगुप्ता जी को बधाई देती हूं। उन्ह मेहनत के कारण आज देश भर में एक स्पष्ट एजेंडा इनकी रिपोर्ट ने रेखांकित किया है आज 37 करोड़ लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं। इन्होंने दो कानून की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए फण्ड्स चाहिए। सर, कितनी दुख की बात है कि वह 37 करोड़ जनता, जो इस देश की रीढ़ है, ये ग्रोथ रेट की बात करते हैं, पर इनकी ग्रोथ केवल एक है और वह है गरीबी की ग्रोथ। उस गरीबी की ग्रोथ को रुकवाने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी क्या कहते हैं? मैं कहती हूं, जो Comprehensive Scheme है, वह कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि बीमा योजना 39:39 ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, please. Please don't disturb.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैं कहना चाहती हूं, उन्होंने पिछली साल कहा कि हम सत्तर लाख Households को इस योजना के अंतर्गत ला रहे हैं और इसमें एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये आंकड़े सुनकर देश की गरीब जनता सोचेगी कि हमारे लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सर, वह स्कीम क्या है, जो चिप्स का पैकेट होता है, वह बाहर से इतना सुंदर लगता है, उसको खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें से आधी तो हवा निकल जाता है। इस Unorganised Sector के लिए यह क्या बीमा योजना है। I tried to find out from LIC. आज तक सत्तर लाख तो दूर रही, दो प्रदेशों ने इसको लागू किया, सोलह लाख पांच हजार परिवार अभी तक इस योजना में हैं। वित्त मंत्री जी, आप स्टेट फंड के साथ बहुत उदार हैं। आप कहते हैं कि स्टेट आधा देगी। आपने इसके लिए कभी स्टेट से पूछा। सर, मैं पुजारी जी का बहुत आदर करती हूं। इन्होंने कहा कि स्टेट को बहुत मिला। मैं कहती हूं कि जितनी भी सेन्ट्रल के स्कीम्स हैं, उनमें स्टेट का जो हिस्सा लगता है, क्या आपने स्टेट से इसके लिए कभी पूछा। क्या यह सेन्ट्रल का encroachment स्टेट में नहीं है? दो सौ, एक सौ रुपया स्टेट को देना हे, स्टेट के पास पैसा कहां है। रेवेन्यु मोबिलाइजेशन कहां से आएगा। आज भी फेडरल सेट-अप में सब अधिकार सेंटर के पास हैं। स्टेट को सौ रुपया देना है, स्टेट के पास पैसा नहीं है, इसलिए यह योजना फेल योजना है। मुझे पता है, अभी आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं, वहां कोई घोषणा जरूर होने वाली है आप जानते होंगे, हमारे मंत्री जी हैं, वह कह रहे हैं कि हम 38 लाख और परिवारों को इसमें जोड़ेंगे। उसको जोड़कर, कुल मिला कर 38 लाख होता है, 70 लाख तो दूर की बात है। आज वह बजट में कह रहे हैं कि एक करोड़ परिवारों को इसमें और जोड़ने जा रहे हैं। I am sorry to say that this is nothing but a complete and utter... what should I say? I don't want to use very strong words. I would say that it is a half-baked scheme which is not going to help. सर, मैं माइनॉरिटीज़ और सोशल सैक्टर पर आती हूं। मुझे बहुत दुख है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपोजिशन के जो मुख्य नेता हैं, उन्होंने "communal" शब्द इस्तेमाल किया इस बजट के लिए! मैं इसकी निंदा करती हूं मैं इसका खंडन करती हूं। मैं कहती हूं कि अगर कोई भी पार्टी आज यह कहे कि ग्रोथ होगी और आप इस बात को नज़रअंदाज करें कि माइनॉरिटी के नाम से discrimination हुआ है, इस हकीकत से अगर मुंह मोड़ना चाहते हैं, तो इस देश को आप कभी भी सुराज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह एक संकीर्ण समझ है, जिसका हम खंडन करते हैं। मेरी एक बिल्कुल विपरीत समझ है। मैंने वैं बजट पेपर्स देखें, क्या है इन बजट पेपर्स में? पांच सौ करोड़ रुपया सिर्फ अधिक! मैंने उन सारी डीटेल्ड स्कीम्स को देखा, 15 परसेंट प्राइऑरिटी सैक्टर लोन्स, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, अभी तक कितने परसेंट पर पहुंचे हैं, मैं पूछना चाहती हूं वित्त मंत्री जी से, 70 करोड़ रुपया पिछले बजट में दिया था प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए, लिखा है-केवल 9 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्यों? क्या माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स नहीं थे, जो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ सकते थे? पढ़ सकते थे, लेकिन जो जांच मैंने की, जो खबर मेरे पास है, हो सकता है वह गलत हो, आप उसको confirm कर लीजिए कि वित्त मंत्रालय से वह स्कीम पास नहीं होने के कारण वह पैसा उस साल के अंत में मिला और वहीं हुआ, Merit-cum-Means Scholarships से 2006-07 के बजट में मंत्री जी ने कहा-हम इतने करोड़ रुपया दे रहे हैं! जब हमने पता लगाया, अंतुले जी से मैंने पूछा एक क्वेश्चन राज्य सभा में, तो जवाब दिया 5 मई, 2007 को कि नहीं, उस साल में तो कुछ नहीं हुआ, इस साल 57 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। यह हालत है! तो मैं कहती हूं कि माइनॉरिटीज़ के साथ इस देश के संाधनों में जो discrimination हुआ है, निश्चित रूप से अधिकतर जो गरीब हैं, उनके लिए देना चाहिए, यह हमारी डिमांड है।

सर, महिलाओं के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत उदार हैं। उन्होंने कहा पैरा 49 में—"I confess that policy-makers often tend to forget that one-half of the population is constituted by women, and they are entitled to an equal share. Sir, in the Budget, the share of women in

total Government expenditure shows a marginal increase-there is an Institute called the CGBA; they did a very quick analysis-from 3.3 per cent to 3.6 per cent. Now I do not know whether the Finance Minister himself is equally guilty of what he has accused the many policy-makers of doing. I leave it to you to make that judgement. But I do want to say two things. For Anganwadi workers, I make a demand. You are talking about women. You cannot talk about women's advancement without looking after them. You have to given them pension benefits. We demand a minimum wage for them. We demand Dearness Allowance for them because they are also victims of price rise. And, as I have already mentioned, Accredited Social Health Activist (ASHA) is working for peanuts. I request the hon. Finance Minister that when he is so concerned about women-I do believe that-he should kindly do this. Sir, I welcome the gender-budgeting steps. This aggregated data is only in respect of 33 Departments. I hope that the Finance Minister will also make provisions for the Prevention of Domestic Violence Act because in the absence of money for them, the Act is not being implemented. Sir, I have just two points more; I am not going to take much time....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I just want to inform you that your party has 42 minutes, and you have taken 39 minutes. I am not stopping you, but I am only cautioning you.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I will wind up in a few minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No problem; everybody is listening.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I now come to education and health. Everyone, from all sides of the House, is very concerned about education and health. There is no partisanship here. I know everybody is deeply concerned about these. I come back to the CMP. The CMP mentions the figure of six per cent of the GDP for education. What is it? The Economic Survey calculates the total public spend on education as 2.8 per cent of the GDP. The CMP mentions, in respect of health, at least, two to three per cent. The Economic Survey mentions the figure of 1.39 per cent in 2020 in respect of health. There are areas of concern. The other very important thing is about the Sarva Shiksha Abhiyan. Sir, because I am in the Standing Committee on HRD, I know there is still a huge number of drop-outs. There is an improvement, but there is still a huge number of drop-outs and the Sarva Shiksha Abhiyan has to continue. But, what has happened in trying to shift it to the States Budget? Now, you want 60:40 ratio. What has happened? Actually, for the Sarva Shiksha Abhiyan, the allocation is Rs. 80 crores less. If you take out the NER component, you will find that it is actually Rs. 80 crore less for the Sarva Shiksha Abhiyan. I think that is very unjust to the children of this country. Now, for both the schemes, the Mid-Day Meal Scheme and the Sarva Shiksha Abhiyan, I want to say that the Government levies an education cess for these schemes. That is very good. The people of this country have supported it. हमारे लोग कहते हैं कि हम जेब से पैसे देंगे, शिक्षा बढ़ाओ, स्वास्थ्य बढ़ाओ। 2,400 करोड़ रुपया एक साल में education cess में आया। अब अगर आप मिड-डे मील स्कीम्स और सर्व शिक्षा अभियान को जोड़कर देखेंगे तो सिर्फ 14 सौ करोड़ है। आपकी जेब में, 2,400 करोड़ आया और आपने एडिश्नल खर्च किया-1400 करोड़। I think this is very unfair. Then, where is the Right to Education Bill? I hope it will be brought forward with allocation. On health allocations, I just want to say two words; and firstly about priortisation. Now, we are all worried about AIDS. Of course, we want AIDS to be controlled. मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हमारे देश में क्या केवल एड्स के लिए खर्चा है। एड्स के लिए 274 करोड़ रुपए बढ़ा दिए और पूरा जो National Disease Control Programme है, उस पूरे प्रोग्राम के लिए केवल

186 करोड़ रुपया बढ़ाया है। यह क्या प्राइवेटाइज़ेशन है? मैं नहीं जानती कि यह क्या समझ है कि प्राइवेट अस्पतालों को आपने पूरी छूट दी। आपने कहा कि हम आपको टैक्स में कंसेशंस देंगे। लूटो। प्राइवेट अस्पताल आज भी गरीबों को नहीं लेते हैं। किसी गरीब से आप पूछो। कोई शख्स सरकारी जमीन लेते हैं, लेकिन गरीब का दाखिला नहीं होता है। आप देखिए कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीटयूट के बजट में कटौती है। क्यों? पब्लिक हेल्थ अस्पतालों के लिए क्यों कटौती है? मतलब, बाकियों के लिए कटौती नहीं है, लेकिन increase भी नहीं है। तो यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं मानती हूं, कि यह प्राइवेट-प्राइवेट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट की प्राइवेट-प्राइवेट पार्टनरशिप बड़े अस्पताल वालों के साथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं पब्लिक हेल्थ के लिए हूं। **(Time-bell)** Sir, please I am just finishing.

Sir, what about disability? I want to remind the Finance Minister that, in 2006-07, he had said that we were incentivising the private' sector; we were giving notionally so many hundreds of crores of rupees, he had said in the Budget. I want to ask him: how many differently-abled persons have been given employment in the public sector? How much money has the Finance Minister spent? I want to know this. I am asking this question specifically because I know, Sir, the Government has a policy of 3 per cent reservation for the differently-abled people, but no Government department, no public sector unit implements it. Incentivise your public sector to do it, and leave the private sector. That is my point.

Lastly, the tiger has found some mention, some attention, some kind attention, of the Finance Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is very good.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Not at all good, Sir. Not at all good, Sir. I say this is the wrong kind of attention. Raising one more armed force, with an allocation of Rs. 50 crores! Why? Is there a dearth of guns in this country in the hands of the Police and the Forest Department? If you give them more guns, who are they going to use those guns against? Are they going to use those guns against poachers and smugglers? If they wanted to use the guns, if they wanted to use the laws, if they wanted to use the jails, there was nothing stopping them. And, now for some symbolic thing, you want to give the message, all tribals are going to be now targeted by this. I oppose this kind of a scheme. I request the Finance Minister that if there anything is populist in this Budget, it is the populism for some wildlife fundamentalist which should not find a place in the Budget. Sir, I just want to ask the Finance Minister one question. Now, energy security, we have heard so much about it. Sir, the whole Government is concerned about the energy security. But, if you look at the finances of the Atomic Energy Department, you will be very, very surprised, to find, Sir, that apart from the money not being spent, there is, actually a cut in the Budget. I don't know what this actually means; what message is being sent. If this is the commitment for nuclear energy, it is a strange way to do it. Sir, the Finance Minister has described himself, about in a lighter vein, that he is a very lucky Finance Minister. Sir, I wish him more Luck, but I would like to give a last word of caution that if he wants luck with the people, don't depend on lady luck, but, change or reverse your policies, then, may be, you will find favour with the people of this country. Thank you, Sir.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the General Budget. Sir, I start with these words, 'three cheers for the Finance Minister and the Government for this Budget'. This Budget is for farmers; this Budget is for workers; this Budget is for the *aam aadmi,* for the middle class, for investors, for women, for old people, etc. ....*(interruptions)*.... अमर सिंह जी, एक मिनट रुक जाइये। मैंने अमर सिंह जी को इसलिए रोका कि अमर सिंह जी ने कहा कि यह पोलिटिकल बजट

है, इलेक्शन बजट है। मैं मानता हूं कि यह इलेक्शन बजट है। In a democratic set-up, Budgets are meant for *aam aadmi.* And if anything is meant for the *aam aadmi,* it is good for elections. His worry is, if the UPA has given a Budget for the *aam aadmi,* election Budget, naturally people in the Opposition will be worried about it. मैं इतना ही आपको कहना चहाता हूँ कि

श्री अमर सिंह: सर, मैं ही वरीड नहीं हूं, इनके वामपंथी साथी भी वरीड हैं। ....(व्यवधान)....

श्री रुद्रनारायण पाणि: संतोष जी, चुनाव कब करवा रहे हो, कृपया बतायेंगे क्या?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, nobody in his clear senses can say that it is not a good Budget, in general, and it is not for the masses. If you see the record, Sir, I congratulate the hon. Finance Minister—I will just talk in general terms—for bringing down the revenue deficit, year after year. As a result of the kind of policies which are being taken up by the Finance Ministry under Dr. Manmohan Singh's Prime Ministership, and under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, the revenue deficit which was 1.9 per cent in 2006-07, came down to 1.5 per cent in 2007-08, and now, it is just 1 per cent in 2008-09. Similarly, Sir, if you see the fiscal deficit, you will find that it has gone down from 3.5 per cent in 2006-07, it was Rs. 1,42,573 crores, to 3.3 per cent in 2007-08. In fact, it came down to 3.1 per cent in the final revised estimates of 2007-08, and in the year 2008-09, as per the estimates, it is 2.5 per cent. This kind of good tax planning, good Budget planning has brought down the revenue deficit and the fiscal deficit at a level which is acceptable in any financial norms anywhere in the world. I am sure, the plan of the Finance Minister is to bring the deficit to the zero per cent level. Very shortly, maybe, in a couple of years, we might be able to achieve it. Sir, Brindaji has been talking about different aspects of the Budget. I would take up some of the points. Some of them I agree with and on some of them I differ. It should always happen like that. But, one of the reasons for this deficit is that 21 per cent of the Budget amount goes towards paying interest alone. That is where we have to find ways as to how we can decrease the interest burden. Obviously, whatever is saved from the interest burden is used for developmental work for the benefit of the poor people; 31 per cent, the largest part, is transferred to the States and the U.Ts and that is quite satisfactory.

Sir, in 1997-98, at the time of the NDA Government, it was Rs. 79,720 crores, whereas in 2008-09, it is Rs. 3,28,422 crores which is being transferred to the States and the UTs. Brindaji has mentioned about the tax on industries. Sir, the country has seen that there was a tax regime on industry which was as high as 67 per cent. In fact, the personal tax was as high as more than 100 per cent. But what was the collection? The more you increase the tax rates, the more the avoidance of tax. The total collection was much less. The moment you started bringing it down to a realistic level of taxation—that is, 30 per cent or 30 per cent plus 10 per cent of surcharge, it comes to 33 per cent or so—rather, there is a scope for further reduction. If you reduce it further, I think, there would be better collection and better compliance. This is a human nature. People do not want to pay taxes. But, if it is at a realistic level, then people would be willing to pay the tax because tax avoidance would become less remunerative. I think, Brindaji does not want to listen to this but I do not mind. Probably, it does not suit her to listen to what I have already explained. I think, some day, I will have to personally discuss with her.

Sir, I would like to mention here the kind of Indian growth story and what has happened during the last few years after this Government has come into power in 2004. In 2004, the agricultural growth was 7.9 per cent. In 2005-06, within one year, the growth became

11.5 per cent and in 2006-07, it is 10.4 per cent. With regard to manufacturing, in 2005-06, it is 25.6 per cent, and in 2006-07, it is 17.9 per cent. About electricity, in 2004-05, it was minus growth of 8.3 per cent with the NDA Government. In 2005-06, the growth was 28 per cent. In 2006-07, it was 8 per cent. Sir, in Railways, there has been fantastic growth. It was 3.4 per cent in 2004-05, in 2005-06 it was 9.4 per cent and in 2006-07, it was 14.2 per cent. These are only the figures, which I wanted to give so that Brindaji can know that growth has taken place ...*(Interruptions)*... No, you did not say but I just wanted to tell you for your knowledge. If it is already known to you it is well and good. ...*(Interruptions)*... When you talked about more tax on the industries, what I have stated on that you have not listened that, unfortunately. This is, I will repeat in one or two sentences, more taxes less compliance, less taxes more compliance. This is what you have to understand. How many industries were willing to pay tax? ...*(Interruptions)*... This is human psychology that if you want to charge 67 per cent, if you want to charge 103 per cent personal tax, naturally people will avoid it. ...*(Interruptions)*... So, I am only trying to tell you that this is a practical thing. You can charge whatever you like, if you get a chance to charge at any time in life. If your party can get a chance, you can do that. If you want to destroy the economy, you can do that. But this is my opinion; you can have a different opinion. I do not mind your opinion. Sir, if you just see the tax revenue—corporation tax, in 2007-08, it was Rs. 1,86,125 crores which increased to Rs. 2,26,361 crores in 2008-09; taxes on income, from Rs. 1,18,320 crores increased to Rs. 1,38,314 crores, Customs—from Rs. 1,00,000 crore approximately to Rs. 1,18,000 crores despite the rate has been decreased so much, which is of course, for various other reasons. But the total volume of business has gone up. Union Excise Duties have increased from Rs. 1,27,947 crores to Rs. 1,37,874 crores. Service Tax, of course, is a phenomenal growth, it has come to Rs. 50,603 crores in 2007-08 and now it is Rs. 64,460 crores. In totality the total revenue is Rs. 5,85,410 crores in 2007-08 and in 2008-09, it has become Rs. 6,87,718 crores. Sir, about growing subsidies in food, fertiliser, and petroleum, as Brindaji mentioned, the rates have increased by $100 or $140 per barrel. The Excise and other taxes have increased. Deoraji has told you, we all know about it because it is on *ad-valorem* and it is not on per litre basis. But where has that increase gone? It has gone for development purposes. It is with this increase that the waiver for agriculturists will come; it is with this increase that roads will be constructed; it is with this increase subsidy will be reduced. Despite this there is so much subsidy in the petroleum products. Now you want to reduce the revenue and then you want more development work for masses, I do not know what magic wand Brindaji will have so that we can have all that development work, all these programmes for the poor people. I compliment Mr. Finance Minister for enhancing outlay for different schemes for the MRP but how do you stop the ground outcomes, which are delivered by falsifying the records. You increase the outlay but unfortunately the records are falsified at the lowest level. In the process the benefit does not reach the right people. On this delivery position you have to look into it and see how we can improve upon it. Who will not and who should not compliment you for debt waiver and debt relief for the poor farmers except your own officers like Mr. Sanjay Sinha, Chief Investment Officer, SBI Mutual Fund? He says, and, I quote, "I take the two and a half per cent deficit figures with a pinch of salt. Much of the sops and subsidies have not been factored while computing this figures. Also, Rs. 60,000 crore waiver for farmers sends out a signal that bad borrower scores over disciplined ones in this country". If we have this kind of officers who are not willing to accept the policy of the Government, Mr. Finance Minister, you only have to decided how to discipline such officers. Such officers and a few others do not realise the plight of the farmers with small holdings, sitting in their air-conditioned rooms in Delhi and Mumbai. These farmers are completely dependent on

5.00 P.M.

weather, which is absolutely under no control of mankind. You have, Sir, covered marginal farmers holding up to one hectare, and small farmers up to one to two hectares for complete waiver. Please note that one hectare in some States like Punjab, Haryana, West Bengal and Assam, or in many other fertilised areas, is equivalent to ten hectares in the State of Rajasthan where neither there is enough rainfall nor the land is fertile. I, therefore, suggest, please re-decide it. I, therefore, suggest that please re-decide the total number of hectares in different States based on fertility and rainfall because the conditions are entirely different in this country. We cannot have a single basis on which this kind of decision can be taken. I request the hon. Finance Minister, through you, Sir, that the OTS rebate of 25 per cent should be reconsidered. You may please first provide complete waiver of the interest on all NPA accounts of all the farmers; out of the balance principal, 50 per cent may be considered for rebate. There are totally eighty-nine million farmers and we have 75 million small farmers. I would like to explain this NPA of 25 per cent and what waiver you want to do. What is happening to big, big industrialists? You waive the entire interest for many, many years, and, then, whatever principal amount is left, which you give a discount of 25 or 30 or 40 or 50 per cent on that also. I have no objection. That is your policy. But, to farmers whose loans have no NPA, you just want to give 25 per cent, which includes the interest also. I don't think it is neither here nor there. You must waive the entire interest, and you reduce the balance by about 25 or 30 or 40 per cent. Then, it will have some equitable policy with the industries. Otherewise, it sounds very good. It is not really as good as you think it is. Jaitelyji is not here. He mentioned that it is a fudgy mass. Yes, it is because the entire mind of the opposition has become fudgy. They are all confused as to how this Government is able to bring out these figures, how this Government is able to bring out such a good Budget. They have nothing else to say. They are only trying to use all kinds of insinuations against this Government. I will come to that later. One more point I would like to say. When I am discussing about the minorities, Sir, when we are talking about agricultural waiver, I would like to draw your attention to the pressing need for evolving an effective mechanism to mitigate the disproportionately high social sector expenses incurred by the tea industry. As you may be aware, the production of Indian tea stood at 956 million kg. in 2006, with the total turnover of Rs. 7894 crores. The social sector cost is Rs. 8.50 per kg. of tea, amounting to over Rs. 100 crores in aggregate, which is around 10 per cent of the total turnover of the tea industry. Given the stiff competition in the international market, the high incidents of social sector cost are rapidly eroding the competitiveness of the Indian tea in the global market. Unless this issue is addressed, the industry will remain sick in all times to come. Let me inform you. Probably, you will know what is happening in South India. Mr. Chidambaram knows very well what is happening in Tamil Nadu and all over the country. Sir, tea planters are abandoning tea gardens. They are just abandoning. It is because of high cost of social sector. I am not against the social sector. But, I would only say that please bring Tea also in the agriculture sector. It is, at the moment, in the industry sector. Sir, 75-80 per cent cost is related to agriculture in tea industry. Sir, the situation 30 or 40 years ago was different. At that time, the cost of agriculture was less, but the cost of production was much more. But, after forty years, the cost of agriculture has gone up abnormally high, whereas the cost of manufacturing remains the same. There is nothing static in life. If you think that cost of agriculture has gone up in tea industry, bring it back into the agriculture sector. Nobody bars you from bringing tea into agriculture. Then, in the light of the above, we earnestly solicit your immediate intervention to ensure reimbursement of 50 per cent of social cost incurred

by tea industry for the last five years. It was not known in any part of the country that Assam Tea will be losing. Tea plantation in Assam is also losing for the last five years. North Bengal, Darjeeling and others are all losing heavily. Tell me what is happening in Silcher. They are abandoning tea gardens. You have done nothing for tea industry. You have just allotted Rs. 40 crores and that is also only for developmental work. That is all right for what you have done after a long time. But think over it and consider it as an agriculture industry where employment potential is immense. Now, small, small farmers have also come in this in different pockets of the country. It will also help them. Sir, AIC has offered insurance cover for tea and spices. Look into it. Encourage them. Some kind of insurance be given to them. Sir, the CCA has to discuss in extending Crop Insurance Scheme for tea, rubber, tobacco and spice like ginger, turmeric, chilli, pepper and cardamom. And, while discussing this issue, I request the hon. Minister to take it very seriously. Sir, even the Government of Assam, for the first time, have offered some incentives for tea industry, because they have realised that unless this is done this industry will not survive. This industry is so good for foreign exchange earning, employment generation, environment, etc. At the moment, we are talking of rise in prices of wheat, rice, pulses and then we will talk of rise in the price of tea because tea will not be available. Tea is required by maximum number of our citizens all over the country, and it will just not be available. Therefore, Sir, it should be taken very seriously as to how we go about, so that this industry becomes a bit more viable.

Now, I come to minorities. I am fully with Brindaji on this. I will, rather, go a few steps ahead of her. To begin with, we must understand 'minority' is a part of our country. They are as much our brothers and sisters as anybody else. They have fought for the freedom of the country as much as any majority community people have fought for it. They are even now as much a part of the developmental efforts as anybody else. I can tell you that in Assam, or, for that matter in any industry, where hard work is required, it is the people from the minority community who are employed there. And, wherever soft work is there, other communities are going because these poor people from the minority community don't get jobs, therefore, they go for very, very hard jobs, like, going near a furnace. This I can tell you with my own experience. At this time, when some friends from the BJP say that the Prime Minister is like Aurangzeb, I only feel sad for them. Such people do not know what Aurangzeb was; and, what our Prime Minister is. Calling Dr. Manmohan Singh 'Aurangzeb' is unimaginable for me. But these people have politicised the whole thing to an extent that they will say that it is a political Budget and they will only talk politics. They don't want that this Government should help the minorities, the poor people, becuase this will expose them. What have they done for the minorities? Brindaji mentioned about an increase of Rs. 500 crores. But that is nothing. For a large community, which comprises 15-16 per cent of the population, this increase is just meagre. The Budget proposes to contribute equity of Rs. 75 crores to the MMFDC. This is a minor increase of Rs. 12 crores. Allocations for minorities are uniformly modest. I would like to underline the words 'uniformly modest'. It has been increased, but it is modest, and modest in every programme. The increase in allocation for the pre-metric scholarship for minorities from Rs. 72 crores to Rs. 80 crores is shameful. It is not paltry—Brindaji was very kind to use the word 'paltry'—I say, it is shameful. If you want to do something do it with a large heart. Do it. It will really be helping them. Increase in allocation for the post-matric scholarship too is very small from Rs. 90 crores to Rs. 100 crores, as compared to Rs. 800 crores for the post-matric scholarship for, anyway, I would not like to compare. But Rs. 100 crore is a very little amount. And, how much has the inflation increased? If you take into consideration the inflation, then, this increase is lesser than what was required

last year. On the whole, the Budget allocations for minorities are insignificant. And, what is most striking is the absence of new welfare schemes for socially and educationally backward minorities. In the context of the Sachar Committee Report, the entire exercise of earmarking additional funds for the development of minorities would make sense only if the amounts allocated for the purpose are substantial. The major items of expenditure for minorities will be the multi-sectoral development programme for MCDs, equity for NMFDC, MAEF and pre and post-matric scholarship schemes. Education is very important. If we want to bring them into the mainstream of our society, then, we have to help them in getting educated because without education we cannot expect them to come into the mainstream. The introduction of Welfare Scheme is particularly important because the proposed Multi-sectoral Plan would cover only 30 per cent of the minority population. This would require programmes and provisions for the remaining 70 per cent.

The Prime Minister's new 15 point-programme stipulates that, wherever possible, 15 per cent of the targets and outlays under welfare schemes will be earmarked for socially and educationally backward minorities. This is why they call him Aurangzeb. He is the known honest person in the world. He is internationally well known. And, they call such a person as Aurangzeb! But this finds no mention in the budgetary documents or in the Budget Speech of the Finance Minister either in 2007-08 or 2008-09. Sir, I request the hon. Finance Minister to please look into it. It is the desire of the hon. Prime Minister. But, you have to implement it. You have to find out ways in the way you have provided Rs. 60,000 crores for the farmers. So, please do something. A large population of 15 per cent in the country should not be kept neglected.

Sir, I will quickly say this. *The Hindu Business Line* said, "This Budget is for *Jai Kisan." The Hindu* says, "Mr. Chidambaram's bonanza for the middle classes." That is why he said it is for the *aam admi.* I am not saying this. This is what the media is saying. *Forbes* said," India Budget seeks to expand social mobility." *The Asia Times* says," Something for all in India's ballot box budget." Everybody thinks that we are going for elections this year. If this were so simple, then, anybody will go on giving these bonanzas year after year. But, still people lose elections. This has not been done for elections. The UPA Government is known for social welfare; so, they are doing it. Elections will be won and this might go to their advantage. This might add to the good intentions of the Government. But, there are many more things which this Government has done for Bharat Nirman; for education for all, for water, sanitation, health, etc. This is not the one criterion on which elections will be won or lost. I want them to understand this. Don't get jittery; try to come to the ground level and start working for the poor people. Then, you can expect to win the elections. You don't want to work for the poor people and you still want to win the elections. How is it possible? Your 'India Shining' slogan is well-known. But, what happened to it? We are not talking about India Shining. We are talking about our poor people shining. We want our poor people to shine. And, if our poor people shine, we will shine.

Sir, I now come to skill development mission in PPP framework. Unfortunately, the hon. Finance Minister has just now come. When I speak good words, he is not there.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Unfortunately!

SHRI SANTOSH BAGRODIA: When I criticise, he is there. It is the unfortunate side of it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Everything is recorded. He will get it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have said, three cheers for you, Mr. Finance Minister. Sir, I started with this.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't repeat your points.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): There was no other Cabinet Minister in the other House. Now, they have come. That is why, I have come here.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will not repeat that. Sir, Mr. Finance Minister, you can recommend that we should have more than 15 per cent MPs in the Cabinet, then, we will have more Ministers available in both the Houses. Otherwise, the Finance Minister cannot run between the Lower House and the Upper House.

Sir, the planned capital expenditure as percentage of total plan expenditure is going down. From 33.85 per cent in 2004-05, it has come down to 13.81 per cent in 2008-09. It can be for various reasons. Sir, normally, the political parties give hopes and assurances that after elections, they will extend such and such facilities. Our Government under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh and the UPA Leader, Shrimati Sonia Gandhi has not bothered about elections, but it has offered this loan waiver to help the suffering peasantry and this will prove to be true by action one year before the next election. Panditji is not here. He wanted to know when elections would be held. Elections are due in May next year and they will be held in time only. This cannot be political. This is completely a concern for the poor farmers. My friends in the Opposition will never understand it. They are, of course, very jittery. This kind of achievement of our Government will expose the work done for agriculturists during its regime. Sir, our Government extends thousands of crores of rupees under 'subsidy for food and fertilizer." There is a continuous complaint that food supply in the PDS is not of proper quality and is not good for human consumption. Similarly, there are continuous complaints that the subsidy given on fertilizers does not reach the poor farmers. It leaks on the way while distributing at different levels.It is for this reason that I give a suggestion. If it is not for immediate acceptance Mr. Finance Minister, at least, this may please be debated for your kind consideration. There are 300 million people under the BPL category consisting of six crores of families. If the Government gives them directly Rs. 1,000/- per month per family, the total subsidy will amount to Rs. 72,000/- crores per year. I do not know whether it is much more than the food and fertilizer subsidy or lesser than that. This amount can be readjusted, but it appears to me that there will be no leakage with this modern transfer of wealth. A bank account can be opened up. The Minister of Finance can directly transfer this wealth to their account. Then, they will decide what kind of food they want to buy, and from which place they should buy. They will not be forced to go to the shops where they have to buy sub-human quality or very poor quality of cereals. Similarly, it is said that fertilizer is also leaked on the way. Some people say that it is being used by the industrialists; it does not reach the farmers. If this is done, this all will be over. Sir Mid-day Meal Scheme is commendable. My concern is only about the quality of food. Many a times, it has been noticed that the quality was so bad that children went sick. But another serious problem that I am told of is that at some places the children refused to take the food because it was prepared by *dalit* women. This is a very serious matter. This was in the news. We need to give proper education to children so that they treat everbody equally and honourably. If this kind of things are happening, you can make a policy that wherever this happens, those children need not take the meals. If they say that meal should be prepared only by some individuals, that is not possible.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Santoshji, now you have taken 37 minutes.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will take only two hours more.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Two hours more!

SHRI SANTOSH BAGRODIA: If that is too much, then, I will take one hour more.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have taken 37 minutes. How much time do you need more?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will try to finish it in 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): That is too much.

SHRI P. CHIDAMBARAM: How many speakers are there, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): There are a lot of speakers.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Finance Minister, we have 12 hours. We will not go beyond 12 hours. Don't worry.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): But there are many speakers.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I know there are many speakers. They will not come, or they will not speak much. Sir, I will try to finish quickly because you are now hurrying it up. Sir, SEZ is not the problem of this Ministry. But I would like to know from the hon. Minister that so many special benefits have been given only for the SEZ units. What crime has been made by the existing units all over the country which are established exporters? Why not make the entire country an SEZ if you want to? Otherwise, please do not give more benefits to the new units at the cost of the old units. Similarly, Sir, I understand the importance of exports. I also understand that we cannot create new *zamindars* for the next thousands of years without any actual benefit to the poor people of the country. In fact, the existing exporters are badly affected under the relentless rise of the rupee against the US dollar. I, therefore, recommend the following points specially for the SME sector:—

1. There is, therefore, a need to customize a package for the SME sector by providing, among others, tax incentives to the manufacturing export sector to move up the value chain (as in Section 35B) for creating an 'export profit reserve' for expansion of R&D.

2. Extend Sections 10A and 10B of the Income Tax Act, 1961 to all exporting units.

3. There is need of basic customs duty exemption on capital goods imported under the EPCG scheme, exempting exporters from payment of customs duty on capital goods.

These are some of the points which the hon. Minister may kindly consider. The small manufacturers who are either in non-excisable sectors or are exempted from the purview of excise duty have to bear the incidence of service tax paid during the course of exports. This may please be considered. The exporting community suggests *ab initio* exemption from payment of service tax on notified services.

Then, Sir, take the CENVAT Rules. The refund of output service tax may also be allowed under the existing CENVAT Rules 2004. Sir, there was a CAG report which says that the Government had to forgo Rs. 1043 crores by way of custom duty exemption alone to these units. The total duty of Rs. 106 crores along with an interest of Rs. 46 crores was

recoverable from 24 SEZ units which fail to achieve positive NFAs. So, I don't know what is to be done. Sir, you might have to re-visit the SEZ plan. Otherwise, the whole purpose for which you are giving this benefit will also be defeated.

Sir, the sunset clause to the income-tax holiday available for the units set up under the STP and EOU scheme post March 2009 is likely to add a significant cost pressure to the domestic players in the globally competitive export market. Sir, I am talking about the small units only at the moment. The FBT is a hard-hitting tax, and the estimates suggest that the tax is no longer 'fringe', and it comprises around five per cent of the PBT for SMEs. The FBT provisions should be rationalised to exclude genuine business expenses.

Sir, while corporatisation of SMEs is being encouraged, the Minimum Alternate Tax (MAT) and Dividend Distribution Tax (DDT) are adding additional layers of tax.

On the compliance side, considering the current business environment and inflation levels, the threshold limit for compulsory tax audit should be enhanced to Rs. 10 million from the present level of Rs. 4 million, which was introduced in 1984.

Sir, I hope the hon. Finance Minister does the balancing act to add fuel to the growth engines of the Indian economy.

Sir, for the information of my friends in the Opposition, I just want to mention that farmers do have a good track record. So, they should not worry how the new loans will be given to the farmers. The banks will be too happy to continue to give them new loans.

Sir, coming to Micro, Small and Medium Enterprises, I just refer to page No. 198 of the Economic Survey. I am surprised to see these figures. On Table 8.17, every year, the growth of number of units is shown as 4.1 per cent. I can't understand how this figure has been arrived at. Similarly, Sir, the employment growth rate is also shown as 4.5, 4.4, 4.5, 4.3 and 4.2 from 2002-03 to 2006-07. If you know, there are three types of... *(Interruptions)*...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): What is the source? The source is given.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I know it is not your fault directly. But since you have issued this booklet, I am mentioning this. I would not have mentioned it here otherwise. I know that the Ministry of MSME has given the figures and you have just incorporated it. I can tell you how they have calculated it too. I would just read out to you how they have calculated it For your kind information, Mr. Finance Minister, the rate of growth of the total number of units in the SSI sector for 2001-02 was 4.1 per cent. It was estimated on the basis of the Third Census results and the 56th and 57th rounds of the National Survey concerning unorganised manufacturing and unorganised services. This growth is assumed--I underline the word 'assumed'--to be constant till the results of the Fourth Census of MSME and subsequent rounds of NSS are available. I am only saying that these are all assumed figures and the Economic Survey is a very important document. We cannot have figures that are assumed figures.

Sir, I will not go into more details except for saying that providing funds of Rs. 2000 crores with SIDBI is good, but the guarantee that you have given, a one-time guarantee from 1.5 per cent to one per cent, and an annual service fee from 0.75 to 0.50 for loans up to Rs. 5 lakhs only, is neither here nor there. I can tell you from my experience--I am the Chairman of the Industries Committee-- that you will not be able to locate even a single

beneficiary if it is kept at Rs. 5 lakhs. Make it Rs. 50 lakhs; only then would you get a beneficiary. This kind of help would not really help. Sir, what I suggest is, increase the turnover eligibility limit from Rs. 4 crores to Rs. 5 crores for availing of general excise exemption benefit.

The next point is about exemption from service tax to MSHGs providing business auxiliary services. I am just quickly going through the points.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is already 45 minutes.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The other points are related to strengthening of credit linked capital subsidy schemes, strengthening of credit guarantee schemes and providing banking status to Small Industries Development Bank of India.

Sir, I would just like to make two last points. Hon. Member, Shri Venkaiah Naidu has thrown a challenge saying they wish to have a debate with the Congress Party. This is an ocean and that is a pond, and there is no match. I cannot say about the Party, but if he wants, I am willing to accept the challenge. Any Member of my Party would accept the challenge and have a debate about what this Party has done for the farmers and what they have done for the farmers. Mr. Finance Minister, this is one point which is very important and which would help you increase your revenue. You have mentioned a policy somewhere here that there would be an excise duty based on capacity and not on the actual production. In some places that may be bad, but in the case of *paan masala*, it would help you. At the moment, the total revenue is about Rs. 40 crores or Rs. 50 crores per month. It should be, at least, Rs. 400 crores per month by your own estimates and that is possible only if you make it excise duty per machine capacity instead of production. Then there would be no evasion. Similarly, Sir, while it is correct that non-filter cigarettes are more harmful than filter cigarettes, and I welcome this action, this has created an anomalous situation. Such a high increase in the excise rate would result in non-availability of cigarettes at the lower end of the market. This will only encourage *beedi* smoking. Sir, I think this relates to your State also. *Beedi* smoking and illegal trade in the country...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P J. KURIEN): Whether it is beedi or cigarette, both are not good for health. Smoking is bad. Both are to be avoided.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I understand that presently 30 per cent of the volume of the cigarettes is in the form of non-filter cigarettes. Thirty per cent drop in cigarette volume would result in reduced demand for tobacco used in cigarettes, thus putting tobacco farmers in total distress. As per the Ministry of Health and Family Welfare, *beedis,* which are cheaper and consumed more by poor people, have higher tar content. *Beedis* are more toxic to the smokers than smoking other tobacco products. Thus, the burden of tobacco-related diseases is high in this group. It is suggested that excise duty by reduced to make this product available to the poor sections of the society as well. It was going on already. I am not commending that smoking is a good thing. But, those people, who wish to smoke after having been informed of the ill-effects of it, must be given a choice.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude now.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Now, I am not going to take any issue other than the issue of price increase. Sir, hon. Finance Minister has mentioned about the price increase and he has mentioned that world prices of different cereals have gone up. But, whatever has

happened, I want to mention about the price rise in pulses. Price of moong has gone up from Rs. 28 to Rs. 36; arhar-Rs. 35 to Rs. 46; chanaa-Rs. 32 to Rs. 40; masoor-Rs. 34 to Rs. 52; chilka daal- Rs. 32 to Rs. 48; genhu, that is, wheat- Rs. 13 to Rs. 15; oil-Rs. 50 to Rs. 72. Now, even in vegetables, the increase is there. Price of carrot has gone up from Rs. 5 or 6 to Rs. 8 or 10, about 100 per cent increase; peas-Rs. 15 to Rs. 20; tomatoes-Rs. 14 to Rs. 20; बैंगन- दस रुपए से बीस रुपए हो गया है, papaya- Rs. 12 to Rs. 20; apples- Rs. 20 to Rs. 50. What I am trying to say to that this price increase has taken place in a big way. Hon. Finance Minister, in one of the speeches, has mentioned ...(**Time-bell**). I am just finishing. You can see that I am keeping all the papers.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I know you can speak without papers also.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Now, he has mentioned about this price increase and he has also mentioned that international prices have gone up. I fully agree for white goods, for other goods, if the prices go up, it is understandable. But, Sir, India is a poor country. Still, we have 300 million people BPL. Now, we cannot compare this kind of increase with the world prices. I think, it is the minimum duty of the Government to find out ways and means to get enough supplies here so that the poorest of the poor can, at least, get their food, vegetables and milk when the prices are going up. No excuses are going to be pardonable. The result will be that all his efforts for waiver scheme of Rs. 60,000 crores for farmers and all other good schemes will go waste in case the prices of foodgrains, prices of pulses, prices of vegetables do not come to a level where an ordinary citizen can have it freely for his family. (**Time-bell**) I am sorry, Sir, I have taken a long time. Thank you, Sir, for having given me this opportunity.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, in contrast to a lengthy speech by Shri Santosh Bagrodia, let me try to be brief.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, in because your Party has only 31 minutes, and there are two speakers.

DR. K. MALAISAMY: We will manage that. I would say, Sir, that you have been always very considerate.

Thank you, Sir, for having permitted me to speak on a most important subject, namely, Budget, on behalf of the leading political Party in Tamil Nadu, AIADMK headed by a daring, dynamic leader, Puratchi Thalaivi Madam Jayalalitha a who is a mass leader, magnificent leader, marvellous leader, field leader, fearless leader and a famous leader indeed. Sir, I have been listening to the discussion on both the sides, from this side and that side. Any coin will have two sides. Similarly, when they speak from ruling party side, I mean, they pat, praise and cheers emanate in plenty in favour of the Finance Minister who has presented the Budget. On the other hand, the Opposition has got their own reservation on the score that it is an election-oriented Budget, it is a populist Budget, and, it has been presented with a hidden agenda etc. etc. Sir, whatever may be the position, I am inclined to analyse it, based on objectivity and merit. Our hon. Minister, by virtue of his knack followed by his word power and vocabulary in Tamil as well as in English he used to cite the world-renowned Thirukkural whenever he makes a Budget speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But we do not hear his Tamil speech.

DR. K. MALAISAMY: Following the same approach, I will also try to cite a couplet, from Thirukkural which means that on an issue what are all the plus points on the one side, what are all the minus points on the other should be weighed and one can make a decision based on whichever is in excess of the other. This is what Thirvukkural has said.

Sir, before we could assess and analyse-there has to be some basis on which we should proceed. Everyone of us knows as to what is meant by Budget? The Budget is the political philosophy of the Government from where the Finance Minister is hailing. The whole gamut of the Government is comprised in the form of the Budget, with the result they allocate money and get things done.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair)

Secondly, Sir, for any Government irrespective of the form of the Government, there should be three primary concerns.

In other words, any government should basically aim and ensure three things-absolute peace and tranquility; pleasure of the people; and, health and welfare of the people.

Since the Finance Minister and the Minister of State and most of my Tamil Nadu colleagues are present here, I am tempted to cite one more poem from Sangam age which means that Why are you not able to get grey hair? I mean, I am so happy. For happiness, these are the things that are needed. Out of which, the very, very important they are mentioning is, namely, The Government or those who are ruling should do all good things and should not do any harm to the people. That is the crux of the point.

Sir, keeping the definition on one side, and the parameters that I have mentioned now let us see whether the Budget is able to fulfil what is needed. My question is whether the Budget has met the requirements. I am sorry to say that the inflation continues, the prices are going up and the unemployment still persists. What about the three things that I mentioned, namely peace pleasure, welfare etc.?

What I am trying to say is that after having seen the UPA Government in office for so many years, what is the perceptible, visible improvement or development that we can witness, you may try to cite so many things but any Government is supposed to do all these things. Is there any thing, which is strikingly different from others? A situation, I would like to discuss a few things in Budget. I would not like to go from a to z. Sir, when the hon. Minister came out of the Lok Sabha after making his Budget speech a number of his friends started congratulating, pampering him saying, that he has saved them and he has done wonderful things for the purpose of elections and all. So, this is the appreciation I could see and heard. His own party people said, "You have done wonders for the purposes of elections". What does it mean? What I am trying to ask is one and the only core purpose about which people are very happy is about the waiver of farmers' loan to the extent of Rs. 60,000 crores. Sir, the AIADMK Party is meant for the poor, downtrodden, oppressed, suppressed and depressed. These are the people about whom the AIADMK is very much concerned. In such a situation, if anything comes to a farmer, anything comes to a farming community, we will all out to support. I mean, if anything comes to them it is fine. But, the way that you are doing, the timing you have chosen belonging to ruling party is questionable. Even the Vice-Chairman, while making the speech, had been critical about certain aspects of the Budget.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The AIADMK supports it or not?

DR. K. MALAISAMY: I very much support the farmers. But not the way you are doing ...*(Interruptions)*... As far as we are concerned, rupees 60,000 crores which you have set apart, I mean, it was sudden and surprising. In fact, we did not know the background of all this. Sir, you know very well that there are political executives and the bureaucracy to implement any decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You are mature enough of both.

DR. K. MALAISAMY: What to do is the function of the political executive and how to do is the function of the bureaucrat. In this process, the bureaucrats, so far as I could gather, are not able to say what is what. With the result ultimately, it is sounding very well. What is the rationale, what is the scope, what is the intent of waivers we are yet to understand. Sir, I will confine myself only to waiver of loan and about rural employment. Except these two points, I am not going to touch the defective points in the Budget. My first and the foremost point is, as far as the loan waiver is concerned, it is not at all clear, in the sense, that how do you arrive at the figure of Rs. 60,000 crores. Can you afford to give the estimate? I have listened to your interview; I have listened to the speech of the Prime Minister. I have gone through all this. You are already in a fiscal deficit. Where from do you get this money? How could you mobilise? In what form? No doubt, it is your look out. It is your empire. I am not going into it. I am very much worried how you could manage. That is the point I am trying to make out. Secondly, are you going to reimburse, or, are you going to issue bonds to the banks? My third point is, there is no mention about any allocation. You have not made any provision in the Budget. Sir, the fourth point is, you have not given any category of the borrowers, any category of the loan. Sixty per cent of the farmers report that they do not belong to the category of loan. Sir, I hail from a village. I belong to a farmers community. So, I can talk with a little authority, though I am on a different footing now. The point is, in a farming community, there are rich people, marginal people and small people. There are various categories of people. Out of them, how many people go for loan. Many of the people, who cannot approach the banks, go mostly to the monelenders. Nearly 60—70 per cent of the total people, who are in the farming community, who are in need of money, go to the moneylenders. I would like to ask whether the loans taken by the farmers from moneylenders are also covered under this scheme. There are several people who come under the category of Kisan Credit Card. My friend Mr. Govindarajar, who is sitting by side is familiar with it. I want to know whether that category is also being covered. The Minister may try to explain to me that these are all minor details which he can do later. Sir, my point is that this is a major problem which cannot be handled easily. It is going to complicate and the ramifications will be that the total scheme itself will become a question mark. This is what I am trying to say.

Sir, the next point is access to financial institutions. Only well-informed farmers and rich farmers can approach them. So, if you say that you want to waive the institutional outstanding debt, it is going to cover only a very few people. If at all it will cover them, it will cover the rich people. It will not cover the marginal farmer, the small farmer. Therefore, what I am trying to sum up is that any generalised waiver will never help the rural borrowers at all. This is the core point which I wanted to make out on the loan waiver.

My second core point is this. In doing so, it has got lot of adverse affects. Sir, you are very much concerned about values. You want to set an example. The Government should set an example. If you say that the borrowers can get away without making any repayment, it

does not create any good culture. On the other point is, it creates a bad culture. This is the approach. The people who know about values. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA (Maharashtra): Then why don't you oppose it? ...*(Interruptions)*... Then you should oppose it. ...*(Interruptions)*... Why don't you say that it should be withdrawn? ...*(Interruptions)*... Then you should say that the waiver should be withdrawn. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Please sit down. ...*(Interruptions)*... You have said this. Now let him decide how he wants to articulate his arguments. ...*(Interruptions)*... Let him articulate the point the way he likes. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: You want to say that this is good but this is bad also. How can it be possible? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shuklaji please. ...*(Interruptions)*... Let him articulate the point the way he likes. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Either you should demand the withdrawal of the waiver ...*(Interruptions)*... You cannot say that this is good but this is bad also. ...*(Interruptions)*... This is what I wanted to say. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: I will clarify it. ...*(Interruptions)*... As I told you in the beginning, the concept of waiving loans. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Dr. Malaisamy, please address the Chair. Please look at this side.

DR. K. MALAISAMY: My intention is very good. You could not understand my intention. You want to implement a scheme. But there are several defects in it. If you correct the defects, it can be implemented easily. That is the purpose behind my saying this. I hope I am clear now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You articulate your point the way you like.

DR. K. MALAISAMY: Now I come to the other point on loan waiver. The hon. Minister is very much concerned about economic reforms. They have done so many things in so many ways as far as that aspect is concerned. Now, waiver is totally against the concept of economic reforms. Is it not running counter to your economic reforms?

SHRI P. CHIDAMABARAM: No. I will clarify it in my reply.

DR. K. MALAISAMY: Kindly clarify it. Sir, he has said in one of the interview that all these things can be taken care of and necessary exercise can be done within a period of four months. Sir, I very much doubt whether this could be done. Let us wait and see because some time should be given for it. Many times we have seen in the history of elections that whatever promises you make, they never work. That is the point I want to stress What I am tyring to tell is that, in most of the cases, it appears to be more like a promise. Sir, I would cite one of our ex-Members of Parliament, Mr. Cho. He used to say that a clever politician is one who throws promises left and right and after having seen that the promises could not be implemented, he should be able to explain why they could not be implemented. ...*(Interruptions)*... A politician should not throw promises left and right.

They must be able to implement it. That is the way I look at it. Sir, here I want to cite an example. Sir, you have come across as to what is happening in Tamil Nadu. Sir, in Tamil Nadu, they have given a promise of issuing colour televisions. They have also given another promise of issuing two acres of land to landless poor. God only knows whether the promised scheme is a success or not. What I am trying to say is ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No interruptions. Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... I can't allow interruptions. Please, keep quiet. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record other than Mr. Malaisamy's speech. ...*(Interruptions)*... I cannot allow interruptions. ...*(Interruptions)*... Let him speak ...*(Interruptions)*... He has every right to speak as to what is happening in one State. ...*(Interruptions)*... You can speak only when your turn comes. You can't interrupt like this. ...*(Interruptions)*... No interruptions please. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): It is implemented in a phased manner. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Unless he yields, I can't allow. Shuklaji, I can't allow. ...*(Interruptions)*... Whether he yielding. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): All right, if you are not yielding, I will not allow ...*(Interruptions)*... If he is not yielding, I can't allow. ...*(Interruptions)*... You please go ahead. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Sir, I don't know whether they have listened to me or not. ...*(Interruptions)*... I am not using any objectionable words. I am only citing an illustration as to how election promises are made but not implemented ...*(Interruptions)*... This is unpopular. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): That does not make any difference. But, you also don't speak. Mr. Malaisamy is strong enough to defend himself. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. No interruptions wil go on record. ...*(Interruptions)*... All right, Mr. Malaisamy, you go ahead. ...*(Interruptions)*... Will you please keep quiet? Please keep quiet. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Sir, how the Vice-Chairman is going to take them to task for having made me cut my speech? I have lost my flow and I have lost my continuity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You go ahead. You are capable of continuing very well. ...*(Interruptions)*... Don't worry about it. I know your capacity.

DR. K. MALAISAMY: Mr. Vice-Chairman can give a ruling that if they have got anything to say let them do so in their turn we are willing to listen to them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You come to your next point because you have three minutes only.

DR. K. MALAISAMY: Sir, when you have given me permission to speak, I should be permitted to speak freely. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Please, go ahead. Take **your next point.**

6.00 P.M.

DR. K. MALAISAMY: Sir, the sum up, many times, whatever they say, it could not be implemented. There are umpteen number of illustrations, for example, colour televisions and two acres of land. This is the point which I am trying to put forward regarding what is happening in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

Sir, now, I come to the next point ...*(Interruptions)*... Sir, now, I come to the Rural Employment Guarantee Scheme. Sir, this is one of the very good schemes. I don't deny it. But, again, it is badly implemented. Sir, as a Member of the Public Accounts Committee, I know the Audit Report on this aspect as to how the Rural Employment Guarantee Scheme has been misused, how the money has been diverted, how badly it has been done, etc. There is a big file on it. What I am trying to ask is, as a villager, I have seen in my village and in other adjoining villages that a number of REGP works are going on. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: You are not a villager. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Narayanasamy, please don't interrupt?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member is staying in Chennai. How can he say he is a villager?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No. interruptions. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb him, otherwise, his time is being wasted. ...*(Interruptions)*... You will lose your time. ...*(Interruptions)*... No interruptions. ...*(Interruptions)*... Go ahead ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Sir, I have a clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Okay, let him ask what does he want to know.

DR. K. MALAISAMY: Sir, the time taken by Shri Narayanasamy from my time may be compensated. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member is from Chennai, how can he say that he is from a rural area? Let him clarify that point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No, no. That need not be clarified. ...*(Interruptions)*... You go ahead. *(Followed by TMV/4n)*

DR. K. MALAISAMY: I don't know about Narayanasamy. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You go ahead. You need not clarify.

DR. K. MALAISAMY: But I am going to the villages. The hon. Minister knows me and I know him. He is going there and I am going there. He hails from the same constituency from where I hail. We know each other. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You go ahead.

DR. K. MALAISAMY: When we speak, we speak nothing but the truth. I have seen it with my own eyes what happens in the name of road construction, in the name of desilting, in the name of this and that, giving employment under Food for Work Programme. What

happens is that, on the one hand, the machine is brought and all these works are being done by big machines and big equipment and, on the other, they try to write the M-book in such a way that so many people are employed and so many men are given employment. In other words, what is the purpose of the scheme? The purpose of the scheme is to offer employment. But the ground reality is that it is not at all happening.This is the point that I am trying to make. So, there is a total misuse of funds. This is the way I look at it. In such a situation, I would like to know whether the hon. Minister is fair enough to allocate funds for extending this scheme to all the 596 districts. Even for doing it in a limited way you have received so much of criticisms and comments from the audit, etc. (*Time-bell*). Sir, have you taken into account the time taken by Mr. Narayanasamy? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Even after taking into account that time, your time is over. ...*(Interruptions)*... Listen to me. Malaisamyji, you can speak. Your party has 31 minutes. Out of that you have already taken 21 minutes. Now, you have got a second speaker. If you withdraw that speaker, you can get another ten minutes. I have no problem. But we can't go beyond your party's time. That is the only point. You decide.

DR. K. MALAISAMY: He will be very brief.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Okay, Whatever time is left out, he will get.

DR. K. MALAISAMY: My Specific and pertinent question to the hon. Finance Minister is this. You have extended the scheme to 596 districts, through out the length and breadth of the country. Your object is good. But when it is bad in implementation, when there are umpteen no: of criticisms and with all that, is it desirable to extend the scheme, all of a sudden, throughout the country? *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No interruptions, please. Don't rectify. *(Interruptions)*... Let him make mistake. *(Interruptions)*... You would better let him make mistakes.

DR. K. MALAISAMY: I have been harping on that the hon. Minister has brought a good scheme of waiving the loans which is bristled with a lot of defects and difficulties. You could have tried it three years before. You could have done this when you came to power. Instead, why do you do it on the election eve? This is my point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Election is next year, not this year.

DR. K. MALAISAMY: So, your purpose is not *bona fide*. Your hidden intention is something different. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No running commentary, please.

DR. K. MALAISAMY: If the hon. Minister is really interested to uplift the rural people, to really help the farming community, to really help the other poor, etc., I would like to quote: a couplet from Thirrukkural which says that if you really want to hit the nail exactly, you should go to the root cause. If you go to the root cause of the farmers' plight, if you go to the root cause of the rural people's plight, you will come to know about it. But you have not done it. That is the point that I want to make. What I am trying to say is please try to give

solutions for unemployment, migration of unemployed persons from the villages, migration of villagers and lawlessness in the villages. Youths are reluctant to take up agricultural work for various reasons. There is insufficient technology, lack of proper mechanisms, market exploitation, low productivity and, above all, no support price for the products. These are some of the fundamental things which one should consider and do some comprehensive exercise. *(Interruptions)*...

The last point is this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): The second speaker from your party will have no time left if you take any more time now.

DR. K. MALAISAMY: If all of you interfere like this, I will get permsion of the Chairman to name on all... *(Interruptions)*... I am serious today. Sir, when the hon. Minister is going to think of waiving the loans, he must have a reorientation in a revised context so that whatever revisions he wants to make, he has to give to the farming community as a whole, whether it is small farmers or marginal farmers, instead of confining to one particular group. He should also give total relief to the entire farming community so that things will be better for them. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (Maharashtra): Sir, I commend the hon. Finance Minister for presenting a Budget geared towards enhancing growth and development to take India forward. It is a Budget for all the citizens of India to further partake in the Indian story.

From tax reliefs to excise reliefs, waiver of farm loans, allocations to the social sector, to incentives for improving education, the hon. Finance Minister has covered all the major sectors and segments of society, and, in turn, thrown a challenge to the people of India to continue and sustain the path of economic development that has been seen since the UPA Government has come to power. Sir, taken in totality, this Budget, along with the previous ones presented during the tenure of this Government, all have laid the foundation for an economically secular India which, though interlocked with the world economy, yet remains relatively insular from the effects of recession that may occur in various parts of the world.

While all the salient points have been presented and spoken during the discussion by my earlier colleagues, I would like to highlight four most important issues, which are close to my heart, before this august House, that will take India to a different trajectory in economic development. The waiver of loans in the agriculture sector and enhancements to increase agriculture output, the incentive to improve and offer quality education to all, enhancements for the social sector and lastly, acknowledging the role of women in the growth of the economy, all these will contribute towards India's development.

I have read with trepidation how most people are concerned with, as to where the Government will raise the funds from, for this waiver given to the farmers of India. While on the one hand, voices had been raised to grant this waiver and, in turn, take credit for the same, now the same voices raise the bogey of the Government falling into a debt trap if there is no game plan to account for this short fall. Rather than playing petty politics, we should try and understand why this step was taken, why it was necessary and how, in the long run, this will aid not only the farmers and the agriculture sector but will also improve the economy of our country.

The loans, as we are all aware, were taken by the farmers at interest rates that were prevalent during the time of disbursements and based on the then prevailing market conditions.

Some of these loans have been carried forward for years together, and during this time, much water has flown through the river of economic development. Whilst the focus remained to enhance, upgrade and make the manufacturing sector competitive, here lay a dichotomy of the agriculture sector being left behind to fend for itself and innovate techniques to provide food for the rest of the country. The farmers were left to plant and plough for generations, and use whatever knowledge their families and forefathers have taught them. They were probably not even aware that there could have been a crop mix and things would have been different. Hence they continued to till the plot of land, which they knew best to do for generations, no matter whether there were floods, drought, winter, summer or spring. Nothing changed for them. In good times, payments were not an issue, but in bad times, it became a serious issue. Today, we appreciate the Government's efforts of waiving off Rs. 60,000 crores. But it is a reminder to all of us that if we do not address the issue of enhancement of the agriculture sector to make it competitive and, at the same time, deliver the economic benefits to the farmers, in a few years, we will be clamouring for another loan waiver, and I have no idea what that amount will be! The funds allocated towards the Irrigation and Water Resources Finance Corporation is a welcome step towards growth. As we are all aware, 60 per cent of agricultural land in our country is rain-fed. Here, I would request the hon. Minister, if he could relax the norms for the loan in rain-fed areas, where probably irrigation is totally weak, we should all try and get good irrigation for our entire lands, in case we need to achieve our dream goal of being self-sufficient in food security.

More thrust has been put on watershed development projects and also on improvement of the infrastructure of our minor, major and medium irrigation projects. The National Food Security Mission, the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the National Horticultural Mission, the Mobile Soil testing programme and the plantation crops are all initiatives which are going to bring a qualitative change to this sector and we all appreciate it. And, it is our responsibility to ensure that they are all deployed diligently so that the results are visible in the years to come.

We have to, Sir, bring enhancements and technology to the agricultural sector in order to partake in the economic development of India. With the reach of the Internet, the new generation of farmers are fully aware of what the world wants, and what can be achieved. Knowledge is aplenty, but it is how we use it that makes a difference between success and failure. We need to aid them in working towards ensuring that knowledge is used effectively and new techniques are adopted so that economic benefits of the same are achieved by all. There may be resistence as most of us are not used to what may be proposed, but if they are not educated on these techniques and schemes proposed, the likelihood of falling into a dept trap is large and we will all be back to square one. Hence, Sir, whilst the waiver and the allocation to schemes that will aid in the upliftment of the agriculture sector is welcome, we need to ensure that by bringing innovation and enhancements we give a better life to the farmers, and ensure that the economic development allows them to pay their debts on time and with honour. The funds allocated to the Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth in Rahuri, Maharashtra, will help in the advancement in teaching, research and impart extension education aimed towards just this. We hope that the Vidyapeeth in Rahuri becomes a torch bearer for these goals, and that other such institutions take the cue, succeed and be funded further.

All these initiatives will help us and should help the agriculture sector reform and contribute towards achieving GDP growth going forward. Sir, I do hope that besides the

incentives already given, the Government will also encourage by reducing interest rates to the farmers who are regularly paying their dues to the banks as regular payments, as this is very important for the health of the lending institutions. Sir, it is not that we do not appreciate all your efforts, but I also urge the Government to consider the recommendations made by Dr. Swaminathan and the National Commission of Farmers to offer interest rates to farmers at 4 per cent calculated on a simple interest basis; offer direct fertiliser subsidy, universal crop support prices and all of which will further boost the sector and further benefit the economy of our country.

This brings me to the issue of education and I think it is a subject which is close to the hearts of all of us. A lot has been achieved and a lot has been done. But today there is a serious cause of concern. There is always a perception that the Government is not doing enough for education. Sir, the last few years have shown that this view is highly cynical and that the advent of television, rural telephony and internet access has in a sense 'educated' the masses into what is available in the world and shown them that if you strive and work hard, anything is possible. However, it is prudent to point out that whilst all these forms media and information may help in creating and enhancing knowledge, if not channelled properly, it can lead to disastrous situations.

It is here then, that policies, frameworks, benefits, taxes etc. given for education are implemented the way they should, vigorously, aggressively, and the people made accountable for the same. Today, we have a great infrastructure for all our schools but what we really need to address is the quality of education that is imparted to our children. We appreciate the additional funding that the Government has done for our IITs and IIMs. But, Sir, I urge you not to remove your focus from primary education as it is very, very crucial to all of us. Specially, in the State from where I come, Maharashtra, today our Zilla Parishad schools have buildings; they have infrastructure; they have computers; they have sanitation; but we do not have quality teachers. So, that is something that we really need to address, because we feel that you are putting in a lot of money in infrastructure but now the time has come when, if we need to change our focus from quantity to quality.

Sir, the funds offered for Sarva Shiksha Abhiyan, the Jawahar Navodaya Vidyalaya, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and the Nehru Yuva Kendra, seem to be a very welcome development, but we need, again, to ensure that the implementers are made more accountable. The time has come when we have to introspect to see if improvements and enhancements are really needed. These additional funds which the hon. Finance Minister has very kindly given are given to the sections which really require it.

Sir, I would like to make a note here-which Brindaji, earlier, has also mentioned about the differently-abled people. I feel, somewhere in this Budget, we have all forgotten them as they are part of us, and they do contribute a lot to all of us.

Sir, whilst offering education to all, we have to realise that there is a large section of the society today which comprises of young women and men who are, probably, not educated. They live in villages, or even today the urban population who have no means of income, who have tried the way of the Self-Help Groups. The Self-Help Group is a great movement which has started today in our country, which is giving good results. But, Sir, there has to be now more focus on giving them education and incentives for a qualitative change. It is about skill development and vocational training as alternate education for these people. We appreciate the amount the hon. Finance Minister has given towards the pension of the Self-

Help Groups. But, Sir, the focus today really has to be skill development. Maybe, you could address or help us to make a formula where through our Zila Parishad a certain amount has to be kept for our women who could be educated. They need more guidance for marketing and packaging. These women are doing a lot of good projects. These women are somewhere caught up in the web of making pickles and *papads,* and, unfortunately, this whole great effort that we are all putting together through Self-Help Groups is not giving the results we want to. Sir, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, the Aam Aadmi Bima Yojana and the housing schemes will contribute...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): But will you like to undermine people making *papad* and pickle? What is wrong in it? That is good. They are doing a good job.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is value addition *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Yes, it is value addition.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, what we are really looking is, as rightly said, value addition. They need to be trained. If there is a group of thousand women making *papads,* why should the other thousand copy them? Because that many *Papads* and pickles we can have. So, they can move like a success story in Latur. I am digressing, since you have brought this up. There is a lady who makes soyabean *chyuda,* and she has a great demand. She took part in one of our fairs, and today she has demands for *vyopaar* all over Mahrashtra. I think, that is the success story of our women. So, they have moved on. We are trying to get them into the forefront. They should have a level-playing field. I think, our women should be trained. Everybody is talking about the mall-culture. Why do our Self-Help Groups not have good products? We are willing to go with the multinationals and will give them a tough fight with good products which are made of good quality, which have good marketing and packaging skills. That is what, Sir, we are looking for.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You are speaking very well. So, I provoked you. Good.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, it is not very difficult to provoke me. I am quite immature.

Lastly, Sir, on behalf of the women of India and the women MPs, I thank the Finance Minister for increasing our threshold limit when we file our Income Tax. However, Sir, under the Sixth Pay Commission, I do think this threshold should be increased further from Rs. 1.8 lakhs to Rs. 2.0 lakhs, bringing us on a par with our male counterparts, who also can get some benefit as a family. Women have come to play a very important role in various sectors of our economy. However, there still exists a bias towards women, especially, the divorcee, the girl child and the widows. While all women are the same, what we acknowledge and appreciate is, if the banks could be directed to give one per cent extra interest to deposits held by widows, divorcees and single women; we could even have an age bracket, say, 30 or 35, and offer them loans at a discount of one per cent. This reduction and increase in percentage of interest will be of great assistance to the ladies living in difficult conditions having to fend for themselves.

Sir, we appreciate the increase of 24 per cent in the allocation of funds to the Ministry of Women and Child Development, which only goes to show that the Government gives

women importance in the development of this country. The women have progressed from being pillars of strength to their husbands and men folk in the families as well as home-makers and mothers, to equal contributors to the economic household and equal decision makers. Sir, whether educated or not, women have always played a major role in India's development, and this recognition bodies well for all of us. Most women who run Self Help Groups or Aanganwadies today or may it be ASHA workers, Sir, would appreciate if you could find a medical aid scheme or a pension scheme for all these women under these sectors. I know it is a huge sector; it is too much for us to demand, but, eventually, we all are also looking for some sense of security from the Government. May they be from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Castes, Minorities, whomsoever, Sir, but I request you to provide for some medi-claim scheme or pension scheme for all us women and there should be no discrimination of caste, creed or religion.

We also appreciate your five year tax holiday set up for the health sector. Quality healthcare is a must. We appreciate the National Rural Health Mission which is trying its best to reach every corner of this country. But, as we all agree, a lot needs to be done. It needs to see much more in the awareness of our AIDS program, in the reduction of diseases; there could be issues concerning pregnancy, child birth, malnutrition, safe drinking water, sanitation, etc. Sir, we are a third world country. We cannot forget all these bases, and I regard the hon. Finance Minister for being very considerate about all these issues. A lot has been said that he is more an economist. I think, he is a citizen first. In this entire Budget, he has touched every part and section of the society. The initiatives taken by the hon. Finance Minister regarding the climate change, the tiger protection and the Sainik schools are absolutely commendable.

Before I end, I just would like to quote the Finance Minister in his Budget Speech. I remember him saying, "More can be done, more needs to be done. Sir, we appreciate all the efforts, but we appreciate even how you have said that more needs to be done in humility. I appreciate all the efforts you have done. But I cannot help it, we are hopefully looking a lot more from you. From the bottom of my heart, I thank you very much for giving such a good Budget to all sections of the society. Thank you, Sir.

SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR (Assam): Sir, firstly I congratulate the hon. Finance Minister who has presented a fair and balanced 2008-09 Budget. It is sound in terms of contributing towards short-term micro-economic stability. It will provide impetus to sustaining high rates of growth over the medium-term. Most importantly, the 2008-09 Budget will be important for sharing the benefits of growth more equally. A growth rate of 2.6 per cent in agriculture in 2007-08 will put pressure on food prices in 2008-09. This will be compounded by the rapidly rising prices of wheat, rice and edible oils in the global community marketes during the current year. Inflation is generally and rapidly increasing food prices, in particular are the most regressive of taxes. These will hit the poorest the most. The importance given to checking inflationary pressures is welcome.

Continued fiscal consolidation at the macro-economic level is necessary to alleviate inflationary pressure. I am pleased that the imporvement in fiscal position is projected to continue in 2008-2009. The explicit acknowledgement by the Finance Minister that the liabilities of the Government on account of oil, food and fertilizer bonds are contributing to understating the extent of the fiscal deficit is most welcome. It is heartening that he intends to bring these liabilities into future fiscal accounting.

The 2008-09 Budget could, at the macro-economic level, be viewed as facilitating a short-term growth with price stability. The Finance Minister has noted some softness in demand for consumer durables. I welcome the cuts in excise taxes not only in the small car sector as well as in two wheelers and three wheelers but also along a wide spectrum of other items. These should contribute to a pick up in the manufacturing sector. Clearly, the increase in the threshold limit of exemption of Income Tax from Rs. 1.1 to Rs. 1.5 lakh, Rs 1.45 to Rs 1.8 lakh for women assessees and Rs. 1.95 to Rs. 2.25 lakhs are steps in the right direction. They not only reflect rapid growth in the last few years but the resulting assistance to women and senior citizens demonstrate greater social awareness. Overall, these steps should also bolster aggregate demand.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair.]

In order to cushion the impact of higher food prices and other essentials, I have noted that nearly Rs. 33,000 crores would be provided as food subsidy under the Public Distribution System. The cost-effective delivery of subsidised food with no or minimum leakages is the fundamental challenge facing us. I strongly support a significant widening of the cost-effective delivery of subsidies to target groups through the use of smart cards. Shrimati Brinda Karat has already spoken about price rise. This will surely affect the prices. It will permanently benefit vast majority of our rural poor. Improved farm productivity and income security through creating on and off farm employment opportunities are the right way forward for ensuring growth with equity. Rapid growth in the manufacturing sector is important for both sustaining rapid GDP growth and creating new productive and decent employment opportunities. Power, roads, ports and other infrastructure at competitive costs are essential as India rapidly integrates itself with the global economy. We see the improvement of our airports, railways, etc. I hope the additional capacities that would be created would be sufficient to ensure India's competitiveness in the global economy. Coming to Towards Long-Term Inclusive Growth, in keeping with the objective of inclusive growth in the Eleventh Five Year Plan, a major portion of the 2008-2009 Budget is allocated to the social sector. The 15% increase in the budget for health and 20% increase in the budget for education are particularly noteworthy. These increases in budgetary outlays and their cost-effective utilization will empower the poor to increase their capacities to participate in and benefit from the opportunities of growth. Clearly, the emphasis on broadening the access to opportunities through human capability enhancement will contribute to inclusive growth. The initiative on financial inclusion will improve access to credit for the disadvantaged. These initiatives are very important as they will not only contribute towards enhancing growth in the long-term but equally importantly broaden inclusiveness. In mainstreaming the bypassed and the marginalized, I was very happy with the emphasis put on development of the North East. First, the Bharat Nirman will be adequately funded including funding allocated to the NER. Second, budget allocation of the NER has been increased from Rs. 14,365 crores to Rs. 16,447 crores in 2008-09. Third, Rs. 40 crores have been allocated to the Special Tea Fund established for replication and rejuvenation. Further, a centenary grant of Rs. 20 crores has been made to the Toklai Experimental Station in Jorhat. Fifth, special allocation will be paid to the NER with the road development target being increased from 180 kilometres in 2007-08 to 300 kilometres in 2008-09. Lastly, Shivsagar has been selected for development of handloom as part of one of the six mega clusters being established. These initiatives for developing and mainstreaming the North Eastern Region with the nation's overall development process are highly laudable. The Budget allocations, if combined with sufficient attention to implementation and monitoring, could lead to tangible benefits in terms of both growth and

employment in the North Eastern Region. I have touched upon just a few of the major initiatives of the 2008-09 Budget of India. This is a sensible and practical Budget which addresses the major, short, medium and long-term challenges facing us. The Eleventh Plan which started with a robust growth of 8.7 per cent in 2007-2008 enters a challenging second year with price pressures emerging from both the domestic and external fronts. The 2008 Budget, just unfurled, is one step but an important step in facilitating inclusive growth in India. First, productive and decent employment opportunities must be created by sustained growth. Secondly, equal opportunities must be created for all, through a level-playing field. The emphasis on social sector is critical for capability enhancement. Thirdly, social protection must be provided to the very needy who cannot participate in the labour markets for reasons for which they are not responsible. In the end, I would like say that a Fifteen Point-Programme is given by our Prime Minister. For that, I think, from the Budget, the minorities may not get the benefit. So, I request the hon. Finance Minister that minority component Plan, a separate Plan, should be constituted so that from the Budget the minorities can get benefit. Finally, I fervently hope that the hon. Finance Minister's belief that the best is yet to come for India is borne out in future. So, I thank heartily the hon. Finance Minister, under the guidance of our hon. Prime Minister and our Chairperson, Shrimati Soniaji He has given an excellent Budget which will surely improve the development of India.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, केन्द्र की सरकार यंह बजट पेश करके, केन्द्र की सरकार और विशेषकर कांग्रेस पार्टी तथा उसके अन्य साझीदार बहुत प्रसन्न हैं। वे लोग काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लेकिन बजट आने के बाद से ही जिस तरीके से जीवन के लिए जरूरी चीज़ों के दाम छलांग मारने लगे हैं और महंगाई दर 5.02 प्रतिशत तक गयी है, दामों की बढ़ोत्तरी का स्तर यहां तक बढ़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि दाम भी किन चीजों के बढ़े – आटा के, दाल के, चीनी के, खाद्य तेल के, रसोई गैस के, मसालों के और चाय आदि के। महोदय, बजट के आने से पहले ही केन्द्र की सरकार ने डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आज ही समाचार पत्रों में छपा है कि केवल कंज्यूमर गुड्स या आदमी की जरूरत की जरूरी चीजों के ही दाम नहीं बढ़े, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में भी जबर्दस्त गिरावट आयी है। बिजली के उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा गिरावट आ गयी है, कोयले के उत्पादन में गिरावट आ गयी, केपिटल गुड्स के उत्पादन में गिरावट आ गयी। जो कंज्यूमर डयूरेबल्स हैं, उनके उत्पादन में गिरावट आ गयी। यह अजीब बात लगती है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, अगर हमें बजट पर चर्चा करनी है, तो यह देखना होगा कि क्या उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यह बजट सक्षम होगा, काफी होगा। इस प्रकार दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं–बढ़ती हुई महंगाई, चीजों के बढ़ते हुए दाम और दूसरी चुनौती हमारे सामने यह है कि गरीबी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन सबको दृष्टि में रखकर अगर हम बजट के प्रावधानों पर नजर डालें, तो यह साफ नजर आता है। कहा तो यह जाता है कि यह आम आदमी का बजट है, लेकिन यह बजट केवल कॉरपोरेट सेक्टर का है, तीस करोड़ के करीब जो मध्यम वर्ग है, उनका है और जो सटोरिए हैं, ब्लैक मार्किट करने वाले हैं, उनके हित की ज्यादा चिंता की गयी है और विदेशी पूंजीधारकों की चिंता की गयी है। यह बजट उनके लिए है, आम आदमी के लिए बजट नहीं है।

उपसभापति जी, इसमें वर्ष 2008-09 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत रखा, जबकि एफआरबीएमए में तीन प्रतिशत तक की सीमा है, परन्तु उससे भी 0.5 प्रतिशत कम है और वहीं पर जो हमारा राजस्व घाटा है, वह आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी का एक प्रतिशत रखा गया है, जबकि वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था, यह घोषणा की थी कि हम इसको जीरो परसेंट पर लायेंगे। परन्तु इसकी भी सही तस्वीर बजट में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसमें तेल, खाद्य आदि के दाम बढ़े हैं या उस पर जो हमें देना है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बजट में छठे वेतन आयोग के खर्चे का भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि यह घाटा और बढ़ेगा। ऐसा वित्त मंत्री जी ने जानबूझकर किया है जिससे कि हमें घाटा दिखाई न पड़े, इसमें ट्रांसपरेंसी भी नहीं रखी गयी और इसमें आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गयी है।

सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि इन्होंने जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उस कॉरपोरेट सेक्टर को कॉरपोरेट टैक्स, आयकर, आयात शुल्क, उत्पाद कर में छूट और रियायत आदि के जरिए वर्ष 2006-07 में दो लाख 39 हजार 712 करोड़ रुपया और वर्ष 2007-08 में दो लाख 78 हजार 644 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया है। और अगर इसमें सबसिडी जोड़ दी जाये, और भी रियायतें इसमें जोड़ दी जायें, तो यह और भी लंबा हो जाता है, यह बात वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार की है। आप एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर को लगातार छूट देते जा रहे हैं और अभी आपने मध्यम वर्ग के तमाम लोगों को छूट दी है, उससे जो हमारा कृषि क्षेत्र है, जो हमारा सबसे कमजोर तबका है, जिसको आप vulnerable section कहते हैं, जिसके बारे में अर्जुन सेन गुप्ता जी की भी रिपोर्ट है। जिसके बारे में अभी लेटेस्ट यूएनओ की वेल्थ कमेटी की रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि 78 करोड़ की औसत आमदनी 18 रुपए प्रतिदिन है। अभी यूएनओ की एक ताजा रिपोर्ट है, जिसमें 15 करोड़ लोग 12 रुपए से कम पाते हैं। माननीय श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त ने भी 76 या 77 प्रतिशत आबादी की आमदनी 20 रुपए से कम बताई है। इस वर्ग में गरीब आदमी आता है, खेतिहर मजदूर आता है। सामाजिक क्षेत्र में भी जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं। इनकी आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। इनके बारे में कोई सोच नहीं है। इस बजट में भी जो प्रावधान है और जो दिशा-निर्देश है, वह इसी बात को मानकर चलता है कि जो खाता-पीता वर्ग है और जो औद्योगिक घराने हैं, उन्हीं को ज्यादा छूट दी जाए, उन्हीं को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो बाजार में चमक है, यह चमक बनी रहे।

मान्यवर, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने संविधान में समाजवादी राज्य की स्थापना की कल्पना की थी। दुनिया में सौ, डेढ़ सौ साल से ज्यादा संघर्ष हुआ, मुसलसल लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद एक वैलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की कल्पना हुई। परन्तु आज न तो समाजवाद की कोई चर्चा है और न ही कल्याणकारी राज्य की कल्पना की चर्चा है। अब एक नया शब्द गढ़ दिया, जिसको इंक्लूजिव ग्रोथ कहते हैं। ये इंक्लूजिव ग्रोथ क्या है, यह शब्द किसका गढ़ा हुआ है? यह जो आज का पूंजीवाद है, यह बराबर नए-नए शब्द गढ़ता जाता है। हमें याद है, पहले इस अर्थव्यवस्था को trickle down theory माना गया। अगर जैसे-जैसे बड़े लोगों, सम्पन्न लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो उसकी जूठन या जो टपकेगा, उसकी टपकन लोगों तक पहुंचेगी। आज यह कहा जा रहा है कि अगर हमारी सम्पन्नता बढ़ती है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, तो उस ग्रोथ से सबकी ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री जी ने जो अपने भाषण में इंक्लूजिव ग्रोथ के बारे में जो कहा है या जो उसका अर्थ समझाया है, वह यह है कि एग्रिक्लचरल क्रेडिट को डबल कर दिया गया, 2 लाख 40 हजार करोड़, मार्च, 2008 तक, फिर नेशनल रूरल एम्पलॉइमेंट गारंटी स्कीम के तहत, मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन और फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उन्होंने इंक्लूजिव ग्रोथ के ये लक्षण बताए कि हम इन दिशाओं में काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल बकवास बात है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आम आदमी को, जब तक गरीब आदमी को काम नहीं मिलेगा- हमने राइट टू वर्क पास कर दिया, परन्तु आपने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में जो पैसा आवंटित किया है और उसमें 100 दिन के काम की गारंटी है, उसका जिस तरीके से कार्यान्वयन हो रहा हे, उसके बारे में भी CAG की भी रिपोर्ट है, तमाम प्रकार की उसकी सूचनाएं हैं। उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें अफसरशाही का बोल-बाला है। अब तो उसको पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। 2007-08 में 12 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 16 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। यह GDP का 0.3 फीसदी है। इसमें एक चालाकी की गई है, सम्पूर्ण रोजगार योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 3 हजार 4 सौ 20 करोड़ रुपया था। उसे खत्म करके इसी में शामिल कर लिया गया। यह केवल 600 करोड़ रुपए का ही इजाफा हुआ। इस नेशनल गारंटी स्कीम से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक कर्ज की बात है, हम कर्ज का विरोध नहीं करते हैं, परन्तु कर्ज माफी की जो बात कही गई, कर्ज माफी का जो समय चुना गया, अगर यह कर्ज माफी की घोषणा पहले की गई होती तो शायद इतनी आत्महत्याएं नहीं होतीं। नम्बर दो, इसमें सिंचित और असिंचित जमीन का फर्क नहीं किया गया। नम्बर तीन, इस योजना से सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को हुआ है, परन्तु शेष क्षेत्र के लोगों को नहीं हुआ है। जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 65 फीसदी कर्ज साहूकारों या निजी क्षेत्र से लिया गया है। इसमें केवल कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक के कर्ज को माफ करने की बात कही गई है। मैं यह चाहता हूं कि अगर कर्ज माफ करना है और किसानों की समस्याओं का निदान ढूंढना है तो उसकी एक निश्चित योजना होनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ खेती में जो इन्वेस्टमेंट है, खेती में पूंजी निवेश निरन्तर घट रहा है। उसका नतीजा यह है कि आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, सर्विसेज सेक्टर हैं। इनमें जितना इन्वेस्टमेंट है, उसका केवल एक प्रतिशत खेती में पूंजी निवेश हो रहा है। अगर प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का हिसाब लगाए तो खेती में जो इन्वेस्टमेंट है, वह एक रुपया है, जबकि मॉडर्न इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में एक हजार है। एक और एक हजार में फर्क होता है। इसकी इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण आज जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनमें हताशा है, उनमें आक्रोश है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विषमता है, कृषि और गैर कृषि में विषमता है, विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में विषमता है, इसी कारण यहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। हमारी जो अर्थ नीति है, जो अर्थव्यवस्था है, यह विस्तारवादी नहीं है, यह सिकुड़नवादी है। आप देखिए कि पूरे बजट भाषण में भ्रष्टाचार की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने जो अनुमान लगाया है, इस अनुमान को आप 8.6 प्रतिशत का ग्रोथ रेट कहते हैं। The real growth rate would be 8.6 per cent and inflation would be 4.4 per cent.

श्री उपसभापति: तिवारी जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री ब्रजभूषण तिवारी: बस, मैं एक सैकिण्ड में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जिस प्रकार की स्थिति है, उससे यह साफ हो रहा है जिस अनुमान के आधार पर यह बजट है, यह बजट अनुमान सफल नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है, जिसकी आहट और आधार मिला है, उससे लगता है कि हम इस ग्रोथ को मेन्टेन और सस्टेन नहीं कर पाएंगे और देश एक बहुत भारी आर्थिक संकट में फंसने वाला है। इसलिए मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपनी अर्थ नीति में बदलाव लाएं और देश के अंदर जो कृषि है, बेरोजगार नौजवान हैं, यहां का जो गरीब तबका है, उसके हित, साधन, उत्पादन में साझीदार बनाने की योजना चलानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इस बजट का विरोध करते हुए मै अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, we are discussing the annual Budget of this year, which deals with the problems of more than 100 million people. This country has great expectations from this Government this year since we are facing an acute crisis in agriculture as well as a hike in the prices of essential commodities. Sir, the poor people are becoming the victims of this situation. Ours is an agrarian country where still 65 per cent people earn their livelihood by means of agriculture. We are facing a deep crisis. On the one side, suicides by the farmers and deaths of the poor people are being reported; on the other side, we are facing a fall in the production and productivity. Sir, naturally, this Budget should address both these questions, but unfortunately, only one issue has been addressed, that is, the debt trap in which our farmers have fallen. Sir, every year, millions of farmers in this country are losing their farming land. That is the problem. Because of the hike in the investment in agriculture, the poor farmer is not in a position to make that much of investment. Every year, agriculture is proving to be a loss- making business for small farmers. So, naturally, they have to go in for loans. Whatever price he is getting for the produce is lesser than his expectation. Naturally, after four or five years of failure in agriculture, he is forced to sell off his land and thus, becomes a landless farmer. That is why the number of agricultural workers is increasing and migration is also increasing. This issue has to be addressed properly. In this Budget, only one part has been addressed, that is, the debt relief. I welcome this. But the other part still remains to be addressed. Sir, the allocation for agriculture should be enhanced. Other infrastructure should also be made available. Whatever is already there is not sufficient. Unless we improve the quality of agriculture by improving the productivity, we will not be in a position to address this problem. Sir, the Budget has, unfortunately, failed to address this very important question. And, while we are failing in addressing this issue, we will fail in two areas. Sir, for the first time in this country, we are facing the problem of price hike of the essential commodities because of the failure of production of foodgrains. Sir, for the first time, we don't have sufficient paddy, we don't have sufficient wheat, and we don't have sufficient cereals. So, in such a situation, the Government has to enhance its investment in

this sector. Sir, when the country is facing the problem of price rise, what should be the approach of the Central Government? I would like to say that the Central Government should adopt an approach of market intervention. We are anticipating such a thing. We are always talking about the Centre-State sharing on some of these issues. With regard to price rise, I would say that we have had a similar experience in our State. We are also facing this problem of increase in foodgrain-prices there. Now, Sir, what was the approach of the State Government? In order to tackle this problem, the State Government tried to strengthen the Public Distribution System and the cooperative system to provide foodgrains to the poor people at a lower price. So, that kind of intervention is needed. The State Government directed the consumer cooperative organization to purchase rice from Andhra Pradesh at a higher price and sell it at a lower price inside the now we are facing acute shortage of foodgrains in the country. Sir, we always make a comparison between India and China. In China, the net sown area for agriculture is lesser than that of India. But with regard to production of major crops, the position in this. With regard to paddy, China's contribution is 29.8 per cent whereas our country's contribution is 21.1 per cent. With regard to maize, India's contribution is only 1.9 per cent; China's contribution is 18 per cent. With regard to wheat, China's contribution is 14.5 per cent; India's contribution is only 11.4 per cent. Then, as for cereals, China's contribution is 17.9 per cent, and India's contribution is 10.6 per cent. What does this show, Sir? This shows lack of productivity in this country. The lack of productivity is because of lack of investment in agriculture in the country. Unfortunately, that aspect is not properly addressed to even in this Budget. Only one aspect has been covered. How can we improve the production and productivity of agriculture in this country? How do we help the poor peasants living in rural areas of this country? It can be done through a proper programme which would give him access to modern equipments so that he could be in a position to use a high-yielding variety of seeds and new hybrids of different crops. Other than this, more money for agricultural research should be allocated.

State and, Sir, the State Government had borne whatever was the difference in price. That is the approach adopted by the State Government of Kerala to tackle this crisis of foodgrains. A similar kind of approach should be adopted by the Central Government. The Central Government has to help the State Government. A share in this kind of expenses should come from the side of the Central Government. If the State Government is prepared to intervene in the market in order to stop this crisis of rise in the prices of essential commodities, the Central Government should share the burden. That approach is lacking in this Budget. That is the problem. So, naturally, the consumers won't be helped by this kind of approach in the Budget. Unfortunately, on this point of price-rise of essential commodities. I would like to criticise the Government. The approach to help the poor man is not there in this Budget. In order to help the consumer in a period of rising prices, the kind of approach which needs to be adopted by the Government is not there in the Budget. So, that is a deficiency which we have seen in the Budget. Sir, what is the reason for this? The public investment is coming down. That is the problem. In agricultural sector, it is coming down. In irrigation, it is coming down. In electricity, it is coming down. In that way, the public investment is coming down. Sir, even now, twenty-four per cent of the GDP is coming from the public sector. Only one public sector company, the oil company, is giving more than Rupees one lakh crores as tax to the Central Government. From where does the major part of the tax is coming? Sir, it is coming from our public sector. Your oil companies are giving it. The hon. Finance Minister has told that this time, the full revenue income was there. It means, his expectation was fulfilled. From where is it coming? It is coming from the public

sector. Every day, we are reading in the newspapers, in the magazines, that, in India, the number of rich persons is increasing. Their number is increasing in the Forbes Book. Their profit is increasing. Sir, their profit is increasing, but their share in the revenue is not increasing to the extent their profit has increased. Their share and money has increased substantially. Is it balancing? If you go through the approach that is adopted in this Budget, we are differing with the Government. You are not ready to touch the rich people who are making the maximum profit during this period. They are making maximum profits. Why are you afraid of touching them? This country owes an answer from the Government. The poor man is in distress. Farmers are committing suicide. There is a hike in the prices of essential commodities. The country is facing acute crisis and the Government is not ready to touch the rich section that is making the maximum profit because of the policies being pursued in this country. Why are you wary of the rich? You owe an answer to this country. Why are you wary of the richer section in the society? This is a very serious issue. It is very alarming.

As regards investment, we are now reaching a situation where public investment is steadily declining and the private sector is making investment in profit-making areas. Sir, it was only during the quarter from September, 1999 to December, 2000 that such a situation occurred in India. Now that situation has arisen again. Since September, 1999, outstanding private investments have been lower than Government investment in this country. In that quarter of 1999, the situation was different. Sir, the difference between private and Government investment has grown from 14 per cent in the quarter ended December, 2006 to 28 per cent in the quarter ended March, 2007. In the quarter ending March, private ownership of outstanding investments exceeded Government ownership of Rs. 3,74,045 crores. This is mainly due to the boom in construction, electricity, mining and services, where maximum profit could be got. Here, the private sector, which increased its investment by 335 per cent in construction, got the maximum profit. It is a booming industry in the country. Private sector investment was increased by 335 per cent, in electricity, by 119 per cent, in mining and services sectors, by 112 and 78 per cent respectively, whereas the Government investment growth in mining, irrigation and service sector showed signs of slowing down. Growth in mining investment fell to 30 per cent in 2006-07 from 81 per cent in 2005-06. Similarly, in services, the growth fell from Rs. 44,200 crores in 2006-07. Here it is an increase of only 9 per cent whereas in the previous period, investment was Rs. 1,26,119 crores, which was an increase of 33 per cent. This is the position. Every year, this public investment is coming down. This is going to create a big problem in our country. It would have an adverse affect. Are you mindul about the future of this nation? What is the experience of the public sector? There may be limitations but what is the income which we are getting? Are you mindful of the future of this country? We want more investment in irrigation, health and education. From where will you get the resources? The resources are coming from taxes. This Government is unfortunately neglecting this important area of public investment.

Then, Sir, I would like to say that there is more emphasis on NGO's and less emphasis on local self-government. You must provide more help to the local self-government. You must promote it. What is the approach of the Government with regard to self-help groups? Would you like to promote the self-help groups through local self-governments or through NGOs? What is the history of NGOs in this country? We know from experience that most of them are corrupt. At least, the local self-Government is accountable to the people. That should be encouraged. Unfortunately, the approach of the Finance Ministry with regard to the self-help groups is totally against the local self-Government. They are going to destroy the system. We have our bitter experience in Kerala. Now, we are very much anguished

about the approach of the Government. They are promoting only the NGOs in the States. This approach should be stopped and you have to strengthen the self-help groups.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: The self-help groups should be separated from the NGOs as early as possible. That is the decision of the Government.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: But, Sir, I have seen that recently, the hon. Finance Minister has gone and inaugurated one such programme. That is why, I am expressing my concern.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: As soon as possible, self-help groups will be separated from NGOs.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, the concern is there because in Kerala, we have best experience of the self-help groups in the rural areas. Now, it is going to be adversely affected.

Similarly, there are two-three problems related to my State. Hon. Minister, Shri Vayalar Ravi, who is sitting very near to me, is in the charge of the Ministry of Overseas Indian Affairs. One problem is related to five million workers from my State who are working in the Gulf Region. They are all poor people. It is not possible for us to provide employment to these five million people. They are working very hard. They are sending crores of rupees, foreign currency, in this country. It is the strength of this country. Whenever this country needs some extra money, if you come with a bond ....*(Interruptions)*.... Yes, 18 billion is the amount of their annual contribution which the hon. Minister, Shri Vayalar Ravi, has told me. So, if we compare their contribution with the kind of security that we are providing to them, it is nothing. We were anticipating a safety mechanism for them, some investment scheme for the Gulf returnees. It was a request from our side. Unfortunately, that has not been done in the Budget. It is a very serious lacuna, a failure in the Budget. When we met the hon. Finance Minister for pre-Budget discussion, I had an opportunity to raise this matter. I had a hope that this issue would be addressed. Unfortunately, the problems related to the NRIs in the Gulf Region, especially the workers who are there, and the Gulf returnees have not been addressed in the Budget. At least, while the Minister answers this debate, I am anticipating that some announcement will come from him which would help to resolve some of these issues of Gulf returnees who are working in that region.

Similarly, with regard to the assistance to the States, my humble request is that most of the assistance is through projects. The difficulty in projects is that in a country like India, for States, it is very difficult to implement the programmes. Naturally, the aid to the states should be through grants. If aid is given only through Centrally-sponsored programmes, it creates problems for the States. So, more grants should be given to the States. The allocation for the States should be enhanced. That approach should be there. Even now, in the service sector, the State Governments are not in a position to levy taxes. That is an issue which we are discussing. While discussing this Budget, my suggestion is that this approach of the Government will help in solving some of the financial crisis being faced by the States. So, the Government has to look into this matter also in order to help the State Governments.

I have one more request in view of the assurance by the Finance Minister that they are going to start some IITs. Our Chief Minister had approached and met hon. Prime Minister and given a representation also in order to start an IIT in Kerala. My humble request, while concluding my speech, to the hon. Finance Minister is to start an IIT in Kerala and implement

the assurance given by hon. Prime Minister. One IIT should be started in the State of Kerala because it has highest literacy rate in the country. It is a long-standing demand. The best human resource in the country comes from Kerala which goes all over the world. At least, for them, this minimum thing should be done from the Central Government. I hope this would be considered seriously by the hon. Finance Minister.

श्री बलवारी लाल कंवल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, बजट प्रस्ताव, जो माननीय चिदम्बरम साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उसकी प्रशंसा और आलोचना, दोनों, करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं।

महोदय, कृषि क्षेत्र में जहां 60 करोड़ लगे हुए हैं, वहीं पर 40 करोड़ छोटे व्यापारी, जो हमारे ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, लगे हुए हैं। मुझे बड़ा खेद है, उपसभापति महोदय, हमारे किसी भी वक्ता ने उन 40 करोड़ व्यापारियों के दुख-दर्द के बारे में एक भी विचार रखने का कष्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, वह व्यापारियों को अपना विरोधी मानती है, अपना दुश्मन मानती है। चार बजट मैंने पढ़े हैं, एक किताब अभी वर्तमान सरकार की आई है, जिसमें 196 योजनाएं प्रकाशित की गई हैं, मैं ढूंढता रह गया कि क्या व्यापारियों के बारे में कहीं कोई योजना है। 40 करोड़ लोग सरकार से एक भी सुविधा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, कोई जमीन नहीं मांगते, कोई जायदाद नहीं मांगते और इसके बावजूद 40 करोड़ छोटे व्यापारियों के बारे में, इतने मोटे बजट में, एक लाइन, एक शब्द न लिखना, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात, इससे बड़े दुख की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चिदम्बरम साहब बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा बजट पेश करते हैं, परन्तु उन्होंने व्यापारियों के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। बीमे की तमाम योजनाएं, 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया आपने बीमा के लिए दिया है, दिया जाना चाहिए, सकल बीमा किया जाना चाहिए, अधिकारियों का बीमा किया जाना चाहिए, टीचर्स का बीमा किया जाना चाहिए, परन्तु जो व्यापारी ऑनरेरी टैक्स कलैक्टर हैं और जो टैक्स कलैक्टर का बीमा कराते हैं, डी.एम. का बीमा कराते हैं, तहसीलदार का बीमा कराते हैं, तो क्या उस ऑनरेरी टैक्स कलैक्टर को बीमा नहीं कराना चाहिए। जो व्यापारी टैक्स पेअर हैं, PAN Card Holder हैं, क्या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कनाडा जाकर देखिए, वहां जो PAN Card Holder है, उसको मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई मिलती है। इंजीनियरिंग पढ़ाना हो, चाहे मेडिकल पढ़ाना हो, चाहे कोई शिक्षा देनी हो, कोई लड़का अगर अपने बाप का PAN Card लेकर जाएगा, तो उसको निःशुल्क पढ़ाई मिलती है, चाहे वह कितनी भी ऊंची से ऊंची हो। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में, मैं दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इधर की पार्टी की सरकार रही हो, चाहे उधर की पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी आज तक व्यापारी का दुर्घटना बीमा कराने के बारे में, आग लग जाती है, दुकान जल जाती है वह सड़क पर आ जाता है-किसी ने नहीं सोचा। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब हमने व्यापारियों की बात उनके सामने रखी तो उन्होंने 6 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सेल्स टैक्स विभाग की तरफ से और लेबर क्लास विभाग की तरफ से कराया। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर 40 करोड़ व्यापारियों के दुख-दर्द की आपको जरा सी भी चिंता है तो उनका बीमा भी कराइए। कितना लगेगा? हमने तो पत्र भेजा था चिदम्बरम साहब को, हम उनसे मिलकर आए। 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए में सारे टैक्स पेअर व्यापारियों का बीमा हो जाएगा। केवल टैक्स पेअर व्यापारियों के बीमे की बात हो रही है, आप क्यों नहीं सोचते?

सर, यह जो कारपोरेट रिटेल आ रहा है, इस बारे में हमने पूरे देश का दौरा किया। मैं खुद गया, व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते और हमने सैंकड़ों, जो तमाम कारपोरेट रिटेल के शॉपिंग मॉल्स हैं, हमने उनका दौरा किया और हमने उनसे तफ्तीश की तो हमें पता लगा कि एक लाख रुपए की बिक्री पर केवल दस लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि कारपोरेट सैक्टर रोजगार दे रहा है, रोजगार दे रहा है, रोजगार दे रहा है और हमारा व्यापारी, जो परम्परागत व्यापारी है, वह एक लाख रुपए की बिक्री पर 100 लोगों को रोजगार दे रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि इस बजट में कारपोरेट रिटेल पर लगाम लगाने के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। ग्रोथ का हल्ला मचाया जा रहा है कि ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। ग्रोथ तो बढ़ रही है, पर ग्रोथ बेरोजगारी की भी बढ़ रही है ग्रोथ बेकारी की भी बढ़ रही है, ग्रोथ भुखमरी की भी बढ़ रही है ग्रोथ आत्महत्याओं की भी बढ़ रही है और अगर ग्रोथ आत्महत्याओं की बढ़ रही है तथा कारपोरेट रिटेल के आने से अगर छोटा व्यापारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा और उसके लिए बजट में एक शब्द

भी नहीं लिखा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि यह निरर्थक बजट है और 40 करोड़ छोटे व्यापारियों की आशाओं पर तुषारापात करने वाला बजट है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि व्यापारियों का दुर्घटना बीमा कराया जाए, व्यापारियों का अग्नि बीमा कराया जाए... । जो व्यापारी इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए इस बजट में मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई का प्रावधान किया जाए और जब चिदम्बरम साहब चर्चा करेंगे तो उसमें जरूर व्यवस्था करेंगे। उपसभापति महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। महंगाई की बात इतनी हुई, अभी मैं चिदम्बरम का मंदिर देखने गया था, चिदम्बरम साहब की Constituency में भी गया था और मुझे वहां इतना अफसोस हुआ, मैं रोटी खाता हूं, पूरी नहीं खाता हूं। जब मैं होटल में रोटी खाने के लिए गया, यहां देश की राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस में दो रुपए की रोटी मिलती है और वहां चिदम्बरम साहब के चिदम्बरम में बारह रुपए की रोटी मिलती है। इतनी महंगाई कि हिन्दुस्तान में बारह रुपए की रोटी बिकेगी। फिर आप ग्रोथ का हल्ला मचाएंगे कि हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है। गरीब लोगों को बारह रुपए की रोटी खिलाएंगे। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे केरल हो या चाहे तमिलनाडु हो, कम से कम होटलों में रोटी का रेट तो ठीक करा दीजिए। अगर दिल्ली में दो रुपए में रोटी मिलती है तो वहां भी दो रुपए में रोटी मिलनी चाहिए। मैं दो-तीन छोटे-सुझाव देना चाहूंगा। अभी टैक्स का रेट तीन स्लैब में किया है और आपने चालीस हजार की छूट बढ़ाई है। मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब बहुत साहसी व्यक्ति है, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Sir, the temple place is different from Mr. Chidambaram's constituency.

श्री बनवारी लाल कंछल: मैं चिदम्बरम जी की Constituency में भी गया था, वहां भी दो-तीन छोटे-छोटे temples हैं, मैं वहां भी देख कर आया हूं। वहां रोटी बारह रुपए की मिली। मैं अपने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की तारीफ भी करना चाहता हूं, पिछले कई वित्त मंत्री हमने देखे हैं, दस हजार रुपए की छूट बढ़ाने में उनको पसीना आ जाया करता था, परन्तु इन्होंने जो चालीस हजार रुपए की छूट बढ़ाई है, यह निश्चित ही बहुत साहस का काम है और मैं इसकी तारीफ भी करता हूं। यदि इन तीन स्लैबों में थोड़ा-सा सुधार कर दिया जाए तो उससे हमारा राजस्व भी बहुत बढ़ जाएगा और काला धन भी सफेद हो जाएगा, जैसे 150001 रुपए से तीन लाख तक दस प्रतिशत है, इसको बढ़ाकर पांच लाख कर दिया जाए। पांच लाख तक 10 परसेंट टैक्स, दस लाख तक 20 परसेंट टैक्स और दस लाख से ऊपर 30 परसेंट की दरें कर दी जाएं तो सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व मिलेगा। पहले 90 परसेंट राजस्व था, तो फिर घटाकर 30 परसेंट टैक्स किया तो कितना राजस्व मिलने लग गया। काला धन सफेद होगा और सरकार की विकास योजनाओं में बहुत पैसा मिलेगा। आपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख 95 हजार से बढ़ाकर दो लाख पच्चीस हजार किया। वरिष्ठ नागरिक पिछले दस सालों से मांग कर रहे हैं कि लालू यादव जी ने अपने रेल बजट में वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा साठ साल रखी है और चिदम्बरम साहब ने पैंसठ साल कर रखी है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा साठ साल कर दें तो वरिष्ठ नागरिकों को इसका बहुत सा लाभ मिल जाएगा। इससे रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आयु सीमा एक हो जाएगी और उसमें disparity नहीं रहेगी।

श्री उपसभापति: इससे ज्यादातर M.P. भी आ जाएंगे।

श्री बनवारी लाल कंछल: M.P. तो आ ही जाएंगे, परंतु बहुत सी जनता आ जाएगी। मेरा अनुरोध है कि इसको कर दें। बजट की धारा 163 में अधिभार समाप्त नहीं किया गया है। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत राजस्व आ रहा है। जब आपके टारगेट से ज्यादा राजस्व आ रहा है तो फिर आप दस परसेंट का अधिभार क्यों रख रहे हैं। अधिभार रखने का क्या औचित्य है? अधिभार तो इंदिरा जी ने बढ़ाया था, बांग्ला देश से जब युद्ध हुआ था, तब अधिभार बढ़ाया था। इस समय देश में कौन-सा संकट है कि आप अधिभार बढ़ा रहे हैं? मेरा अनुरोध है कि अधिभार को समाप्त किया जाना चाहिए। अधिभार की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट की धारा 181 में बैंकिंग लेन-देन का टैक्स समाप्त कर दिया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, बजट की धारा 183 में आपने वैट यानी केन्द्रीय बिक्री कर की दर को तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। व्यापारी यह मांग कर रहे हैं कि बीस साल पहले आपने एक कानून बनाया था कि एक दिन में बीस हजार से ज्यादा नकद लेन-देन कोई व्यापारी नहीं कर सकता है। यह कानून बीस साल पहले बनाया गया था। अब बीस हजार की कीमत कितनी रह गई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि नकद लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए तक कर दिया जाए। अगर आज कोई व्यापारी दिल्ली में चालीस हजार

का सामान खरीदने आता है, रात को उसका प्रोग्राम बना और वह ड्राफ्ट नहीं बनवा पाया, ऐसी परिस्थिति में वह चालीस हजार का सामान नकद नहीं खरीद सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बीस हजार की सीमा को एक लाख कर देने में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। केवल अधिकारी-इंस्पेक्टर राज बढ़ता है और पैसे का लेन-देन बढ़ता है, इसलिए इस सीमा को एक लाख रुपया कर दीजिए।

छोटे व्यापारियों के लिए ऑडिट सीमा आपने बीस साल पहले चालीस लाख निर्धारित की थी, अब चालीस लाख की क्या वैल्यू है? इसलिए इसको बढ़ाकर एक करोड़ किया जाना बहुत उचित होगा। इसी प्रकार से आपने राष्ट्रीय बचत योजना में, सैक्शन 80 सी में कोई बढ़ोतरी नही की है। महंगाई का इतना ज़ोर है, महंगाई घटाने के लिए हम सुझाव दे रहे हैं। बचत योजना 80 सी की राशि एक लाख से बढ़कार दो लाख कर दीजिए, जब आदमी बचत योजना में अपना एक लाख रुपया लगा देगा, तो उसकी एक लाख की परचेजिंग पावर घट जाएगी और परचेजिंग पावर घट जाने से चीज़ों के दाम कम होंगे और महंगाई पर अंकुश लगेगा। जब देश में और देश के प्रदेशों में बचत राशि बढ़ेगी, तो तमाम योजनाओं में आप अपना धन invest कर सकेंगे और उद्योगों का विकास कर सकेंगे और सरकार के राजस्व पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभव नहीं पड़ेगा।

महोदय, अब मैं पैन कार्ड पर आता हूं। पैन कार्ड में आपने बहुत सुधार किया है, इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपने विभाग की पूरी monitoring कर रखी है, पर जो दो रुपया income tax दे रहा है, उसके पास भी वही पैन कार्ड है, जो दो करोड़ रुपया income tax दे रहा है, उसके पास भी वही पैन कार्ड है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो व्यक्तिगत आय कर देने वाले हैं, उनके पैन कार्ड का रंग अलग होना चाहिए और जो कॉरपोरेट हैं, कंपनी के लोग हैं, उनके पैन कार्ड का रंग अलग होना चाहिए। पैन कार्ड में तीन श्रेणियां बनाइए - जो एक लाख रुपया वार्षिक टैक्स दे रहा है, उसको रजत पैन कार्ड दीजिए, जो पांच लाख रुपया या दस लाख रुपया वार्षिक टैक्स दे रहा है, उसको गोल्डन पैन कार्ड दीजिए और जो पच्चीस लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक कर दे रहा है, उसको प्लैटिनम पैन कार्ड दीजिए। अगर ये तीन श्रेणियां कर देंगे, तो लोगों में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि मैं रजत कार्ड बनवाऊंगा, मैं भी टैक्स ज्यादा दूंगा, मैं गोल्डन कार्ड बनवाऊंगा, मैं भी ज्यादा टैक्स दूंगा, इन तरीकों से ज्यादा टैक्स आएगा और जो आदमी अपनी जेब में गोल्डन पैन कार्ड लेकर चलेगा, उपसभापति महोदय, वह शान समझेगा कि मेरे पास गोल्डन कार्ड है, मैं गोल्डन कार्ड धारक हूं, मैं सिल्वर कार्ड धारक हूं, मैं प्लैटिनम कार्ड धारक हूं। अगर ये छोटे-छोटे सुझाव आप मान लेंगे, तो राजस्व तो आपको इतना मिल जाएगा कि रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मैं एकाध छोटे-छोटे सुझाव और दूंगा।

उपसभापति महोदय, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो आप उसे शाबासी देते हैं, आप उसको prize देते हैं, परंतु हमारे यहां क्या हो रहा है? आय कर विभाग में उलटी गंगा बह रही है। अगर किसी व्यापारी की सेल ज्यादा हो गई और किसी व्यापारी ने पिछले साल से ज्यादा income tax pay किया, तो दंड के रूप में उसका खाता scrutiny में खोल दिया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। अधिकारी पचास बार उसके दफ्तर में अपने जूते घिसवा ले, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो आदमी पिछले साल से ज्यादा income tax दे रहा है, उसको तो prize देना चाहिए, उसको तो इनाम मिलना चाहिए, इसलिए यह जो scrutiny की गंदी व्यवस्था है कि जो सेल बढ़ाते हैं, जो income tax ज्यादा देते हैं, उसका scrutiny में आप लाएंगे, अधिकारियों के दरवाज़े पर उसकी नाक रगड़वाएंगे, उसके जूते घिसवाएंगे, ऐसा गलत काम कम से कम आयकर विभाग में नहीं होना चाहिए। मैं अपने विद्वान वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिसकी सेल बढ़े, जिसकी आय बढ़े, उसको बुलाकर उसकी पीठ ठोंक दीजिए, उसको बुलाकर एक शॉल present करवा दीजिए, एक memento भेंट करवा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम प्लीज़, उसका scrutiny में खाता मत खोलिए।

श्री उपसभापति: शायद यह तो वे कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल कंछल: नहीं किया है, वे नहीं कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, वे award दे रहे हैं - Best Taxpayer Award.

श्री बनवारी लाल कंछल: नहीं, नहीं, वह तो दे रहे हैं, पर पिछले साल से इस साल किसी ने ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो उसको दंडित कर रहे हैं।

महोदय, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ। अभी scrutiny में अधिकारियों की बहुत लाल-फीताशाही है जिसके मन में आता है, दफ्तर से फोन आता है - कंछल साहब, आपकी फाइल scrutiny में आ रही है, अधिकारी से आकर मिल लीजिए। क्यों अधिकारी से मिलवाते हैं? अधिकारी से मिलने का मतलब है एक लाख रुपए देना। अधिकारी से मिलने का मतलब पचास हज़ार रुपया देना। अधिकारी से क्यों मिलवा रहे हैं आप? इसलिए एक नियम बना दीजिए? मंत्री जी, आप एक नियम बना दीजिए कि जो पिछले साल से पंद्रह परसेंट राजस्व बढ़ाकर दे, उसका खाता scrutiny में नहीं आना चाहिए। जो कम टैक्स ...(व्यवधान)...

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Please send the name of officers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How, can he?

श्री बनवारी लाल कंछल: नाम दे देंगे, तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि नाम दे दीजिए, तो नुकसान हमारा ही होगा। खरबूजे पर चाकू इधर से गिरे या उधर से गिरे। आप उस अधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे हमारा ही। वह कहेगा - अच्छा, तुमने मंत्री जी को नाम दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कितने बड़े एम.पी. हो, अब मैं तुम्हें ठीक करता हूं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक नियम बनाइए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्व बढ़ाने के हित की बात कर रहा हूं। अगर व्यापारी पिछले साल से 15 परसेंट राजस्व बढ़ाकर दे रहा है तो आप कानून बना दीजिए कि जब तक वह उसे बढ़ाकर देता रहेगा, उसका खाता scrutiny में नहीं आएगा। बढ़ाने वालों को हतोत्साहित मत कीजिए। जब आप उन्हें हतोत्साहित कर देते हैं, तभी आदमी नम्बर-दो के खाते रखता है। नम्बर-दो के खातो को बंद करने की व्यवस्था कर नम्बर-एक के खातों को संचालित करने की व्यवस्था कीजिए। अगर इनकम टैक्स के कानूनों में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत लाभ होगा।

महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों के मसीहा मुलायम सिंह जी ने बार-बार यह कहा है कि जब तक किसानों को फसल का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। अभी तो आपने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। यह जो ऋण माफी है, यह बेहोशी का इंजेक्शन है। ऑपरेशन करना है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, उसके बाद चाहे जहां से बदन काट लो, पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने केवल तीस परसेंट या चालीस परसेंट ऋण बैंकों से लिया हुआ है, बाकी साठ-परसेंट ऋण दूसरे बैंको यानी साहूकारों से ले रखा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदते हो, आप बाहर से दलहन खरीदते हो, जो दाम आप आस्ट्रेलिया को दे सकते हैं, वही दाम हिन्दुस्तान के किसानों को मिलना चाहिए। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, उनके घरों में खुशहाली आ जाएगी। केवल ऋण माफी करने से किसानों के घरों में खुशहाली नहीं हो सकती। मैं तो मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, यूएनपीए को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चार दिन तक उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, इसलिए मजबूर होकर माननीय चिदम्बरम जी ने ऋण माफी की है। चलिए, इसके बावजूद भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऋण माफी की है। किंतु आप कल एक घोषणा और कर दीजिए कि किसानों को फसल का वही मूल्य दिया जाएगा, तो मूल्य हम आस्ट्रेलिया को गेहूं का दे रहे हैं। इसी प्रकार दलहन मंगाने पर विदेशों को जो दलहन का मूल्य दे रहे हैं, वही हम भारत के किसानों को देंगे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में आपकी जय-जयकार होगी। अंत में, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप व्यापारियों को अपना दुश्मन मत मानिए, व्यापारियों को अपना दोस्त मानिए और उनके लिए भी बजट में कुछ जरूर करवा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद कंछल जी। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, I have to inform you that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is, the 13th March, 2008, has allotted time for the Government Legislative and other Business as follows: